हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

09 मार्च, 2021 (द्वितीय बैठक)

खण्ड–1, अंक–4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 09 मार्च, 2021

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 09 मार्च, 2021

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में मध्याह्न पश्चात् 02:35 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ होगी।

श्री विनोद भ्याना (हांसी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चहुमुंखी विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं। आज प्रदेश में हर क्षेत्र में चाहे वह सड़कें बनाने की बात हो, शिक्षा देने की बात हो, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की बात हो अभूतपूर्व विकास कार्य किये हैं। अब मैं एक–एक बात का जिक्र करूंगा, जिसमें सबसे पहले सड़कों के बारे में बताना चाहूंगा। जब मैं वर्ष 2009 से लेकर 20014 तक विधायक था और मैं यह बात सही मायने में और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि उस समय मुझे हांसी से चण्डीगढ़ आने में चार–साढ़े चार घंटे का समय लगता था, परन्तु अब हांसी से चण्डीगढ़ आने में मात्र तीन घंटे का समय लगता है। इसी तरह से मैं शिक्षा की बात करूं तो हमारी सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज बनाकर शिक्षा के प्रति अपनी सोच दिखायी है कि हमारी सरकार शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है ? अगर मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं तो हर जिले में मैडिकल कॉलेज खोलना एक बहुत बड़ी सोच होती है। यह आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रति बहुत बड़ी सोच दर्शाता है। मैं समझता हूं कि कोविड–19 के समय में भी सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किये हैं। फिर चाहे हम हमारे सफाई कर्मचारियों की बात करें, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात करें या समाजसेवी संस्थाओं की बात करें। इन सभी ने सरकार के साथ मिलकर हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किये हैं। मैं आज इन सब कार्यों के लिए आरदणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को सलाम करता हूं और उनके द्वारा किये गये विकास कार्यों के लिए भी सलाम करता हूं। आज पूरे देश, प्रदेश और इस सदन में भी किसानों का मुद्दा बहुत जोर–शोर से उठाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ हमेशा राजनीति होती रही है। पिछली सरकारों द्वारा किसानों का हमेशा मजाक बनाया जाता रहा है। फिर चाहे वह एस. वाई.एल. नहर का मामला हो, चाहे हांसी बुटाना नहर का मामला हो या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का मामला हो। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने ही नहीं

बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले जिनकी पार्टी का राज इस प्रदेश में रहा है, उन्होंने हमेशा किसानों का फायदा उठाया है। किसानों के नाम से राजनीति की है, परन्तु किसानों की भलाई करने के लिए किसी ने सोचने की हिम्मत नहीं की। आज इनके द्वारा किसानों को फिर से बरगलाया जा रहा है। सौभाग्य से इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी सोच यह है कि इस देश को संसार में एक नम्बर पर लेकर जाएंगे। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में बहुत बढ़िया–बढ़िया कानून बनाएं हैं। ऐसे कानून बनाएं हैं जिनका यह देश पिछले 70 सालों से इन्तजार कर रहा था। पिछले 70 सालों से देश का नागरिक यह सोच रहा था कि यह धारा 370 कैसे खत्म हो ? माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 को खत्म कर दिया। पहले हमारे देश की मुस्लिम बहनों के साथ तीन तलाक के नाम पर अत्याचार होते थे। इस तरह से कई ऐसे कानून बनाए हैं, जिससे देश का हर नागरिक बड़ा संतुष्ट हुआ है। (विघ्न)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही चर्चा करनी चाहिए।

श्री विनोद भ्यानाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं उसी पर ही बोल रहा हूं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही चर्चा करनी चाहिए।

श्री विनोद भ्याना : अध्यक्ष महोदय, आज फिर किसानों के साथ राजनीति हो रही है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किसानों की आय दुगुनी करने के लिए तीन कृषि कानून बनाये हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन कृषि कानूनों को काला कानून बता रही है परन्तु अफसोस की बात यह है कि ये लोग अभी तक काले कानून की परिभाषा नहीं समझा पा रहे हैं। ये एक ही बात कहते हैं कि अगर कृषि कानून में कुछ गलत नहीं है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? मैं इनको इस बात का जवाब देता हूं कि आज किसान विपक्ष के लोगों के बरगलाये में आया हुआ है और इनके बरगलाने के कारण से आज किसान दिल्ली के बॉर्डर्ज पर धरने पर बैठे हुए हैं। मैं इनको छोटी सी मिसाल देकर ऐसी बात बता दूंगा और मुझे यकीन है कि इनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। पिछले सत्र के दौरान आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के लिए इस महान सदन में धन्यवाद प्रस्ताव

लेकर आये थे और उस धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना था कि जिन्होंने देश के किसानों के फायदे के लिए तीन कृषि कानून बनाये हैं। जिससे देश का किसान समृद्ध और उसकी आय दुगुनी हो सके। उस पर विपक्ष के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि ये किसान के फायदे के कृषि कानून नहीं हैं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने यह कहा था कि इस महान सदन में आप अपना तर्क रखें और हम अपना तर्क रखेंगे। मुझे यह बात बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी तर्क रखने की बजाए इस महान सदन से वॉक–आउट करके चली गई क्योंकि इनके पास कोई तर्क रखने की ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर इनके पास कोई तर्क रखने की बात होती तो इस महान सदन में आकर तर्क वितर्क करते न कि इस महान सदन से वॉक–आउट करके चले जाते। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करता हूं कि हाउस का समय 6:30 बजे तक है। इस हिसाब से सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए टोटल 3 घंटा और 50 मिनट का समय दिया जायेगा। मेरे पास बोलने वालों की 23 मैम्बर्ज की सूची आई हुई है और इनके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपना जवाब देने के लिए 45 मिनट का समय दिया जायेगा। अगर देखा जाये तो 23 मैम्बर्ज के हिसाब से हर मैम्बर के हिस्से में लगभग 8 मिनट का समय आता है। अगर कोई भी सदस्य बोलने वाले सदस्य को बीच में डिस्टर्ब करेगा तो बाद में बोलने वाले सदस्यों के लिए दिक्कत खड़ी हो जायेगी इसलिए प्रत्येक मैम्बर को लगभग 8 मिनट का समय दिया जायेगा। मेरी सभी माननीय सदस्यों से दोबारा से विनती है कि यदि कोई मैम्बर बोलता है तो उसको बीच में टोका–टाकी न करें।

श्री विनोद भ्याना : अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी सरकार किसान के सम्मान की बात करती है तो विपक्ष के लोग किसान–किसान करते हैं। किसान को सम्मान देने का काम केवल और केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। जिसका उदाहरण आपके सामने है। किसान को सम्मान भत्ता 6 हजार सालाना देकर के किसान का मान सम्मान बढ़ाया है। अगर मैं एम.एस.पी. की बात करूं तो आज हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में एम.एस.पी. पर अधिकतर फसलें खरीद रही हैं। जिसके कारण हमारा हरियाणा प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी किसानों के प्रति कितनी अच्छी सोच रखते हैं। आज एम.एस.पी. पर अधिकतर फसलें खरीदी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय,

मैं इसके अलावा किसान को मुआवजा देने की बात करूं तो जितना मुआवजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को दिया है शायद आज से पहले किसी भी सरकार ने किसानों को इतना मुआवजा देने का कार्य किया हो। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री आफताब अहमद (नूंह) : स्पीकर सर, आज आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल होने के लिए मौका दिया सबसे पहले इसके लिए आपका शुक्रिया। हमारे बहुत से साथी किसान की जब बात करते हैं उसमें यह कहते हैं कि किसानों के लिए जो कानून बने हैं उनमें काला क्या है? कल हमने कई बार अपने सत्ता पक्ष के साथियों को समझाने की कोशिश की। कल सैनी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और आज डॉ. कादियान जी ने जिस तरीके से व्याख्या की थी उसमें सभी पहलुओं को क्लीयर किया था। सर, हरियाणा प्रदेश सन् 1966 में बना था। जब हरियाणा प्रदेश का निर्माण हुआ था उस समय यह कहा गया था कि इनके पास न तो अपने रिसोर्सिज हैं और न इनके पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा है। उस समय यह मान्यता थी कि हरियाणा प्रदेश कभी भी सक्षम राज्य नहीं बन सकेगा। हमारे मेहनतकश किसानों ने न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के अन्न भण्डार को भी भरने में अपना विशेष योगदान दिया। हमारा हरियाणा प्रदेश आज की तारीख में एक कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता है। मुझे यह बात कहते हुए गर्व होता है कि हमारे हरियाणा के किसानों ने पूरे देश में अपना परचम लहराया है। अगर हमारे प्रदेश का किसान कृषि कानूनों के विरूद्ध है तो या तो हमारे सत्ता पक्ष के साथियों को इस बात की समझ नहीं है या फिर वे जानबूझकर सच्चाई को नजरअंदाज करना चाहते हैं। किसानों ने सत्ता पक्ष के विधायकों को अपने–अपने हल्कों में जाने पर भी रोक लगा रखी है। उनका यही कहना है कि जो इन कृषि कानूनों के विरोध में हमारे साथ नहीं है हम उसका पूर्ण बॉयकाट करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के विधायक अपने हल्कों में नहीं जा सकते। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको भी कांग्रेस पार्टी ने ही बहका दिया है? भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ मजाक कर रही है और इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को बहका रही है। हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। यह बात हम किसान

आंदोलन के पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी हम अपनी इसी बात पर कायम हैं। सत्ता पक्ष के लोग किसानों के आचरण और कुर्बानी पर जिस तरह की बातें करते हैं हमें वे बातें सुनते हुए भी शर्म आती है। सर, कल मेरा सवाल था कि जिन किसानों की मृत्यु किसान आंदोलन के दौरान हुई है क्या उनको शहीद का दर्जा दिया जायेगा? मेरे सवाल का छठा नम्बर था लेकिन इसके बावजूद भी वह पुट–अप नहीं हो पाया। मैं आज भी इस पर चर्चा की मांग करता हूं। हरियाणा में यह इतिहास रहा है कि अगर किसी भी किसान की किसान आंदोलन में मृत्यु हुई है तो उसको शहीद का दर्जा दिया गया है। पड़ोस के राज्य पंजाब में भी जिन किसानों की मृत्यु किसान आंदोलन के दौरान हुई है उनको शहीद का दर्जा देकर उनके परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देकर सहारा देने का काम किया गया है। सर, सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का एलांयस कोई नेचुरल एलांयस नहीं है। जब झूठ के सहारे से 75 पार का नारा देकर भी भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके ही हरियाणा विधान सभा के चुनावों में 10 सीटें जीतने वाली जननायक जनता पार्टी के साथ गठबन्धन करके सरकार का गठन किया गया। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी विरोधी दल हैं लेकिन सत्ता के लालच में एक हो गये हैं। इनका मेल मन का मेल नहीं है इसलिए जब हमारी पार्टी द्वारा सरकार के खिलाफ नो कांफिडैंस मोशन लाने की बात कही जाती है तो इससे गठबन्धन सरकार को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्पीकर सर, अगर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वायदे पूरे करती तो हरियाणा की जनता में इन दोनों पार्टियों के प्रति इतना असंतोष नहीं होता। अगर यह गठबन्धन सरकार सही नीयत और सही नीति से काम करती तो हरियाणा प्रदेश की तस्वीर कुछ और ही होती। आज सरकार में ऐसा माहौल है कि किसी एक विषय पर मुख्यमंत्री के ब्यान कुछ होते हैं और मंत्री के ब्यान कुछ और होते हैं जबकि होना तो यही चाहिए कि मुख्यमंत्री और पूरी केबिनेट को मिलकर काम करना चाहिए। इस समय विपक्ष की बातों की तो अखबारों में कम हैड लाईन बनती है जबकि सरकार की कार्यशैली की समाचार–पत्रों में ज्यादा हैड लाईन बनती हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री आफताब जी को यह कहना चाहता हूं कि वे हमारी गठबन्धन सरकार

की चिंता न करके अपनी पार्टी की चिंता करें। इनको अपना टाईम भी याद करना चाहिए कि इन्होंने श्री कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के साथ क्या किया था?

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, आप प्लीज वाईंड–अप करें।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश घोटालों की वजह से जाना जा रहा है। यह बड़े शर्म की बात है कि एक के बाद एक घोटाले होते जा रहे हैं। चाहे शराब घोटाला हो, चाहे जमीन घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो या धान घोटाला हो। सरकार जीरो टॉलरेंस के बहुत बड़े–बड़े दावे करती है लेकिन इस बात का बड़ा दुख होता है कि आज तक किसी को सजा नहीं दी गई है और न ही किसी को इंगित किया गया है कि यह दोषी है। क्या एक सवा साल में सरकार में इन बातों का फैसला ही नहीं हो पाया। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बड़े–बड़े दावे करती है लेकिन असलियत यह है कि सरकार की स्वयं की संलिप्तता है इसलिए पर्दाफाश हो कर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो पाता है। आज सारी की सारी जांचें या तो एस.आई.टी. में अटकी हुई हैं या उनका निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है जबकि सरकार कहती है कि करप्शन फ्री गवर्नमैंट है। मैं इस महान सदन के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर सरकार में जनता के प्रति कोई भावना है तो चुनाव से पहले जो वायदे किये गये थे या जनता के साथ कोई कमिटमैंट की गई थी वह पूरी करे। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 40 विधायक दिये थे, हालांकि थे तो वे अल्पमत के ही लेकिन फिर भी जनता से किये गये वायदे पूरे करने चाहिएं। सरकार की तरफ से नारा दिया गया था कि सबका–साथ सबका–विकास लेकिन मुझे बड़े भारी मन से यह कहना पड़ता है कि कहीं पर भी विकास नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, आपका समय समाप्त हो रहा है इसलिए आप जल्दी से वाइंड अप कीजिए।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, अब मैं मैडिकल कॉलेज की बात पर आता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बड़े भारी दावे करते हैं। मेरे क्षेत्र में मैडिकल कॉलेज है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमने वर्ष 2012 से उसे चलाया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रोहतक के बाद मेवात की धरती पर शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मैडिकल कॉलेज बन सकता है लेकिन हमने उसे बनाया और चलाया। लेकिन पिछले 6 साल से स्वास्थ्य मंत्री जी एक बार भी इस कॉलेज में नहीं गये हैं। आज उस कॉलेज की हालत ऐसी हो गई है कि वह खुद बीमार नजर आ रहा है। वहीं

पर 100 बैड का डैंटल कॉलेज था जिसको घटा कर आज मंत्री जी 50 बैड का बनाने में लगे हुये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आफताब जी, आपका समय समाप्त हो गया है, इसलिए अब आप बैठ जाइये।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा (जीन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की झलक मात्र से ही पता चलता है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली भाजपा–जजपा की सरकार जनकल्याणकारी नीतियों के साथ गरीब, मजदूर, किसान, कमेरे, अनाथ और असहाय लोगों की सेवा का जज्बा लिए हरियाणा प्रदेश के उत्थान के लिए निरन्तर प्रयासरत है। वर्ष 2019 के आम चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता से जो वायदे हमने किए, कोराना काल के चलते भी मनोहर सरकार अपने वायदों को निभाने के लिए प्रयासरत रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश के हर नागरिक को एक "परिवार–पहचान पत्र" प्रदान करने का काम किया है जिससे जहां भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी वहीं अवैध कब्जा रोकने के लिए मनोहर सरकार ने "लाल डोरा मुक्त" प्रदेश में व्यवस्था प्रदान करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में ऐतिहासिक सुधारों की सराहना प्रदेश का जन–जन कर रहा है लेकिन विपक्ष को ऐतिहासिक सुधार पच नही रहे हैं। मैं तो विपक्ष के साथियों को इतना ही कहना चाहूंगा कि :–

लाल डोरा हमने तोड़ दिया गांव का बाजारों का,
देकर पहचान भला करेंगे हम सब परिवारों का,
तुम्हारे कहने भर से क्या सच झूठ हो जायेगा,
जितना चाहे ढोल बजाओ, विरोध करो तुम सुधारों का।

अध्यक्ष महोदय, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसान और खेती के लिए निरन्तर ऐतिहासिक फैसले ले रही है। हमारी सरकार ने किसान को सुगम सिंचाई व्यवस्था प्रदान के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू करके, किसान हित में कदम बढाए हैं वही "मेरा पानी मेरी विरासत" योजना को लागू करके किसान को धान का विकल्प प्रदान करने का काम किया है। स्पीकर सर, मनोहर लाल जी की भाजपा सरकार देश में गन्ने का सबसे ज्यादा भाव किसानों को प्रदान करके स्वयं

में किसान हितैषी होने का प्रमाण दे रही है। विपक्ष निरन्तर किसान पर राजनीति कर रहा है लेकिन 10 वर्ष कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसान को बचाने के लिए पानी बचाने की किस परियोजना पर कार्य किया है? अध्यक्ष महोदय, विषय यह है कि किसान को बचाने के लिए और किसान की आय को दोगुणा करने के लिए सर्वप्रथम किसान को नहरी जल उपलब्ध करवाना अतिआवश्यक है। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि किसान की फसल एवं हरियाणा प्रदेश के हक के लिए एस.वाई.एल. नहर के लिए मुझे पंजाब में जेल में जाना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की किसान हितैषी सोच के अनुरूप राज्य को अतिरिक्त पानी उपलबध करवाने के लिए सरकार यमुना नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांधों के निर्माण की मजबूती से पैरवी कर रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी की एक सोच है किः–

पानी सिर्फ पानी नहीं, विरासत है मेरे मान की,
इसको बचा के रखना, बात है एक शान की।
सवालों से नहीं, सोच से बदलेगा नजारा,
पानी बचेगा तो बदलेंगे तकदीर किसान की।

स्पीकर सर, पूर्व की सरकारों में जीन्द मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता था लेकिन हमारी सरकार जीन्द को स्वास्थ्य–शिक्षा के साथ–साथ मूलभूत सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर साधुवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे पिता श्री तथा तत्कालीन विधायक ब्रह्मलीन डॉ. हरिचन्द मिड्ढ़ा के आग्रह पर जीन्द के हैबतपुर में मैडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। यह एल एण्ड टी कम्पनी द्वारा 30 महीने में 750 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हो जाना तय है। स्पीकर सर, बड़े हैरानी का विषय है कि जीन्द जिला प्रदेश के प्रारंभिक सात जिलों में शामिल है तथा सूबे की राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ है । शहर में नहरी जल पर आधारित पेयजल'' व्यवस्था न होने का एक उदाहरण और है। पूर्व की सरकारों ने किस प्रकार जीन्द की अनदेखी की है वह आपके सामने है लेकिन मनोहर लाल जी ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया और मेरी मांग पर भाखड़ा–नरवाना ब्रांच से जीन्द की जनता को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से यह परियोजना तैयार हो रही है। क्योंकिः–

''लाख उछालो पत्थर हम पर,
लाख चला लो बातों के तीर।
अंधेरा अब रोक ना पाएगा।
जगमग होगी हरियाणा की तस्वीर।।''

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार धरोहरों एवं पुरातत्व–संग्रहालयों के विकास एवं रखरखाव के लिए निरंतर काम कर रही है। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मैं उस भूमि से आया हूं जहां पर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। वहां पर वंशमूलक तीर्थ बरसोला, रामराये में भगवान परशुराम का प्राचीन मन्दिर, प्राचीन भूतेश्वर मन्दिर–रानीतालाब में, कुरूक्षेत्र के युद्ध का फैसला करने वाली भूमि–इक्कस तथा पाण्डवों की परम्परा के प्रतीक पिण्डारा में स्थली मां जयंती देवी के शहर के मंदिर में, पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा दो–दो करोड़ रुपये की राशि देने का काम किया है। स्पीकर सर, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यह भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए वचनबद्ध है लेकिन मुद्दाविहीन विपक्ष आज कभी किसानों, कभी पैट्रोल व डीजल की कीमतों पर जनता में भ्रम फैलाने की नापाक कोशिश करता है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि–

''हमसे जलना इनकी फितरत है,
झूठी इनकी हार तोहमद है।
खोल कर सुन ले कान जरा,
आगे बढ़ते रहना, मनोहर लाल जी की फितरत है।''

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ मांग सदन के पटल पर रखना चाहता हूं । लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र जीन्द में खोला जाना अति आवश्यक है क्योंकि जीन्द के बीड़ में मुर्राह नस्ल की भैंसे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जीन्द शुगर मिल की पिराई क्षमता बढ़ाए जाने का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में किया जाए। जीन्द में माता जयंती देवी मन्दिर के सामने अस्थाई नंदीशाला को स्थाई नंदीशाला में शिफ्ट करके उपरोक्त जमीन पर हर्बल पार्क और एक कम्युनिटी सैंटर बनाये जाने का प्रावधान वित वर्ष 2021–22 में सुनिश्चित किया जाए। पटियाला चौक से आगे वीटा मिल्क प्लांट के सामने से इक्कस बाई–पास तथा पटियाला चौक अपोलो रोड से सी.आई.ए. स्टाफ थाना की सड़क को चार

मार्गीय बनाए जाने का प्रावधान वित वर्ष 2021–22 में किया जाए। शहर के अन्दर 18 फुट से अधिक चौड़ी मेन सड़कों जिनको पेवर ब्लॉक से निर्मित किया गया है को दोबारा ब्लैक टॉप किए जाने का काम किया जाए। पिंडारा तीर्थ को विकसित करने के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाए। जिस प्रकार से कुरूक्षेत्र में बना हुआ है उसी प्रकार से वहां बनाया जाए । वहां जब युद्ध समाप्त हुआ था तो पांडवों ने यहां पिंड दान किये थे इसलिए इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए। राजकीय हाई स्कूल अमरहेड़ी का दर्जा इसी सत्र में बढ़ाए जाने की घोषणा की जाए। अध्यक्ष महोदय, पहले पंजाब में सबसे ज्यादा ट्रक बॉडी बनाई जाती थी लेकिन आज जीन्द भी ट्रक बॉडी मेकिंग का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। जीन्द में प्रस्तावित पोलटैक्निक कॉलेज की भी शुरूआत की जाए। जीन्द जिले के बुडायन में एक मात्र केन्द्रीय विद्यालय में बिजली और पीने के पानी का प्रबंध विभाग द्वारा आगामी कुछ दिनों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जीन्द विधान सभा तथा अलेवा खंड के गांव रायचन्दवाला में एक उप–स्वास्थ्य केन्द्र वित वर्ष 2021–22 में खोला जाए। जीन्द विधान सभा क्षेत्र के गांव डालमवाला, बोहतवाला, खुंगा, रायचन्दवाला, गांव को उचाना उप–मंडल से जीन्द उप–मंडल में जोड़ा जाए क्योंकि ये गांव पूर्व में भी जीन्द उप–मंडल का ही हिस्सा थे। अध्यक्ष महोदय, ये मांग मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखता हूं और आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद।

15-00 बजे

श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सवेरे जब मैं उठा तो मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा तो पाया कि इसमें असलियत तो कुछ भी नहीं है सिर्फ फ्यूचर टैंस को आधार बनाकर सारी बातें कहीं गई हैं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि राज्यपाल महोदय सच बोलेंगे लेकिन *राज्यपाल महोदय को तो वही बोलना पड़ता है जो सरकार लिखकर देती है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में न तो किसी घपले के बारे में लिखा गया है

न कोई और दूसरे महत्वपूर्ण विषयों को ही कोई स्थान दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

———————————————————————————————————————

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने महामहिम के लिए * शब्द का प्रयोग किया है अतः आपसे अनुरोध है कि शब्द को प्रोसीडिंग्ज का हिस्सा न बनाया जाये?

श्री अध्यक्षः ठीक है, * शब्द को रिकॉर्ड न किया जाये।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे इस शब्द से किसी को आपत्ति है तो मैं इस शब्द को वापिस लेता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कितनी अजीब बात है सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हमसे सवाल पूछते हैं तो इसका तो सीधा सा मतलब निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाने वाली है। कितनी विडम्बना की बात है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में जितने घपले हुए, उनकी जो इंक्वायरी हुई तथा उनकी जो रिपोर्ट आई उनका कोई भी जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं किया गया जबकि इस तरह की बातों को जनता को बताने का इस पवित्र सदन से ज्यादा उपयुक्त जगह और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, 14 फरवरी को करनाल में एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई जिसके बारे में शायद कल्याण साहब और कश्यप साहब ने भी अखबारों में पढ़ लिया होगा। यह एक रजिस्ट्री घोटाला है जिसके बारे में 'पंजाब केसर' अखबार में खबर छपी है। अध्यक्ष महोदय, फेक आई डी व एन.डी.सी. बनाकर 209 रजिस्ट्रियां कर दी गई और किसी को कुछ पता तक नहीं चला। अध्यक्ष महोदय, 143 रजिस्ट्रियां तो केवल मात्र एक ही आई. डी. से की गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इसकी जांच होगी? अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में उस एफ.आई.आर. की कापी भी है और जिस अखबार में यह खबर छपी है, वह अखबार भी मेरे हाथ में है। अध्यक्ष महोदय, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर वह सच्चाई को मान लेता है तो आने वाले समय में सुखी रहेगा और नहीं मानेगा तो आने वाले समय में दुखी रहेगा। सच्चाई–सच्चाई होती है और झूठ–झूठ रहता है। अब जिस तरह मेरे सामने की बैंचों पर बैठने वाले लोग दुखी है वह इनके कर्मों का फल है। कर्मों के बारे में तो गीता ज्ञान तक दिया गया है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अध्यक्ष महोदय, गीता का ज्ञान बताता है कि सबको कर्मो का फल मिलता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सदन को

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

पेट्रोल–डीज़ल के रेट में लगातार हो रही बढ़ौत्तरी के विषय पर कहना चाहूँगा क्योंकि किसानों के मुद्दों पर बोलने पर तो सत्ता पक्ष वालों को तकलीफ होती है। किसान आंदोलन में किसान की अगर मौत हो जाती है तो सत्ता पक्ष वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह इतनी संवेदनहीन सरकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्हें किसानों की मौतों पर दुख नहीं होता है। सत्ता पक्ष के सदस्य कहते हैं कि वर्ष 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार वर्ष 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं कर पाई तो क्या किसानों की आय के लिए अलग से बजट का कोई प्रावधान करेगी। दूसरी तरफ हर रोज पैट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ौत्तरी हो रही है और सरकार कहती है कि यह मैटर इंटरनैशनल मार्किट के हिसाब से चलता है। मैं स्वयं पैट्रोल पंप चलाता हूँ और मैं ऑल इण्डिया ऑयल एसोसिएशन का प्रधान भी रहा हूँ। सरकार ने मेरे पैट्रोल पंप बंद कर दिये हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज पैट्रोल और डीजल के दामों में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इस संबंध में पूरी तरह से गंभीर है तो इस विषय की जांच उच्चतम न्यायालय के सिटिंग जज से करवायें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री राम कुमार (इन्द्री): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने चहुँमुखी विकास किया है। अध्यक्ष महोदय, कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान हमारी सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग ने पूर्ण टीकाकरण के साथ ही संयुक्त टीका उपयोग करके राज्य को मवेशियों और भैंसों की मुंहखुर और एच.एस. की बीमारी से मुक्त कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय यह लिया है कि पिछड़ा वर्ग के लिये गांवों में सरपंचों के पद पर 8 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं पिछड़ा वर्ग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। हमारी सरकार ने बड़े–बड़े महापुरूषों अर्थात् गुरू रविदास, वाल्मीकि, डॉ. भीम राव अम्बेडकर, संत कबीर व चाहे गुरू नानक के 550 वें प्रकाशोत्सव की जयंती हो, इन

सब जयंतियों पर अपने खर्चे पर बड़े–बड़े समारोह आयोजित किये हैं, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय व उप मुख्यमंत्री महोदय की सरकार को बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पंचायती राज में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया है । इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। सदन में अभी रोजगार की बात हो रही थी । माननीय सदस्य श्री ईश्वर सिंह जी ने इस पर चर्चा की थी कि माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण दिया है । मुझे उम्मीद है कि इस कार्य से हरियाणा के युवाओं को अच्छी नौकरियां मिलने में मदद मिलेगी । अब मैं अपने हल्के की कुछ मांगों और समस्याओं की तरफ सदन का ध्यान केन्द्रित करूंगा । मेरे हल्के में इंद्री–कुरूक्षेत्र वाया उमरी गांव एक रोड जाता है । वहां पर एक शुगर मिल 'पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड' बनी हुई है । गन्ने के सीजन में इंद्री–कुरूक्षेत्र वाया उमरी गांव के रोड पर गन्ने से भरी ट्रॉलियां चलती हैं जिससे वहां पर जाम लग जाता है । मेरा सरकार से निवेदन है कि उस सड़क को चौड़ा कर दिया जाए । इसके अलावा करनाल से लाडवा वाया खानपुर रोड पर फॉर लेनिंग का काम चल रहा है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं । जहां तक इस रोड पर फॉर लेनिंग का काम चल रहा है वह सिर्फ खानपुर तक चल रहा है । उससे सिर्फ 6 किलोमीटर आगे एक रोड लाडवा, कुरूक्षेत्र और यमुनानगर को कनैक्ट करता है । मेरा निवेदन है कि इस 6 किलोमीटर के टुकड़े को भी फॉर लेन कर दिया जाए । इसके अलावा जब हम गांवों में जाते हैं तो बहुत–सी गरीब महिलाएं बी.पी.एल. कार्ड से संबंधित समस्याएं बताती हैं । सरकार इस ओर अच्छा प्रयास तो कर रही है परन्तु फिर भी इस सिस्टम में अभी उनको असुविधा हो रही है । मेरा निवेदन है कि सरकार इसका पुनः सर्वे करवाए ताकि जो लोग बी.पी.एल. कार्ड बनवाने से वंचित रह गये हैं उनके कार्ड बन जाएं । इससे उनको काफी राहत मिलेगी । अध्यक्ष महोदय, अंत मैं 'भरोसे' फिल्म के एक गाने की चार पंक्तियां गाकर सुनाना चाहता हूं ।

इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ
गैर तो गैर ही थे अपनों का सहारा न हुआ ।
लोग तो रो–रोकर भी इस दुनिया में जी लेते हैं,
एक हम हैं जो हंसे भी तो गुजारा न हुआ ।

इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ
गैर तो गैर ही थे अपनों का सहारा न हुआ ।
लोग तो रो–रोकर भी इस दुनिया में जी लेते हैं,
एक हम हैं जो हंसे भी तो गुजारा न हुआ ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि मुझे सभी का सहारा मिला है । आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

मोहम्मद इलियास (पुन्हाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत शुक्रिया अदा करता हूं । माननीय सदस्य गोगी जी कह रहे थे कि आदरणीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण या तो पढ़ा नहीं या देखा नहीं या फिर सरकार ने उनको गुमराह किया है । मैं कहना चाहूंगा कि जब तक महामहिम राज्यपाल महोदय को लगा कि यह अभिभाषण सच्चाई पर आधारित है तब तक तो उन्होंने अभिभाषण को पढ़ा लेकिन जब उन्हें लगा कि सरकार उनको गुमराह कर रही है तब उन्होंने अभिभाषण को पढ़ना बंद कर दिया और कह दिया कि बचे हुए अभिभाषण को पढ़ा हुआ माना जाए । अतः अभिभाषण की वास्तविकता तो इसी बात से साबित हो जाती है । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार की तरफ से सारे विभागों की तारीफ की गयी है और यह कहा गया है कि फ्यूचर में यह कार्य होगा, परन्तु सरकार ने यह नहीं बताया कि क्या–क्या कार्य किए हैं? अब मैं आपको धरातल की बात बताना चाहूंगा। यहां पर माननीय शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेवात जिले के अन्दर कोई ऐसा स्कूल/कॉलेज बता दें कि जिसमें पूरा स्टॉफ हो। इसके बाद दूसरी बात बिजली देने की आती है। बिजली न मिलने से किसान कितना परेशान है, उसके बारे में सरकार और विपक्ष माननीय सदस्य भी जानते हैं। मैं मेरे हल्के का एक ऐसा ही केस बताना चाहूंगा। मेरे हल्के के केहर गांव में 3 महीने पहले ट्रांसफार्मर लगवाना मंजूर हुआ था और उसके लिए खंभे भी लाए जा चुके हैं, परन्तु 3 महीने से आज तक वे ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैं इसके बारे में एस.ई./एक्सियन को भी कह चुका हूं, परन्तु आज तक उनको नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त सड़कों की हालत खराब है। मैंने मेरे हल्के की सड़कों के बारे में हरियाणा विधान सभा की माननीय कमेटी के माध्यम से विभागीय अधिकारी को एक शिकायत दी थी। मौके पर चीफ इंजीनियर भी चैक करने के लिए गए थे। सीकरा

से पुन्हाना तक एक सड़क जाती है। मैंने सड़कों में गढ्डे तो बहुत देखे, परन्तु गढ्डों में सड़क सीकरा से पुन्हाना में देखी है। इसी प्रकार फरदरी से पुन्हाना तक की सड़क जाकर देख लें, लेकिन आज तक उनको ठीक नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त सिंचाई के बारे में माननीय मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल साहब कह रहे थे कि उन्होंने दक्षिण हरियाणा को पानी पहुंचा दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मेवात जिला दक्षिण हरियाणा में नहीं आता है? वहां के लोगों की फसलें पानी की वजह से सूख रही हैं। आप वहां पर मेरे साथ कोई कमेटी बनवाकर भेज दें और अगर कोई यह साबित कर दे कि मैं सदन में झूठ बोल रहा हूं तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। हमारे एरिया के खेतों में एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा है। माननीय सदस्य डॉ0 अभय सिंह यादव जी कह रहे थे कि दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंच गया है। माननीय सदस्य ही बता दें कि दक्षिण हरियाणा में पानी की क्या पॉजीशन है ?

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, आज दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंच रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, इस वक्त वहां पर फसलें पकने जा रही है, परन्तु इरीगेशन विभाग पानी नहीं दे रहा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों का ताल्लुक है। हम सभी माननीय सदस्यगण और आप भी कहीं न कहीं किसानों के बेटे हैं, किसानों की बेटियां हैं, किसानों के मां–बाप और रिश्तेदार हैं। किसान आंदोलन में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं और वे सभी किसान हिन्दुस्तान के ही थे। हमारा हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और यहां पर 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। हरियाणा प्रदेश भी कृषि प्रधान राज्य है। यह बड़े अफसोस की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात तो बहुत करते हैं लेकिन उन्होंने किसानों के प्रति कोई मन की बात नहीं की है।

श्री अध्यक्षः इलियास जी, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, आप उसके बारे में यहां पर चर्चा न करें।

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसानों के प्रति एक भी शब्द श्रद्धांजलि के लिए नहीं था, परन्तु जब आर.एस.एस. के लोगों की भैंस या कटड़ा भी मर जाता है तो सरकार के माननीय मंत्री जी वहां पर शोक प्रकट करने पहुंच जाते हैं। किसान आंदोलन के कारण पूरे देश और प्रदेश के कुल

250 किसान मर चुके हैं, परन्तु सरकार की तरफ से उनके लिए कोई भी शोक प्रकट करने के लिए नहीं गया। (विघ्न)

डॉ0 कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सदन में आर.एस.एस. की बात करने का क्या मतलब है ? मैं इटली का नाम लूंगा तो कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को बुरा लगेगा। (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि किसानों की मांगों को माना जाये ताकि एम.एस.पी. पर कानून बनाया जाये। हमारे प्रदेश की 36 बिरादरी चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो और चाहे कर्मचारी वर्ग हो, इनमें से किसी भी वर्ग के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के से संबंधित कुछ मांगों को सदन में रखना चाहता हूं। मुझे इसके लिए दो मिनट का समय और दे दीजिए। मेरे हल्के में दो कस्बे हैं एक पुन्हाना है और एक पिनगवां है। इन दोनों कस्बों के लिए बजट में भी प्रावधान कर दिया गया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध और मांग भी करता हूं कि कृपया करके बाइपास के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द बनाया जाये। मैंने पिछले सत्र के दौरान गंगवानी माइनर की भी मांग रखी थी। उस माइनर का 75 फीसदी हिस्सा बना हुआ है इसलिए उसको भी जल्द से जल्द पूरा करवाने का काम किया जाये ताकि वहां के रहने वाले किसान अपनी फसलों को समय पर पानी दे सके। मेरे हल्के से एक उजीना डायवर्सन ड्रेन गुजरती है, मैं इस बारे में कई बार इस महान सदन में कह चुका हूं कि इसमें पम्प हाउस बने हुए हैं, सिर्फ इसमें पम्प लगाये जाने बाकी हैं इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर पम्प लगाये जायें ताकि किसान अपने खेतों में सिंचाई कर सके। मेरे हल्के में सिंगार गांव है जो बहुत बड़ा गांव है बल्कि मेवात का सबसे बड़ा गांव है परन्तु वहां की एक एकड़ जमीन में सिंचाई नहीं होती है। मेरी मांग है कि अगर सरकार वहां पर पम्प हाउस बना दे तो उससे हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है कि मेवात का इलाका काफी पिछड़ा हुआ है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूं कि मेवात को हरियाणा से अलग न समझा जाये। सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी। मैं इसके अलावा आपके माध्यम से सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि हमारे नूंह से अल्वर तक जो नैशनल हाईवे बना हुआ है, उसको फोर लेनिंग बनाने का काम किया जाये क्योंकि एक्सीडेंट्स की वजह से वहां काफी मौतें हो चुकी हैं और साल के अंत तक सैंकड़ों

मौते हो जाती हैं इसलिए मेरी मांग है कि उसको फोर लेनिंग बनाने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि मेवात भी हरियाणा का ही अंग है इसलिए इसको अलग न समझा जाये। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं ।

श्री दीपक मंगला (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने इस ''कोविड–19 वैश्विक'' महामारी के दौरान जिस प्रभावी ढंग से इस महामारी को नियंत्रित किया और इस महामारी को नियंत्रित करने में चाहे वो हमारे डॉक्टर्ज हों, चाहे नर्स हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे पुलिस के जवान हों, चाहे सामाजिक संस्थाओं के लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों और चाहे हमारे साथीगण हों, सभी ने मिलजुलकर इस ''कोविड–19 वैश्विक'' महामारी के दौरान जिस तत्परता के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस कोरोना नाम की बीमारी को भगाने में जो अपनी अहम भूमिका निभाई उसकी जितनी प्रशांसा की जाये उतनी कम है। मैं इसके लिए इन सभी को सैल्यूट करता हूं और इसके अलावा मैं हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी इस ''कोविड–19 वैश्विक'' महामारी के दौरान प्रदेश के गरीबों को जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं और चना आदि वितरित करवाने का काम किया था। इसके अलावा मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस कोरोना काल में ''राशन टोकन योजना'' लागू करके गरीबों पर बड़ा उपकार करने का काम किया। प्रदेश में किसी भी गरीब आदमी के पास राशन कार्ड नहीं था तो उसको भी ''राशन टोकन योजना'' के तहत राशन वितरित करने का काम किया गया था। ऐसा करने पर हमारा हरियाणा प्रदेश देश का पहला राज्य बना था। अध्यक्ष महोदय, मेरे कांग्रेस के साथी श्री शमशेर सिंह गोगी जी ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस अभिभाषण को मैंने सुबह पढ़ा था। मुझे लगता है कि मेरे साथी नींद में से उठे होंगे तो शायद पूरा अभिभाषण पढ़ने से रह गये होंगे। श्री गोगी जी ने अभिभाषण को लेकर एक शब्द का प्रयोग किया था कि ''करेंगे''। मैं श्री गोगी जी से पूछना चाहूंगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पहले कौन करता था? हम सभी को इस बात का पता है। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गोगी जी की जानकारी के लिए बताना

चाहूंगा कि इस प्रकार की भाषा पूर्व के प्रधानमंत्री जी बोला करते थे ''करेंगे'', ''देखेंगे'', ''होगा''। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, सदन में बार–बार किसानों की बातें हो रही हैं। साथियों मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि किसानों की आय बढ़ाने में जो निर्णायक कदम हरियाणा सरकार उठा रही है उसका उदाहरण कम ही देखने को मिलता है। साथियों किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान है चाहे वह किसान सॉयल टैस्ट कार्ड की बात हो, चाहे किसान क्रेटिड कार्ड की बात हो, चाहे मुआवजा राशि के वितरण की बात हो, चाहे किसान फसल योजना की बात हो और चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो इन सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किये हैं। मुझे याद है जब वर्ष 2014 में चुनावों के परिणाम आ जाने के बाद प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद मेरे पलवल जिले में बारिश और ओलावृष्टि से हमारे किसान भाइयों की फसलों का बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ था। उस समय पलवल जिले से एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सबका साथ–सबका विकास को चरितार्थ करके दिखाया और 200 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि पलवल जिले के किसानों को वितरित की। स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में फोर लेन और सिक्स लेन सड़कों का जाल बिछा दिया है। हरियाणा प्रदेश में जिन हाईवेज का निर्माण हमारी सरकार के शासनकाल में हुआ है जब कोई व्यक्ति अपना व्हीकल लेकर उन हाईवेज पर चलता है तो पता ही नहीं चलता की वह कब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। हमारा पलवल शहर ट्रैफिक जाम की समस्या से बहुत बुरी तरह परेशान था। पलवल का जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पेलक गांव के अंदर एक इंटर चेंज देने की राज्य सरकार द्वारा अभी केन्द्र सरकार से योजना मंजूर करवाई गई है। उस पर सैक्शन 3–ए पर भी काम शुरू हो गया है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। विपक्ष के साथी झूठ का सहारा लेकर प्रदेश के किसान भाइयों को बहकाने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नये कृषि कानूनों के अमल में आने से किसानों की जमीनों पर प्राईवेट कम्पनीज का कब्जा हो जायेगा। मैं इनसे सबसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि तीन कृषि कानूनों पर बात करने से पहले इनमें से कोई ये तो बता दे कि ये तीन कृषि कानून कौन–कौन से हैं? इनका

कोई भी सदस्य अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बता पाया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस कानून की धारा 8 में यह स्पष्ट तौर पर लिखा पड़ा है कि उत्पाद का अनुबंध हो सकता है लेकिन जमीन का अनुबंध किसी भी रूप में नहीं हो सकता। विपक्ष के साथियों का काम सिर्फ और सिर्फ किसानों को बहकाने का ही है जबकि इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। इन्होंने हमेशा से ही झूठ की राजनीति की है। मैं अपने विपक्ष के साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि झूठ की राजनीति करने से सत्ता हाथ में नहीं आती बल्कि सत्ता तो ईमानदारीपूर्वक प्रदेश की जनता की सेवा करके प्रदेश का चहुंमुखी विकास करने से प्राप्त होती है। हमारी सरकार प्रत्येक क्षेत्र के अंदर विकास के अभूतपूर्व कार्य कर रही है। स्पीकर सर, अब मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में यमुना नदी पर एक बैराज बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है ताकि पलवल और मेवात के क्षेत्र में भविष्य में पीने के पानी की कोई समस्या उत्पन्न न हो। इस समय मेरे क्षेत्र में यमुना नदी पर बैराज न होने से मेरे क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर लगातार बड़ी तेजी के साथ नीचे जा रहा है। अगर यमुना नदी पर मेरे क्षेत्र में बैराज बन जायेगा तो मेरे क्षेत्र का भूमिगत जलस्तर ऊपर आ जायेगा और भविष्य में पलवल व मेवात जिले में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं होगी। एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पलवल में एलिवेटिड फ्लाई–ओवर का निर्माण हो रहा है मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि उसके दोनों ओर नाला बनाकर पलवल शहर की कॉलोनियों के पानी की निकासी के समुचित प्रबन्ध किये जायें। स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री नयन पाल रावत (पृथला): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं 2–3 बातें कह कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारी मनोहर लाल जी की सरकार ने अपनी पहली योजना में और इस कार्यकाल के एक सवा साल में जिस प्रकार से हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबका साथ–सबका विकास के नाते से काम किया है मैं उसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। पहले की सरकारों में खुद का विकास होता था। यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि पूरे प्रदेश का समुचित विकास हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहते थे

कि केन्द्र सरकार से 1 रूपया भेजा जाता है लेकिन जब धरातल पर पहुंचता है तो केवल 15 पैसे रह जाते हैं। मैं केन्द्र की सरकार और राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पूरा का पूरा पैसा खातों में जाता है और पूरा पैसा लगता है। एक बात मैं किसान आन्दोलन के बारे में भी बता देना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार ने अपने रहते हुए किसान की भलाई की बात तो दूर इन्होंने किसी की भलाई के बारे में सोचा तक नहीं। ये सी.एल.यू. के नाम पर जमीन हड़पने का काम करते थे। कभी सैक्शन 4 का नोटिस और कभी सैक्शन 6 का नोटिस। सैक्शन 4 और सैक्शन 6 का नोटिस होने के बाद जमीन को हड़पने का काम करते थे। हरियाणा में पहली ऐसी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की बनी जिसने कांग्रेस सरकार द्वारा एक्वायर की गई 3500 एकड़ जमीन को वापिस करने का काम किया है। फसल के जहां तक रेट की बात है, एम.एस. पी. की बात है तो अभी हमारे साथी असीम गोयल जी ने बताया था कि पहले 98 हजार करोड़ रुपये केन्द्रीय बजट में एम.एस.पी. पर फसल खरीद के लिए होता था जिसको बढ़ा कर 2.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार से एम.एस. पी. पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया है। यह बात तय है कि किसान की फसल एम.एस.पी. पर ही खरीदी जायेगी। जहां तक कांट्रैक्ट फार्मिंग की बात है तो कांट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कोई किसान बाध्य नहीं है। अगर कोई किसान अपनी जमीन कांट्रैक्ट फार्मिंग के लिए देना चाहता है तो दे सकता है और अगर कोई नहीं देना चाहता हो तो न दे। मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि वे पहले पूरे एक्ट को पढ़ लें और किसानों को गुमराह न करें। किसानों को गुमराह करने से उनको सत्ता हासिल होने वाली नहीं है। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि पड़ोस में ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर बाजरे की खरीद 1100/– रुपये प्रति क्विंटल के भाव से हो रही है और हमारी सरकार किसानों का बाजरा 2100/– रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीद रही है। इसी प्रकार से पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहां पर मक्का की खरीद 1000/– रुपये प्रति क्विंटल के भाव से हो रही है जबकि हमारी सरकार 1800/– रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मक्का की खरीद कर रही है। अब ये साथी स्वयं बता दें कि कांग्रेस अच्छी है या हमारी सरकार अच्छी है। इससे साबित होता है कि श्री मनोहर लाल जी की हरियाणा सरकार ही किसानों की सच्ची हितैषी है और हमारी सरकार ही किसानों का हित कर सकती है। जहां तक

किसान आंदोलन की बात है तो अब वहां पर केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता रह गये हैं और उन्हीं का शोर–शराबा है। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि ये कानून किसानों के हित में हैं इसलिए ये किसानों को बरगलाने का काम न करें। ये कानून किसानों की आय को दोगुणा करने के लिए बनाए गये हैं लेकिन हमारे विपक्ष के साथी किसानों की आय दोगुणी नहीं होने देना चाहते इसीलिए ये किसानों को बरगलाने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की भी दो बातें रखना चाहता हूं। मेरा फरीदाबाद का एरिया बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है इसलिए हम फरीदाबाद के सभी विधायक यह मांग करते हैं कि पलवल में इंडस्ट्रीज की एक मदर यूनिट लगाने का काम किया जाये। जमीन हम फरीदाबाद के सभी विधायक उपलब्ध करवा देंगे। इसके अतिरिक्त मेरी दूसरी मांग यह है कि चंदावली गांव से के.जी.पी. पर लिंक देना पास हो चुका है इसलिए उसका लिंक यथाशीघ्र चालू किया जाये। वहां से 6–7 गांवों को रास्ता मिल जायेगा क्योंकि इन गांवों से निकलने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरी यही दो मांग हैं धन्यवाद।

श्री अमित सिहाग (डबवाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से मैं मानता हूं कि इसमें सही मायने में दर्शाने का प्रयास किया गया है कि "All is well" सरकार की कार्यकुशलता को मापने के चार अहम परिचायक हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। इनमें मैं सबसे पहला परिचायक है किसान जिस पर बहुत चर्चा हुई और जो जरूरत है, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और जब इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसान 100 दिन से सड़कों पर हो अपना घर–बार छोड़कर बोर्डर को सील किया हो तो आप लोगों को यह मान लेने की आवश्कता है कि "All is well" यानि आज प्रदेश के हालात ठीक नहीं हैं। बोर्डर पर बैठे किसान मांग क्या करते हैं? केवल एक कि ये सरकार केन्द्र की बात न सुनते हुए उन किसानों के मन की बात सुने जिन्होंने आपको इस सत्ता की चाबी देने का काम किया है। वे किसान केवल एक मांग करते हैं कि अगर आप हमारी आमदनी को बढ़ा नहीं सकते हैं तो कम से कम एम.एस.पी. का कानूनी प्रावधान दीजिए ताकि जो हरियाणा का कृषि आधारित परिवार है जिसकी वार्षिक आय आज की तारीख में 1 लाख 73 हजार रुपये, वह घट कर भविष्य में बिहार प्रदेश के किसान परिवार की वार्षिक आय 42 हजार रुपये तक न पहुंच जाए। वे किसान आप लोगों से केवल ये मांग करते हैं लेकिन ऐसा महसूस होता है

कि सरकार राजधर्म निभाने की बजाए कुर्सी का धर्म निभाने में कहीं न कहीं मशरूफ है। आज की तारीख में ये बात खुद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने रखी कि आज की तारीख में इन किसानों और मजदूरों ने अपने दिलों में, अपने घरों में, अपने गांवों में हम लोगों के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिये हैं। उसके बाद भी यह लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है यानी ऑल इज वैल। मैं इस संदर्भ में आपसे यही मांग करना चाहूंगा कि एम.एस.पी. के कानून को केवल आश्वासन नहीं चाहिए जैसे हमारे मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि केवल 9 फसलों पर एम.एस.पी. दी जाएगी। किसान आश्वासन नहीं चाहते। वे तो केवल कानूनी प्रावधान चाहते हैं जिसमें एम.एस.पी. से कम रेट में फसल खरीदने वाले के लिए सजा का प्रावधान हो। मेरा दूसरा परिचायक यह है कि आज की जो कानून व्यवस्था है उसमें मैं केवल अपने हल्के का उदाहरण देना चाहूंगा जिसमें मेरे पास कुछ प्रैस कटिंग्ज हैं, जिनमें लिखा है कि–गंगा में बढ़ रही चोरियां, ग्रामीणों ने अपने स्तर पर तैनात किया चौकीदार, पुलिस के नाके सिर्फ नाम के, राजस्थान से बे–रोक–टोक शहर के रास्ते पंजाब में नशा सप्लाई कर रहे तस्कर। नशे के दल–दल में फंसता जा रहा युवा, लोगों में नाराजगी। हथियारों के बल–पर बनाया बंधक, लूटी नकदी। इसी तरह से चौटाला गांव में 30 हजार नशीली गोलियों के साथ राजस्थान का युवक काबू। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में इस तरह की व्यवस्था का होना क्या ठीक है? इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? मेरे हल्के में एक कालूआना गांव पड़ता है वहां पर गऊशाला के गुल्लक से सौ या हजार रुपये की चोरी करने के लिए वहां के चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी गई लेकिन अभी तक उसके हत्यारों का पता नहीं चला है। आज की तारीख में इस तरह के काम हो रहे हैं। जहां तक आंकड़ों का सवाल है जिनको हमारे प्रशासन ने आप तक पहुंचाने का काम किया है। यह सोचने का विषय है कि वर्ष 2020 एक ऐसा वर्ष था जिसमें कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण करीब पूरे वर्ष लॉकडाउन रहा लेकिन उस समय भी डबवाली शहर और सदर के अन्दर ड्रग्स की सप्लाई चलती रही जिसके कारण एन.डी.पी.एस. के तहत 203 केस दर्ज किये गये जिनसे 1100 ग्राम हीरोईन बरामद हुई तकरीबन 90 हजार नशीली गोलियां बरामद हुई और 1000 किलोग्राम डोडा–पोस्त बरामद किया गया। यह आज की तारीख में वास्तविकता है। इसी के साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि क्राईम और नशे का एक बहुत बड़ा गठजोड़ है, इसलिए खासकर मेरे क्षेत्र में इसको गम्भीरता से लिया जाए। इसी के साथ मेरी

एक मांग है कि जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए एक मांग यह करना चाहूंगा और जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी कि सब–डिविजन डबवाली को कालांवाली सब–डिविजन के साथ जोड़कर डबवाली को जिला बनाया जाए। इस मांग को लेकर मैं 7 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री महोदय से पर्सनली मिला भी था और मेरी उनके साथ सारे तथ्यों पर चर्चा भी हुई थी। उसके बाद अगस्त के महीने में मैंने फिर विधान सभा में सत्र के दौरान इस बात को उठाया था। आज सरकार ने इन दोनों मुद्दों को लेकर इंक्वायरी करवाई है उसमें खुद अधिकारियों ने कहा है कि डबवाली एक तरफ राजस्थान के साथ और दूसरी तरफ पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है। जिसकी वजह से वहां पर नशे का व्यापार फल–फूल रहा है। वहां हमारे लिए एक बहुत भारी समस्या यह भी है कि वहां पर पुलिस बल की कमी है। वहां पूरे तरीके से सारे मापदंड पूरे किये जाएं। सब–डिविजन कालांवाली और डबवाली को जोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि अदालत डबवाली के अन्दर ही लगती है। इस तरह से मैं मानता हूं कि आज डबवाली को जिला बनाने की सब से बड़ी आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि इस बार मेरी इस बात पर पूरी गम्भीरता से संज्ञान लिया जाएगा। जहां तक तीसरे परिचायक की बात है तो वह बेरोजगारी है जिसके बारे में सभी साथियों ने सदन में बड़ी अच्छी पिक्चर दिखाने की कोशिश की लेकिन शायद आंकड़े दिखाना भूल गए। हरियाणा प्रदेश में अप्रैल, 2019 में जो बेरोजगारी का स्तर 26.5 प्रतिशत था वह अप्रैल, 2020 में बढ़कर 45.2 प्रतिशत हो गया। अब आप कहेंगे कि कोरोना काल था परन्तु वर्ष 2019 में कोई कोरोना काल नहीं था। कोविड के दौरान जो प्रदेश हरियाणा से आगे चले गए हैं, अब मैं उनके बारे में बताता हूँ। अप्रैल में तामिलनाडु में 49.8 परसेंट बेरोजगारी थी लेकिन अगस्त में यह घटकर 2.6 प्रतिशत ही रह गई। इसी प्रकार झारखंड में जहां पर बेरोजगारी 47.1 प्रतिशत थी, वहां पर यह घटकर 9.8 प्रतिशत रह गई और ठीक इसी प्रकार के हालात बिहार प्रांत के हैं। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के क्षेत्र में पहली पायदान पर खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह आंकड़े सी.एम.आई.ई. के आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ। इनको कोई भी आदमी कहीं पर भी जाकर देख सकता है। मैं रिसर्च के साथ बात को सिद्ध करके ही बोल रहा हूँ। आंकड़े के हिसाब से आज की स्थिति बताते हुए कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में 26.4 प्रतिशत के आंकड़े के साथ हम फिर से बेरोजगारी के क्षेत्र में नम्बर–1 पर खड़े हुए हैं। जहां तक कोविड काल की बात है,

सत्ता पक्ष की तरफ से बड़ी–बड़ी बातें कही जा रही हैं कि सरकार ने कोविड काल को बहुत बढ़िया तरीके से संभाला लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कोविड काल में सरकार का टोटल फेलियर दिखाई दिया। जो समस्यायें इस काल में पैदा हुई वास्तव में यह समस्याएं तो वर्ष 2016 से चलती आ रही हैं और तब भी हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में तीसरे या चौथे पायदान पर ही रहा था। बावजूद इसके भी सत्ता पक्ष द्वारा बहुत बड़ा गुणगान किया जाता रहा। अब मैं प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण के सरकार के जुमले पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। वास्तव में इस जुमले को समझने की आवश्यकता इस प्रकार से है कि सरकार ने यद्यपि 75 प्रतिशत आरक्षण की बात तो कह दी लेकिन इस जुमले ने यह तो सिद्ध कर दिया है कि सरकार का गणित जीरो है क्योंकि अगर 75 को शून्य से गुणा किया जाता है तो इसका रिजल्ट जीरो ही होता है। जब प्रदेश में उद्योग ही नहीं हैं तो 75 प्रतिशत आरक्षण का औचित्य ही क्या है? हम सबको इस बात को सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अमित जी, आपका बोलने का समय पूरा हो गया है, आप प्लीज बैठिए और गौतम जी को अपनी बात रखने दें।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आज मैं सरकार का ध्यान वर्तमान के सबसे बड़े मुद्दे किसान आंदोलन की ओर दिलाना चाहूंगा। अभी बैठे–बैठे मेरे दिमाग में एक बात आई है कि पहले मैं सोचता था कि मोदी जी को तीन कृषि कानून वापिस ले लेने चाहिए और किसानों से फोरन बात कर लेनी चाहिए लेकिन अब मैं सारी बात समझकर इस निचौड़ पर पहुंचा हूँ कि चूंकि सब जानते हैं कि तीन प्रकार की हठ होती है राजहठ, बालहठ और त्रियाहठ। मोदी जी ने राजहठ कर ली है तो निश्चित तौर पर वह नहीं मानेंगे और लगातार कह रहे हैं कि किसान के लिए यह सबसे बढ़िया कानून होंगे जबकि दूसरी ओर किसान इन कानूनों को काले कानून कह रहे हैं। इन सबका मेरे दिमाग में एक ही हल आया है कि हम सभी पार्टी के विधायक सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पास करें और मोदी जी से अनुरोध करें कि इन कानूनों को 3 साल 2 महीने की समयावधि के लिए होल्ड पर रख लें और उसके बाद रेफरैन्डम हो जायेगा तब किसान बता देंगे कि इसमें क्या अच्छा है। 3 साल 2 महीने के बाद चुनाव होगा किसान इनको रिजेक्ट कर देंगे और नई सरकार आ जायेगी। अगर किसान समझेंगे कि इन कानूनों में

अच्छी चीज है तो दोबारा मोदी जी की सरकार आ जायेगी। दूसरी बात जो मैंने सोची है, वह यह है कि मोदी जी को यह काम करने के बाद फोरन किसानों को बुलाना चाहिए और बताना चाहिए कि देखो यह मेरा बजट है, बताओ मैं इस बजट से आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कितना एम.एस.पी. दे सकता हूँ या और क्या बढ़िया काम कर सकता हूँ। इस तरह का फैसला मोदी जी को ले लेना चाहिए और इसके साथ ही फोरन जो आज हमारा पंजाब के साथ ताजा–ताजा भाईचारा बना है, इस भाईचारे के आधार पर एस.वाई.एल. नहर का पानी लाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इन पंजाब के लोगों ने पहले हमारी खुदी हुई नहर को बंद करने का काम किया था। अब भाईचारे के माहौल में उनसे फोरन आग्रह करना चाहिए कि तुम हमारे बड़े भाई हो, हम प्यासे मर रहे हैं हमें पानी दे दो। निःसंदेह इसका कोई न कोई हल निकलकर रहेगा। अभी किरण चौधरी भी कह रही थी और दूसरे सदस्य भी कह रहे थे कि उनके क्षेत्र में पानी नहीं है, उनके क्षेत्र के लोग प्यासे मर रहे है तो ऐसी अवस्था में इस समस्या का केवल और केवल हल एस. वाई.एल. नहर है। अतः इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनेकों काम किए हैं, जिन्हें सदन में गिनाने की जरूरत नहीं है। अनुसूचित जाति के हमारे भाइयों ने बहुत बुरे दिन देखें हैं और सदियों से पिसते आ रहे हैं। जिन्होंने अपनी जिन्दगी पशुओं से भी बद से बदतर व्यतीत की है। इसका समाधान केवल और केवल यह है कि सैंटर और स्टेट गवर्नमैंट बैकलॉग तुरंत प्रभाव से पूरा करे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह जी की सरकार में जब ओ.बी.सी. आरक्षण लागू हुआ था तो अनेक जातियां ऐसी थीं जो बैकवर्ड न होते हुए भी ओ.बी.सी. श्रेणी में शामिल हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि जो असली बैकवर्ड श्रेणी के लोग हैं उन्हें एक प्रतिशत भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि सदन इस चीज की सिफारिश माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्र मोदी जी से कर दे कि 16 प्रतिशत आरक्षण असली बैकवर्ड जाति के लोगों को दे दें और 11 प्रतिशत आरक्षण बैकवर्ड की दूसरी श्रेणी में कर दें। अध्यक्ष महोदय, हमारे मराठा, पटेल, जाट आदि भाई बैकवर्ड श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो उनको 11 प्रतिशत आरक्षण की श्रेणी में शामिल कर लें। अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिये हैं, जिसे कोई भी नहीं ले सकता है। श्री मोदी जी ने

जम्मू कश्मीर में धारा–370 हटाई, जो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। इसके बारे में कहा जाता था कि इसको हटाने से खून की नदियां बह जायेगी। जम्मू कश्मीर से लगभग 4 लाख पंडितों को भगा दिया था और हमारी वहां की बहनों के साथ गलत व्यवहार किया गया था। आज वे लोग शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे पास मौजूदा भाजपा सांसद * के पति * चण्डीगढ़ में रहा करता था, उनका परिवार भी कश्मीरी पंडितों से संबंध रखता था। जब इस विषय पर चर्चा होती थी तो वह रोने लग जाता था। अध्यक्ष महोदय, जो पार्टी जड़ से खत्म हो जाये, वह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वह कभी भी पनपती नहीं है। *कभी भी सपने में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि वे स्वयं और उनकी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री रामकुमार गौत्तम जी ने जो इस सदन के मैम्बर नहीं हैं, अभी उनके नाम लिये हैं, वह रिकॉर्ड न किये जायें।

श्री राम कुमार गौत्तमः अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दूसरा ऐतिहासिक फैसला अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण का लिया था। कांग्रेस पार्टी के नेता *माननीय उच्चतम न्यायालय में पैरवी करते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मन्दिर का निर्माण करवाया, इसके लिए पूरे देश को गर्व होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने कोई में कहा था कि अयोध्या के राम मन्दिर के मसले पर अगले 10 साल तक कोई भी सुनवाई न की जाए । अतः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अयोध्या के राम मन्दिर के निर्माण का फैसला करवाकर बहुत बड़ा काम किया है । (शोर एवं व्यवधान) हमारी मुस्लिम बहनें आज अगर सम्मान से जीवन जी रही हैं तो इसका कारण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं । उन्होंने मुस्लिमों के तीन तलाक

कानून को खत्म कर दिया । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही कीमती बातें सदन में कहना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष सुधा (थानेसर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने गवर्नर ऐड्रेस पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

हूं । एक साल पहले कोरोना महामारी पूरे विश्व में आई थी । मैं कहूंगा कि उस समय हमारी सरकार ने प्रदेश में अच्छा काम किया था । माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हर गरीब को 5 किलोग्राम आटा, 1 किलोग्राम दाल और हर गरीब को 3–5 हजार रूपये देने का काम किया था । बहुत–सी संस्थाओं, पुलिस कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, स्वास्थ्यकर्मियों आदि ने उस समय दिन–रात मेहनत की थी । इसके लिए मैं उनका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । इसके साथ–साथ मैं कहूंगा कि अभी कृषि पर बात हो रही थी । पिछले दिनों प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी ने संसद में कहा था कि एम.एस.पी. था, एम.एस.पी. है और एम.एस.पी. रहेगा अर्थात् एम.एस.पी. कभी खत्म नहीं होगा । हरियाणा प्रदेश में जहां पर गेहूं और पैडी एम. एस.पी. पर खरीदी जाती है वहीं मक्का, बाजरा, जौं, चना, कपास, सूरजमुखी भी खरीदी जाती है । इन सब फसलों की खरीद करने वाला पूरे हिन्दुस्तान में हरियाणा प्रदेश है । मैं कहूंगा कि पूरे हिन्दुस्तान में हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां पर गन्ने का रेट सबसे ज्यादा है । यहां पर गन्ने का रेट 350 रूपये प्रति क्विंटल है । माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किसान के खाते में 6000 रूपये प्रतिवर्ष डालने का काम किया है । इसके अलावा उन्होंने देश में प्रधानमंत्री 'फसल बीमा योजना' को शुरू करके किसान को फसल में होने वाले नुकसान के समय एक सहारा दिया है । पंजाब में आलू की कांट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती थी और आज भी है । आज अगर कृषि यंत्रों पर किसी ने 80 प्रतिशत सब्सिडी देने का काम किया तो यह काम हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। अभी सदन में किसान की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि हमको किसान की डैफीनेशन नहीं पता है । मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी किसान हैं। वे 3 एकड़ भूमि में खेती करते हैं । यहां पर हमारी पार्टी के अनेक माननीय सदस्य उपस्थित हैं जो खेती–किसानी करते हैं । माननीय सदस्य श्री घनश्याम दास जी बहुत बड़े क्षेत्र में खेती करते हैं, माननीय सदस्य ईश्वर सिंह जी 45 एकड़ में खेती करते हैं, माननीय सदस्य श्री हरविन्द्र कल्याण खेती करते हैं, माननीय सदस्य श्री कंवर पाल जी खेती करते हैं । उपर्युक्त सभी माननीय सदस्य खेती करते हैं । (शोर एवं व्यवधान) मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि किसान की डैफीनेशन क्या है ? इसके अलावा मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये माननीय सदस्य किसान नहीं हैं ? (शोर एवं व्यवधान) हम सब किसान हैं । हमें सबकी चिन्ता है । आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय

श्री नरेन्द्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी ने किसानों की जितनी चिंता की है उतनी शायद अन्य किसी ने भी नहीं की है । अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि आदि के कारण किसान की फसल नष्ट होती है तो किसानों को उसकी फसल का सबसे ज्यादा मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह काम किया है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब के बठिंडा शहर से चलने वाली एक ट्रेन को 'कैंसर एक्सप्रैस' कहा जाता है। इसका कारण यह है कि वहां की भूमि में पेस्टीसाइड्स का इतना प्रयोग किया गया है कि उस जमीन में पैदा होने वाली फसल से इंसानों में कैंसर जैसी घातक बीमारियां पनपती हैं। पंजाब के बठिंडा से निकलने वाली उस ट्रेन में यात्रा करने वाले अधिकतर लोगों को कैंसर की बीमारी होती है। हमारे गवर्नर साहब भी जैविक खेती करते हैं और उनकी फसल आम फसल से 3 गुना ज्यादा रेट पर भी बिकती है। हरियाणा में गेहूं बहुतायत में पैदा होता है लेकिन आज के दिन हम सभी एम.पी. गेहूं का आटा खाना पसन्द करते हैं । हम चाहते हैं कि हमारे लोग अच्छी क्वॉलिटी की गेहूं खाएं और उनको उनकी गेहूं की फसल का अच्छा मूल्य मिले। हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने पढ़ी–लिखी पंचायतें बनाने का काम किया है। पहले मैं गांवों में जाकर देखता था। गांवों में जो डेरे हैं, उन तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होती थी। अब हमारी सरकार ने वहां तक सड़के बनवाने का काम किया है। हमारी सरकार ने पहली बार 4–4 एकड़ में कम्यूनिटी सैंटर बनाने का काम किया है। माननीय गवर्नर साहब के अभिभाषण में एलिवेटिड ट्रैक बनाने की बात की गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में 225 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटिड ट्रैक का काम शुरू हो चुका है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जी की भूमि पर कुरूक्षेत्र में सरकार ने 150 करोड़ रुपये की लागत से कृष्णा सर्किट बनाने का काम किया है। अगर विपक्ष का कोई माननीय सदस्य वहां पर जाकर देखना चाहे तो इन विकास कार्यों को देख सकता है। हमारी सरकार ने हमारे हल्के में गवर्नमैंट कॉलेजिज और नर्सिंग कॉलेजिज बनावाए हैं। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले की सरकारों ने वहां पर इस प्रकार के कार्य नहीं करवाए। हमारे वहां पर दो शिफ्टों में स्कूल लगता था और उसमें हमारी बेटियां पढ़ने के लिए जाती थी। आज तक वहां पर किसी ने उनके लिए स्कूल बनवाने का

काम नहीं किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके लिए स्कूल बनवाने का काम किया है। हमारी सरकार ने मेरे हल्के में गर्ल्ज कॉलेज बनाने का काम किया है। पहले मेरे हल्के में 50 बैड का हॉस्पिटल था और वह जर्जर हालत में था, परन्तु हमारी सरकार ने 100 बैड का हॉस्पिटल बनवाने का काम किया है। पहले हमारे कुरूक्षेत्र में टूरिस्ट्स आते थे तो वहां सड़कों पर 4–4 फुट के गढ्डे होते थे, परन्तु आज आप वहां पर जाकर देखेंगे तो बहुत अच्छी सड़के बनवायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे ब्रहम सरोवर का पानी रूका हुआ था, उसको भी हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक करवाने का काम किया है। इसी तरह से शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा वहां पर विकास कार्य करवाए गये हैं। एक नाले पर 60 वर्षों से कब्जा था। हरियाणा सरकार द्वारा उसको अमरूत योजना के तहत 27 करोड़ रुपये की लागत से बनवाया जा रहा है। पहले हमारे वहां पर सीवरेज की व्यवस्था नहीं थी, परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 सीवरेज ट्रिटमैंट प्लांट बनवाने का काम किया है। मैं, अन्त में यही कहना चाहूंगा कि हमारे कुरूक्षेत्र में बाई पास का निर्माण करवाया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैंने कल भी उनसे अनुरोध किया था कि हमारे कुरूक्षेत्र के बाई पास का निर्माण करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री वरुण चौधरी (मुलाना) (एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज 100 दिन से अधिक का समय हो गया है, परन्तु आज भी किसान आंदोलनरत हैं। वे अपने खेतों को छोड़कर सड़कों पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनकी समस्या को गम्भीरतापूर्वक सुना जाए और उनकी समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि गन्ने की फसल की कीमत 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ायी गयी है। इसी तरह से अन्य फसलों के दाम 10 रुपये से लेकर 20 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाए गये हैं और गेहूं के दाम 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए गये हैं। यह कहा गया है कि इसके माध्यम से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन सा गणित है जिसके माध्यम से 2 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत कीमत बढ़ाने से आय दोगुनी होगी। अभी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो होने वाली है, परन्तु सरकार के पास बारदाना तक नहीं है और

न ही उसको खरीदने की कोई प्रक्रिया शुरू की गयी है। सरकार ने पिछले साल आढ़तियों के ऊपर दण्ड लगाया था। उनको कहा गया कि आपने किसानों के खातों में देरी से भुगतान किया है। सरकार द्वारा यह बताया गया था कि यह दण्ड जल्द से जल्द किसानों के खाते में डाला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि अब सरकार अपने ऊपर कितना दण्ड लगाएगी क्योंकि उन बातों को एक साल से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु अभी तक किसानों के खातों में वह पैसा नहीं डाला गया है।

16:00 बजे

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और इस बीच सरकार जब हरियाणा में ''उद्यम एवं रोजगार नीति'' को लाने का काम किया गया है परन्तु यह बात सुनने में तो अच्छी लगती है क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वह 5 लाख नौकरियों का सृजन करना है और एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इसी प्रकार की नीति वर्ष 2015 में भी लाई गई थी। उसका भी उद्देश्य ऐसा ही था कि 4 लाख से ज्यादा नौकरियों का सृजन करना और 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना आदि। इस ''उद्यम एवं रोजगार नीति'' का क्या हुआ? मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि जब पांच साल बाद इस ''उद्यम एवं रोजगार नीति'' की जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि 32030 बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिली, जिसका प्रतिशत के हिसाब से देखा जाये तो लगभग 8 प्रतिशत ही बनता है और अगर निवेश के मामले में प्रतिशत देखा जाये तो लगभग 14 प्रतिशत बनता है। इस बात से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यह नीति असफल साबित हुई। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती? हमें पांच साल बाद इस बात का पता चलता है कि उद्योग नीति तो असफल हो गई। अब आप ही बतायें कि जो सरकार द्वारा नीति बनाई गई है हम उस पर कैसे उम्मीद करें कि ये सफल होगी? जब तक हम पिछली नीति की जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ विधानपालिका में डॉ. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने का काम किया जाता है और दूसरी तरफ कार्यपालिका में उन्हीं के बनाये हुए श्रम कानूनों को तहस–नहस करने का काम किया जाता है। नई उद्योग नीति में कहा गया है कि जो भी बड़े उद्योग हरियाणा में आयेंगे उनके ऊपर मिनिमम बेजिज के अलावा कोई भी श्रम कानून लागू नहीं होगा। अध्यक्ष

महोदय, इस महान सदन में दिनांक 05.03.2021 को भी चर्चा हुई थी। यह मामला भी कंकरेंट लिस्ट का है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बारे में क्या माननीय राष्ट्रपति महोदय से परमीशन ली गई है? इस प्रकार से तो हरियाणा के अंदर श्रमिकों का शोषण होगा और बंधुआ मजदूरी शुरू हो जायगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसे रोका जाये इस तरह का कार्य न किया जाये। सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों को अलग–अलग विभागों में स्थानातरित करने का काम किया जा रहा है और यह तब हो रहा है जब हरियाणा में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं इस बात का क्या अर्थ निकालूं कि हरियाणा प्रदेश को पुलिस राज्य बनाने की ओर कदम बढ़ाये जा रहे हैं? इस महान सदन में कल हम सब ने ''अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' के रूप में मनाया है। जो हमारा ''राष्ट्रीय महिला आयोग'' है। उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि वर्ष 2020 में सबसे ज्यादा अगर शिकायतें पूरे देश में से कहीं से आई है तो वह हरियाणा प्रदेश से आई हैं। यह हमारे लिये कितने दुख और चिंता की बात है। अध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा पुलिस एक्ट है उसका सैक्शन 59 इस प्रकार है –

> "**State Police complaint Authority. -** The State Government shall, within three months of the commencement of this Act, establish at the State Level, a Police Complaint Authority, …."

The word, "shall" is mentioned परन्तु आज तक उसे नहीं बनाया गया है। उसका कार्य जनता की सुनवाई करना है। अगर आम जनता को पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से कोई समस्या है या उनसे किसी को कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत ''स्टेट पुलिस कम्प्लेंट अथॉरिटी'' में की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन को यह बात बताना चाहूंगा कि पुलिस द्वारा निहत्थे किसानों को जान से मारने एवं उनकी हत्या करने के प्रयास के मामले दर्ज किये गये हैं। क्या सरकार द्वारा आम जनता की आवाज को दबाने का कार्य नहीं किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा नम्बर 153 में लिखा गया है कि पुलिस विभाग के लिए 630 सरकारी वाहन खरीदें जायेंगे। जो कि मैं आपके संदर्भ में भी लेकर आया हूं। ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि कार्यपालिका, विधान पालिका को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा इस तरह के बार–बार कार्य किये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इस महान सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह 630 वाहन अढ़ाई महीने पहले खरीदे जा चुके हैं खुद

मुख्यमंत्री महोदय इनका निरीक्षण भी कर चुके हैं। इन पर अढ़ाई–अढ़ाई किलो धूल जमी हुई है और सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये अभी खरीदे जाने हैं। क्यों इस महान सदन को गुमराह किया जा रहा है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसकी इन्क्वॉयरी करवाई जाये। अगर हो सके तो इसमें अमैंडमैंट भी की जाये। सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण की बात कर रही थी। मैंने इस बारे में पिछली सरकार के 5 साल की जानकारी भी मांगी थी क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए जितने बजट का प्रावधान किया जाता है उतना लगाया नहीं जाता है। इसके विपरीत दूसरे विभागों के लिए सरकार द्वारा सप्लीमैंट्री ग्रांट्स लाई जाती हैं लेकिन अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए जो पैसा निर्धारित होता है वह भी नहीं लगाया जाता। सरकार ने अनुसूचित आयोग को भंग करने में तो देर नहीं लगाई लेकिन आज तक अनुसूचित आयोग का गठन नहीं किया गया है। हम कैसे इस बात को मान लें कि वर्तमान हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए संवेदनशील है? बिजली उपभोक्ताओं के लिए कहा गया था कि जितनी भी तारें घरों के ऊपर से निकलती हैं उनको हटाया जायेगा। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार की यह योजना कहां गई? अभिभाषण में यह बताया गया है कि नियामकों को 640 करोड़ 51 लाख रूपये का लाभ हुआ है। सरकार को यह भी देखना है कि जनता को कितना लाभ हुआ है? प्रदेश के गरीब बिजली उपभोक्ताओं ने एल.ई.डी. बल्ब भी लगा लिये लेकिन इसके बावजूद भी उनका बिजली बिल दोगुणा–तिगुणा होता जा रहा है। मेरा सरकार से यही कहना है कि सरकार को यह देखना चाहिए कि बिजली उपभोक्ताओं का कितना फायदा हुआ है न कि यह देखना चाहिए कि नियामकों का कितना फायदा हुआ है? अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री बलराज सिंह कुण्डु (महम) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मैं सभी सीनियर साथियों और अपने साथ वालों का भी वक्तव्य सुन रहा था। मैंने सभी के अलग–अलग वक्तव्य सुने। मैंने इस अभिभाषण में जो देखा कि किस प्रकार से पूरे प्रदेश को पूर्ण रूप से खुशहाल दिखाया गया है। सरकार की कार्यशैली का बड़ा सुन्दर वर्णन अभिभाषण के अंदर किया गया है।

उसी के संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि अभिभाषण में नम्बर एक पर जो कहा गया है कि मैं उसी एक नम्बर पर किसान की बात करना चाहता हूं। किसान की आय दोगुणी करने की बात करता हूं। जिस प्रकार से सरकार ने किसान की आय को दोगुणा करने का काम किया है उसका जश्न मनाने के लिए इस प्रदेश का अन्नदाता दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है। किसान अपनी आय को दुगुणा करने से इतना ज्यादा खुश है कि खुशी के मारे 200 किसान अपनी जान दे चुके हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इससे खुश होकर खुदकुशी कर चुके हैं। बहुत से किसान दिल्ली जाते–जाते रास्ते में एक्सीडैंट्स में मर चुके हैं। मैं सरकार की इस कार्यशैली के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं कि सरकार ने किस प्रकार से किसान की आय को दुगुणा और किसान को खुशहाल करने का इतना सुन्दर काम किया है? सरकार ने पानी को बचाने के लिए बड़ी सुन्दर व्यवस्था की है। जो 45 दिन में 8 दिन के लिए नहर में पानी आता था सरकार ने उसको कम करके तीन दिन कर दिया क्योंकि पहले 8 दिन इतना पानी नहीं आता था जितना तीन दिन में आ जाता है और ये सरकार किसान को दे देती है। किसानों की फसलों में पानी भरने लगता है। पानी के लिए की गई सरकार की इस व्यवस्था को मैं सलाम करता हूं। सरकार ने जिस प्रकार से प्रदेश से बेरोजगारी को दूर करने की बात की उसका भी कोई जवाब नहीं है। आज सदन में सत्ता पक्ष के एक भाई ने बताया कि आज युवाओं को रोजगार देने में पूरे देश में नम्बर एक पर है। कांग्रेस के साथी सरकार पर नौकरी बेचने का आरोप लगाते थे। सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी कि नौकरी देना बंद करके ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी। हरियाणा वाले सरकार पर ब्लेम लगाते तो सरकार ने बाहर वालों को नौकरी देनी शुरू कर दी। मैं सरकार की इस प्रकार की कार्यशैली को भी सलाम करता हूं। सरकार ने इस प्रदेश को महंगाई से बचाने का इतना अच्छा काम किया कि पैट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर आज कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसके लिए भी सरकार की कार्यशैली को सलाम करता हूं। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था का तो कमाल है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी उसकी चर्चा कई दिन पहले कर चुके हैं। इस बारे में अखबारों में बहुत बड़ा लेख मैंने पढ़ा था। जिस प्रकार से उन्होंने अपने डी.जी.पी. की तारीफ की थी उसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके लिए भी प्रदेश सरकार की कार्यशैली को सलाम करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश का किसान

भूखा–नंगा सड़कों पर बैठा हुआ है और जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने उसके खाने पीने की व्यवस्था की है, उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, उसके लिए पीने के पानी की व्यवस्था की है, जिस प्रकार से दीवार खींचकर, कांटेदार तार लगा कर, खाइयां खोदकर तथा किसान पर वाटर कैनन चलवाने की व्यवस्था की है उसके लिए मैं सरकार को सलाम करता हूं। आज जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के हर सदस्य ने सरकार की तारीफ की है, आज जिस प्रकार से सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, बिजली विभाग में भी जो बहुत अधिक घाटा था जिसको कांग्रेस सरकार लूट कर खा गई वह भी आज फायदे में आ गया है लेकिन जब मैं हकीकत देखता हूं तो पता चलता है कि कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, उसके लिए मैं आपकी सरकार की कार्यशैली को सलाम करता हूं। आज जिस प्रकार से आउटसाईडर को नौकरियां देकर हमारी सरकार के सहयोगी हमारे साथी जो सरकार में आने से पहले आंदोलन करते थे, बाहर वालों को नौकरियां देने पर जिन्होंने सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया था आज वे सरकार की तारीफ करते हैं। मेरे प्रदेश के युवाओं को उन नौकरियों के काबिल नहीं बताते और कहते हैं कि उनके पास वे डिग्रियां नहीं है। आज जिस प्रकार से डोमिसाइल बनवाने के लिए पहले जहां हरियाणा का 15 साल का रिहायशी होना जरूरी था उसको घटा कर बाहर वालों के लिए आधा समय करने का जो काम किया है उसके लिए मैं हरियाणा सरकार को सलाम करता हूं। मैं एक बात और आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमारे जो भाजपा के सदस्य हैं इनको आज अपनी ए.सी.आर. लिखवानी है क्योंकि मंत्रिमण्डल में चेंज होने वाला है इसलिए इनको दोष मत दिया करो, इनका बोलना बनता है। मैं हमारे साथियों को दुआ देता हूं कि अपनी ए.सी. आर. गुड नहीं वैरी गुड लिखवाएं ताकि आपका नाम मंत्रिमण्डल में आ सके। आप इनसे बुरा मत माना करो, ये हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सरकार की उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। माननीय मंत्री जी सुबह जिस प्रकार से जवाब दे रहे थे, मैं ऐसी सरकार का धन्य हूं। निश्चित रूप से जैसे हमारे कई भाइयों ने बताया कि भाजपा सरकार के स्वागत के लिए गांवों–गांवों में अड्डों पर बोर्ड लगा दिये हैं। उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं। जिस प्रकार से विवाह–शादियों में भी आज इन इतना ज्यादा स्वागत हो रहा है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। जो जश्न पिछले तीन महीने से किसान दिल्ली के बोर्डर पर मना रहा है पूरा विश्व उस बात को जानता है कि आपकी सरकार की

उपलब्धियों को देख कर ये अन्नदाता कितना खुश हो कर आपको दुआएं दे रहा है, उसका परिवार दुआएं दे रहा है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इसके लिए पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूं और आपको एक बात का आश्वासन भी देता हूं कि ये तीन साढ़े तीन साल का समय गिनती के दिन हैं। आपका वैलकम करने के लिए इस प्रदेश और देश की जनता तैयार बैठी है। आपका बहुत बड़ा वैलकम होगा उसके लिए भी मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूं। अंत में मैं दो शब्द अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए भी कहना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जब से विधायक बन कर आया था तो मेरे महम क्षेत्र का एक मात्र सामान्य हॉस्पिटल जिसकी हालत आज बिल्कुल जर्जर हो चली है जिससे रोहतक 35 किलोमीटर पड़ता है, उसको बनवाने का काम सरकार करे। वह मेरे काम नहीं आता बल्कि उस हल्के की जनता के काम आता है। इसी प्रकार से मैंने अपने महम में लड़कियों के लिए कॉलेज बनाने की मांग रखी थी उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारी बहनों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए महम में गर्ल्स कॉलेज खोला जाए। धन्यवाद।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों द्वारा अपने संबोधन में कई तरीके की बातें बताई गई हैं। जैसे कुण्डू साहब ने ठेकेदारी प्रथा के बारे में बताया लेकिन यह ठेकेदारी प्रथा कांग्रेस के समय से चलती आ रही है। जहां तक बाहर के लोगों को नौकरी देने की बात है। आप ये बता दीजिए कि अगर आप मैरिट पर नौकरी देंगे तो बाहर के लोगों को कैसे रोकेंगे? आपने 10 साल सरकार चलाई क्या आपके समय में इस तरह से नौकरी नहीं दी गई?(शोर एवं व्यवधान) अभी गोगी जी ने कहा है कि हमारी सरकार तो केवल घोषणाएं कर रही है। मैं कहता हूं कि आपने 10 साल में क्या किया था? (शोर एवं व्यवधान) अमित सिहाग जी ने कहा कि किसान मापदंड है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, आप बैठ जाईये। मंत्री जी बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, अमित सिहाग जी ने कहा है कि एम.एस.पी. की केवल घोषणा नहीं चाहिए एम.एस.पी. इम्प्लीमैंट भी चाहिए। बी.बी. बत्तरा जी ने कहा कि इनकी सरकार ने कानून बना दिया था कि किसान अपनी फसल को एम.

एस.पी. से नीचे नहीं बेच सकते। अभी मैं इनके समय का डाटा बताउंगा। यह मुझे बताएं कि इन्होंने क्या–क्या काम किये हैं? वर्ष 2013–14 में इनकी सरकार थी। इनकी सरकार ने उस समय 58.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी जबकि हमारी सरकार ने उतने समय में 54 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी। (शोर एवं व्यवधान) यह किसान की आमदनी के बारे में जानकारी ले रहे थे तो उसके बारे में मैं इनको बताउंगा कि हम किसान की आमदनी को दुगुनी कैसे करेंगे?(शोर एवं व्यवधान) इन्होंने गेहूं और धान को छोड़कर न बाजरा खरीदा, न सरसों खरीदी, न मूंग खरीदी, न मक्का खरीदा, न सूरजमुखी खरीदी इन फसलों का इनकी सरकार ने अपने समय में एक दाना भी नहीं खरीदा। फिर यह एम.एस.पी. कहां से मांग रहे हैं? एम.एस.पी. को अगर इम्प्लीमैंट कर रही है तो वह हमारी सरकार कर रही है। इन्होंने कभी एम.एस.पी. को इम्प्लीमैंट नहीं किया।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, प्लीज अब आप बैठ जाईये।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं हाऊस के बाहर भी इनसे एम.एस.पी. के विषय पर बात करने के लिए तैयार हूं।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पानी की किल्लत पर कालिंग अटैंशन मोशन भी दिया है और इतनी बड़ी–बड़ी चिट्ठियां भी दी हैं। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत भारी किल्लत है। (शोर एवं व्यवधान) मैं ये फोटो लेकर आई हूं जिससे पता चलता है कि हमारे वहां पानी की कितनी भारी किल्लत है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप सुबह से एक घंटा पानी पर ही तो बोल रही थी। सुबह ये फोटो कहां थी? (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्रीमती किरण चौधरी जी ने वैल में आकर कुछ फोटो दिखाए।)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप ये फोटो मंत्री जी को दे दीजिए। प्लीज, अब आप अपनी सीट पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश जरावता (पटौदी) (एस.सी).: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहीम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका और पूरे सदन का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 1966 के बाद हरियाणा विधान सभा के प्रवेश द्वार पर आपने बाबा साहब डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की है और हमारे कार्यकाल में की है। इस बात

के लिए हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। माननीय स्पीकर महोदय, मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा है लेकिन जहां भी एक–दो जगह मेरी निगाह पड़ी वहां बहुत ही अच्छी–अच्छी बातें मिली हैं। कोरोना काल के दौरान एक विषय आया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर वर्ग के बच्चों के लिए 8 लाख से ज्यादा मुफ्त टैबलेट देने का निर्णय लिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उसकी वजह से आज गरीबों के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिला है।(शोर एवं व्यवधान) बहन जी, मैं आपकी बात पर भी आ रहा हूं। आप बहुत वरिष्ठ हैं। जैसा आप बोलती हैं वैसा हमें भी बोलने दीजिए। हम आप से सीख रहे हैं। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक समय ऐसा भी था जब हमारे गांव के अन्दर हमारी माताएं–बहनें दो–दो किलोमीटर से पानी भरकर लाती थी लेकिन आज माननीय प्रधान मंत्री जी ने उस बात को समझा और पूरे देश के अन्दर वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर तक नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार ने वर्ष 2022 तक हरियाणा के प्रत्येक घर में नलकूप लगाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करता हूँ जिसने एक नई पहल करके के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे के साथ ऑर्बिटल रेल कोरिडोर बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस प्रोजैक्ट के लिए 5618 करोड़ रूपये का बजट मंजूर किया। हरियाणा सरकार के प्रयास से ही रेवाड़ी और गुरूग्राम को कनैक्ट करने वाले रोड के लिए जमीन एक्वॉयर करने व दूसरी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए नैशनल हाइवे बनाने की अवधारणा को मूर्त रूप देने का काम हुआ। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज से पहले पटौदी विधान सभा क्षेत्र मानेसर को चंद लोगों ने केवल मात्र लूटने का ही काम किया था। पूरे देश में मानेसर उद्योग की दृष्टि से नम्बर वन पर था लेकिन उस मानेसर को लूटते हुए इस क्षेत्र को बदनाम करने का काम किया गया। जिस तरह से भी जिसके हाथ जो लगा चाहे प्रोपर्टी में लूटा, चाहे इंडस्ट्री में लूटा या चाहे किसी और क्षेत्र में लूटा, जमकर लूटा गया लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी रहमत दिखाते हुए मानेसर को निगम बनाकर इसको देश–प्रदेश के साथ विश्व के पटल पर भी चमकाने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत

धन्यवाद व आभार प्रकट करना चाहूंगा। कोरोना काल के दौरान बेरोजगारी निश्चित तौर पर बढ़ी है और हर वर्ग को बड़ी तकलीफों का भी सामना करना पड़ा है लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति से उभारने के लिए एम.एस.एम.ई. में बढ़े बदलाव करते हुए माइक्रो यूनिट के लिए पूर्व में नियत 10 लाख रूपये के प्रावधान को बढ़ाते हुए 1 करोड़ रूपये करने का काम किया गया और इतना ही नहीं वर्ष 2014 तक मात्र 25 हजार रूपये ऋण एक किसान या व्यापारी को बगैर कोलेटरल सिक्योरिटी के मिलता था उसको हमारी सरकार ने बढ़ाकर 2 करोड़ रूपये देने का काम किया है ताकि बेरोजगार लोग इंडस्ट्री लगाकर आत्म निर्भर बन सकें। अभी हमारी बहन गीता जी गुरू रविदास जी का एक दोहा पढ़ रही थी, अगर वास्तव में बहन जी चाहती है कि वैसा राज हो, जैसा कबीर साहब, गुरू रविदास जी या बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे तो मेरा निवेदन है कि बहन जी आप हमारी तरफ आ जाइये, वह सब कुछ मुमकिन हो जायेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बहन जी, आपकी तरफ न तो बाबा साहब की इज्जत हुई, न जगजीवन राम जी की इज्जत हुई और ज्यादा न कहें तो आपकी पार्टी के जो हरियाणा के पूर्व प्रधान थे अशोक तंवर जी, उनकी भी इज्जत नहीं हुई थी। आप हमारी तरफ आ जाइये आपको मान–सम्मान सब कुछ मिलेगा क्योंकि हमारी पार्टी केवल इस मकसद से काम करती है कि किस प्रकार से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उपर उठाया जाये। मुझे आज भी वह दिन याद हैं जब हमारी मातृशक्ति इंतजार किया करती थी कि कब अंधेरा होगा और वे शौच के लिए बाहर जायेंगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने व माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दर्द को समझने का काम किया और घर–घर शौचालय बनाने का काम किया। घर में शौचालय नहीं होने के कारण हमारी मातृशक्ति को न जाने कितनी–कितनी प्रकार की पेट की बीमारियों से जूझना पड़ता था। हमने वह वक्त भी देखा है जब हमारी मातृशक्ति चूल्हे में फूकनी से फूंक मार–मार कर खाना बनाया करती थी। धूएं के कारण उसकी आंखे खराब हो जाती थी। इस मंजर को मैंने अपनी आंखों से देखा है और ऐसे माहौल में हमने चूल्हे के आगे बैठकर खाना भी खाया है लेकिन कितनी विडम्बना की बात है कि उस वक्त जब हमारी मातृशक्ति इतना नरकीय जीवन जी रही थी, कांग्रेस पार्टी के शासन काल के इस दौर में एम.पी. तथा एम.एल.ए. की चिट पर गैस कनैक्शन मिला करते थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति के इस दर्द को समझते हुए उज्ज्वला योजना के तहत घर–घर तक एल.पी.जी. गैस

पहुंचाने का काम किया। इसके अतिरिक्त सदन में किसानों के लिए बहुत कुछ कहा गया। सरकार द्वारा उनके खातों में दिए गए 2000 रूपये के बारे में भी बात कही गई। संदर्भित विषय पर अब बात चली है तो मैं भी इस विषय पर कहना चाहूंगा कि देश को आगे बढ़ाने में किसान के साथ–साथ मजदूर का भी अहम रोल होता है। हरियाणा में 16 लाख किसान हैं लेकिन यह भी जानने की आवश्यकता है कि यहां पर 32 लाख भूमिहीन खेतीहर मजदूर भी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको भी अन्य मजदूरों की तरह अर्थात् रजिस्टर्ड मजूदरों को जो सुविधाएं मिलती हैं, उसी प्रकार से सुविधाएं मिलनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, पटौदी के अंदर बिलासपुर से कुलाना रोड को चारमार्गीय किया जाये। इस प्रोजैक्ट में जमीन अधिग्रहण का भी कोई इशू नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, फर्रूख नगर, और मानेसर दोनों जगहों पर पब्लिक का आवागमन ज्यादा रहता है, इसलिए इन दोनों को सब–डिवीजन बनाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री बलबीर सिंह (इसराना) (एस.सी.): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र किया गया है कि भवनों के निर्माण के लिए गरीब परिवारों की बहुत मदद की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस की सरकार थी तो तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार ने इन्दिरा आवास योजना के तहत एस.सी/बी. सी. व गरीब आदमियों के लिये मकान बनाये थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब वह स्कीम ही बंद कर दी। इसी तरह से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार के समय महात्मा गांधी आवास योजना के तहत करीब 4 लाख प्लॉट जरूरतमंद व्यक्तियों को दिये गये थे। इस सरकार ने इस स्कीम को बंद करके गरीब आदमियों का हक छीनने का काम किया है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान बहुत जरूरतमंद परिवारों की मदद सरकार ने की है। कोविड मरीज बड़े–बड़े नेताओं का इलाज तो बड़े–बड़े अस्पतालों में हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, जिन डॉक्टर्ज व अन्य महकमों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने कोविड–19 महामारी के दौरान कोविड मरीजों की सेवा की थी उनमें से कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों की भी कोरोना से

संक्रमण की वजह से मौत हो गई थी। मेरे हल्का इसराना, ब्लॉक मतलौडा, गांव अटावला में सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये भी ड्यूटी लगाई थी। श्रीमती कविता पत्नी श्री सुरेश कुमार, आशा वर्कर थी, उसे जब इस वैश्विक महामारी से बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया तो बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूँ कि जिन परिवार के सदस्यों की इस कोरोना वैक्सीन टीका लगवाने के कारण मौत हुई है, क्या सरकार उन परिवारों को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देगी? उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हरियाणा में स्थित विभिन्न कंपनियों, समितियों, न्यासों, लिमिटेड लाइब्लिटी पार्टनरशिप फर्म, भागीदारी फर्म आदि के तहत रोजगार में हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की बात कही है लेकिन इसमें भी सरकार ने एस.सीज/बी.सीज कैटेगरी का कोई भी कोटा निर्धारित नहीं किया। हरियाणा डोमिसाईल की अवधि 15 साल से घटाकर 5 वर्ष कर दी है, मेरे ख्याल से हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसने डोमिसाईल की अवधि का पीरियड कम किया है। कोविड–19 महामारी के दौरान गरीब आदमी बहुत परेशानियों से गुजर रहा है क्योंकि कारखाने, फैक्टरी व उद्योग धंधे बंद होने के कारण उनका रोजगार चला गया है। हरियाणा सरकार ने ऐसी स्थिति में हरियाणा डोमिसाईल की अवधि घटाकर गरीब आदमी विशेषकर एस.सीज/बी.सीज कैटेगरी के लोगों को हानि पहुँचाने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सदन को 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना की सच्चाई के संबंध में कहना चाहता हूँ। हल्का इसराना, बरौदा और गोहाना के लगभग 80–90 गांव इन्दिरा गांधी ड्रेन नं0 8 पर आधारित हैं। जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उस समय सभी गांवों को इस ड्रेन से सिंचाई के लिए पानी दिया जाता था और पानी की कोई कमी फसल के लिए नहीं रहती थी । जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी है तब से इस ड्रेन में कभी भी फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा गया । केवल बरौदा विधान सभा क्षेत्र के उप–चुनाव में वोट पाने के लिए पानी छोड़ा गया था । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने इस ड्रेन में सिंचाई के लिए पानी चलवाया था अब भी इसी प्रकार से ड्रेन में पानी चलवाया जाए । इसके अलावा पानीपत से वाया मतलौडा–सफीदों जो सड़क है उस पर बहुत ज्यादा

ट्रैफिक चलता है और सड़क कम चौड़ी होने से वहां पर एक्सीडैंट हो जाते हैं जिससे काफी मौतें भी हो जाती हैं । अतः मेरा निवेदन है कि इस सड़क को फोर लेन किया जाए । यह बहुत ही जरूरी है । इसके अलावा पानीपत से गोहाना की जो सड़क है उस पर भी जो गांव लगते हैं उन पर भी स्पीड ब्रेकर बनवाये जाएं क्योंकि गाड़ियों की तेज स्पीड की वजह से कई बार एक्सीडैंट हो जाते हैं जिससे काफी मौतें भी हो जाती हैं । स्पीड ब्रेकर बनने के बाद वहां पर होने वाले जान–माल का नुकसान टल जाएगा । उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा व जजपा के सदस्यों द्वारा बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने किसानों का सारा गन्ना हरियाणा की शुगर मिलों में डलवाया जबकि गन्ना किसानों का जो गन्ना हरियाणा में नहीं लिया गया उसको उन्होंने मजबूर होकर यू.पी. और पंजाब की शुगर मिलों में पहुंचाया। आज तक किसानों को उनकी पेमेंट नहीं मिली है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि गन्ना किसानों की जो बकाया पेमेंट है उसे शीघ्रातिशीघ्र दिया जाए । इसके अलावा अनुसूचित जातियों के लिए बैकलॉग के तहत बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हैं लेकिन इस सरकार ने आज तक बैकलॉग की सीटें भरने का कोई प्रयास नहीं किया है । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों की जितनी सीटें रिक्त पड़ी हैं उनको जल्दी–से–जल्दी भरा जाए । आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री नरेन्द्र गुप्ता (फरीदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । वैश्विक महामारी के समय में हमारी सरकार और अधिकारियों ने पूरे हरियाणा में इस महामारी से निपटने के लिए जिस तत्परता से कार्य किया उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । विशेष रूप से पुलिस के सभी कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, सामाजिक संस्थाओं और सभी एन.जी.ओज. ने तत्परता से कार्य किया है । इन सब ने इस महामारी के असर को हरियाणा में कम से कम करने में अपना पूरा योगदान दिया है । इनके योगदान से इस महामारी के समय में व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही । मैं सभी संस्थाओं को पुनः धन्यवाद देता हूं । कोरोना काल में हमारे प्रदेश में आये हुए जो दिहाड़ीदार–मजदूर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्ज थे उनका रोजगार छिन गया था । उस समय अप्रैल–जून, 2020 तक उन सबको 'सामाजिक वितरण प्रणाली' के तहत आवश्यक वस्तुएं मुफ्त में उपलब्ध करवाई गई थी । इसके लिए मैं सरकार को

बधाई देता हूं । सरकार ने 17 लाख गरीब परिवारों को 3–5 हजार रूपये दिए जिससे उनका घर आराम से चल सके । यह कुल राशि 730 करोड़ रूपये बनती है। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं । मैं गैर–संगठित क्षेत्र के 70 हजार से अधिक श्रमिकों को 35 करोड़ रुपये से ऊपर राशि देने के लिए भी सरकार को धन्यवाद देता हूं । हरियाणा में औद्योगिक क्रांति की बहुत ज्यादा संभावना है । हमें प्रदेश में एक लाख करोड़ रूपये के निवेश के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करना है । हरियाणा में उद्यम और रोजगार नीति, 2020 के तहत निवेश, सब्सिडी, कम ब्याज दर, स्टाम्प ड्यूटी रिफंड, कम बिजली शुल्क जैस आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं । इससे हमें उम्मीद है कि हम हरियाणा प्रदेश को कृषि के साथ–साथ औद्योगिक रूप से बहुत उन्नत कर पाएंगे । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के अनुसार काम करते हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश की सभी 90 विधान सभा क्षेत्रों में समान रूप से 'मॉडल संस्कृति स्कूल्ज' की स्थापना करने की घोषणा की है। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के अनुसार सभी 90 माननीय सदस्यों को विधायक निधि के तहत 5–5 करोड़ रुपये के विकास कार्य करने नीति बनायी है।

श्री शमशेर सिंह गोगी: उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्स: उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद: उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेन्द्र गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के माननीय सदस्य ने इस बारे में एक प्रश्न भी पूछा था और सरकार ने उसके जवाब में बताया था कि उन्हें कितने रुपये की ग्रान्ट दी जा चुकी हैं।

श्री कुलदीप वत्स: उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

श्री नरेन्द्र गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, सदन में सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि सभा में या तो प्रवेश न किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए क्योंकि वहां पर न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। विपक्ष के माननीय सदस्यों को झूठ बोलने के अलावा कुछ कहना आता ही नहीं है। विपक्ष के माननीय सदस्य कितना पाप के

भागी बनना चाहते हैं? माननीय सदस्य श्री वरुण चौधरी जी के क्वैश्चन के रिप्लाई में बताया गया था कि उनके 5 करोड़ रुपये में से 80 लाख रुपये आबंटित किये जा चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, उसको पूरा भी करते हैं।

श्री कुलदीप वत्सः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः कुलदीप जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री नरेन्द्र गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स जी को बताना चाहूंगा कि मेरे सामने सदन में बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, उसके हिसाब से मैं कुछ भी बोलने से पहले 50 बार सोचता हूं। माननीय सदस्य श्री वरुण चौधरी जी ने क्वैश्चन पूछा था कि 5 करोड़ रुपये की विधायक निधि में से उनके हल्के के विकास के लिए कितने पैसे अलॉट हो चुके हैं ? अगर माननीय सदस्य सरकार के पास विकास कार्यों के लिए कोई एस्टिमेट्स बनवाकर नहीं भेजेंगे तो पैसे कैसे रिलीज होंगे ? इसके लिए तो माननीय सदस्यों को प्रपोजल बनवाकर भेजना चाहिए। माननीय सदस्यों को सदन में अपनी बात रखने के लिए तैयारी करके आना चाहिए। जब विपक्ष का कोई माननीय सदस्य अपनी बात रखने के लिए खड़ा होता है तो भी इनकी पार्टी के 6 माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। माननीय सदस्य आपस में कैमेंटरी न करें। जब आपको बोलने के लिए समय दिया जाए तब ही अपनी बात रखें।

श्री नरेन्द्र गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं फरीदाबाद हल्के के छायसा में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। पहले सभी लोग सोचते थे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से बहुत पीछे थे, परन्तु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में कोविड–19 की रोकथाम के लिए 2 वैक्सीनों का निर्माण किया है। इनको 50 देशों में भी भेजा जा चुका है और 100 देश इनको लेने के लिए लाईन में लगे हुए हैं। यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। मैं इसके लिए इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हरियाणा सरकार ने 15 दिसम्बर, 2020 में एक निदेशालय सभी के लिए

आवास उपलब्ध करवानें के लिए बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने के लिए जो निदेशालय बनाया गया है, उससे मुझे उम्मीद है कि फरीदाबाद जोकि स्लम की दृष्टि से मुम्बई के धारावी के बाद दूसरे नम्बर पर आता है, में स्थिति में सुधार आएगा। यह योजना मेरे हल्के के स्लम एरिया को रिहैबिलिटेशन करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इससे हम समाज में पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को जल्दी से जल्दी मकान उपलब्ध करवा सकेंगे।

श्री उपाध्यक्षः नरेन्द्र जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री नरेन्द्र गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एन.एच.ए.आई. द्वारा दिल्ली से फरीदाबाद होते हुए बड़ौदा को कनैक्ट करने के लिए एक हाईवे बनाया जाएगा। उसके लिए एच.एस.वी.पी. से जमीन भी अलॉट करवा दी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई गांव नहीं पड़ता है, वह पूरा क्षेत्र यू.एल.बी. के अंडर आता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करता हूं कि फरीदाबाद के विकास के लिए अलग से फंड दिया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में संत सूरदास जी की जन्मस्थली सीही में है। यह एरिया काफी पुराना है। इसमें सीवरेज व्यवस्था, रोडज बनाने और पूरे विधान सभा क्षेत्र का विकास करने के लिए अलग से 100 करोड़ रुपये का बजट दिया जाए ताकि हम वहां पर और विकास कार्य करवा सकें। इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा हल्के में और भी विकास कार्य किये जाने हैं।

श्री उपाध्यक्षः नरेन्द्र जी, अगर आपकी कोई और बात कहने से रही गयी है तो उसको आप लिखित में दे सकते हैं।

श्री नरेन्द्र गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं लॉस्ट में यही कहना चाहूंगा कि आपने कल महिला दिवस पर हमारे विपक्ष की माननीय महिला सदस्यों को सम्मान देते हुए सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही चलाने का जो मौका दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री नीरज शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय तो दिया है, परन्तु अभी तक मेरे हाथ में माईक नहीं आया है। आपने माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र गुप्ता जी को बोलने के लिए 11 मिनट का समय दिया था। मेरे बोलने का समय निकलता जा रहा है, इसलिए आप मेरा टाईम भी नोट करवा ले। (शोर एवं व्यवधान) इस महान सदन की मर्यादा के अनुसार हर मैम्बर को बोलने का अधिकार

है और यह उसका विशेषाधिकार भी है। आप इस महान सदन में मैम्बर्ज को डिमोरलाइज कर रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं 4:40 मिनट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, चाहे तो आप इस टाइम को नोट कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बिजली से संबंधित जिक्र किया गया था और मैं भी बिजली से संबंधित कुछ तथ्य इस महान सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। हरियाणा सरकार ने दो कम्पनियां यू.एच.बी.वी.एन. और डी.एच.बी.वी.एन. बना रखी हैं। सरकार इनके माध्यम से हर जगह कृषकों को बदनाम करने का काम कर रही है। चाहे कृषि क्षेत्र में सब्सिडी की बात हो और चाहे पराली जलाने से प्रदूषण की बात हो। हरियाणा सरकार का वर्ष 2004 में एग्रीकल्चर सेल्स 800 करोड़ रुपये था लेकिन आज यह बढ़कर 7000 करोड़ रुपये हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन को इस बारे में बताना चाहूंगा कि जब कोई भी अच्छा कार्य करता है तो उसे प्रोत्साहन करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है। जहां तक बिजली की चोरी की बात है तो जो विभाग के ऑफिसर्ज हैं वे स्थानीय लोगों से मिलजुलकर दो–तीन जिलों में चोरियां करवा रहे हैं। वहां के लोगों को इस बात का अहसास होना चाहिए कि यह गलत काम है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इन दोनों कम्पनियों यानी यू.एच.बी.वी.एन. और डी.एच.बी.वी.एन. का सरकारी डाटा है। डी.एच.बी.वी.एन. के अंदर लाइन लॉस 5 परसैंट से कम है। जहां तक कॉस्ट ऑफ सर्विस पर यूनिट की बात है तो यू.एच.बी.वी.एन. की 7.84 पैसे प्रति यूनिट है और डी.एच.बी.वी.एन. की 7.25 पैसे प्रति यूनिट है, जोकि 60 पैसे प्रति यूनिट का फर्क है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब किसानों को अनुदान की राशि के बारे में इस महान सदन को बताना चाहूंगा कि जो यह 6000 हजार करोड़ रुपये अनुदान के रूप में किसानों को मिलता है वह 55:45 के रेशों में यू.एच.बी.वी.एन. और डी.एच.बी.वी.एन. के बीच में बांटा जाता है जबकि डी.एच.बी.वी.एन. के अंदर बिजली की खपत 60 प्रतिशत ही होती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कायदे से इसका ऑडिट किया जाये तो सबके सामने सच अपने आप आ जायेगा। यहां पर एनर्जी ऑडिट के बारे में भी बार–बार बातें हो रही हैं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि डी.एच.बी.वी.एन. के उपभोक्ता को 1 से डेढ़ रुपये प्रति यूनिट का नुकसान हो रहा है, जबकि वहां चोरी कम है क्योंकि वहां ऐसे अधिकारी नहीं है जो स्थानीय लोगों से मिलजुलकर बिजली चोरी करते हैं परन्तु यू.एच.बी.वी.एन. के अंदर ऐसे कुछ चुनिंदा अधिकारी आपको देखने को मिल जायेंगे जो स्थानीय लोगों से मिलजुलकर चोरी करते हैं।

इन सबको एक ही रास्ता मिला हुआ है कि जो बिजली की फालतू चोरी होती है, उसका बिल एग्रीकल्चर के नाम पर या किसानों के नाम पर डाल दो। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करने से हमारे किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। किसी डिपार्टमैंट के अंदर एक साथ इतनी खामियां मिलना शायद ऐसा भी पहली बार हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2015 में एक आदेश पारित किया गया था। मैं उस बारे में बताना चाहूंगा कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इन आदेशों की पालना नहीं की गई। ऐसा भी शायद हमें आज तक सुनने को कहीं नहीं मिला कि आदेशों की पालना की गई है। मैंने इस विषय को डिपार्टमैंट के अधिकारियों के सामने विधान सभा की कमेटी की मीटिंग में उठाया था लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस बात से साफ पता चलता है कि जब इस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना की गई है तो फिर आम जनता पर इस बात का क्या असर पड़ेगा? अध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में हमारे फरीदाबाद के एक महान कवि दिनेश रघुवंशी जी के दो शब्द इस महान सदन में कहना चाहता हूं :–

> ''गरीब और मजलूमों का धन खाते यही दुख है,
> कोई समझाये तो उसको भी ये भरमाते, यही दुख है,
> समझते खुद को बस देवता और वक्त आये तो बचाने
> भ्रष्ट को, सब एक हो जाते बस यही एक दुख है''।

कहने का अभिप्राय यही है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सब एक हो जाते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सब बातें अच्छी–अच्छी लिखी गई हैं। मैं बहुत सी बातों से ऊपर उठकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर ये सारी बातें इतनी अच्छी हैं तो फिर इन बातों पर अमल क्यों नहीं किया जाता है? अब मैं लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट के बारे में जिक्र करना चाहता हूं जिसको छोटी सरकार भी कहते हैं। आज लोकल बॉडी डिपार्टमैंट में क्या हो रहा है? मैं इस बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे इलाके की एक बेटी के हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और उस बेटी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को ट्वीट करके कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज मेरी शादी है, मेरी बारात कैसे आयेगी, मेरी शादी कैसे होगी? उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने उस बेटी के ट्वीट पर संज्ञान लिया लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि यह बात

पूरी सरकार के लिए शर्म की बात भी है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी सीवरेज में फंटी मारने का काम करेंगे? क्या उस नगर निगम में 610 करोड़ रुपये की सिर्फ अधिकारियों/कर्मचारियों को तनख्वाहें बांटने का काम किया जाता है? उपाध्यक्ष महोदय जी, आज जिस क्षण मैं बोल रहा हूं उस क्षण भी उस गली की स्थिति जस की तस है। कोई साथी कहता है कि 15 परसैंट की लीकेज है। कोई कहता है कि सैंट्रल गवर्नमैंट से इतना पैसा आता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर तो बिना काम के ही पेमैंट हो जाती है। यह 250 करोड़ रूपये का मसला है यह कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। यह एक बड़ी ही व्यावहारिक बात है कि देरी से न्याय मिलना भी अन्याय ही है। सतबीरा एण्ड सतबीरा कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही करवाने के लिए चण्डीगढ़ के चक्कर काटते–काटते हमारे जूते घिस गए। जब इस मामले में स्टेट विजीलैंस डिपार्टमैंट से इंक्वॉयरी के ऑर्डर हुए तो नगर निगम के रिकार्ड रूम में ही आग लग गई। इस प्रकार की स्थिति में क्या जांच होगी और मौके पर क्या काम होंगे? अभी हमारे सत्ता पक्ष के एक साथी कह रहे थे कि हरियाणा में सब चीज अच्छी है। मगर हार्डवेयर चौंक से लेकर प्याली चौंक तक का रास्ता करप्शन की भेंट चढ़ गया। इसी रास्ते पर भाई मूल चंद शर्मा जी के विधान सभा क्षेत्र का लड़का सचिन शर्मा शहीद हो गया। अगर सड़कों में गढ्डे नहीं थे तो बाटा पुल उतरते हुए बेटा पवित्रा कैसे शहीद हो गया? इसी महान सदन में मैंने यह सुझाव दिया था कि सीवरेज के ढ़क्कन न बदले जायें तो उसको राईट टू सर्विस के अंदर लिया जाये। मुख्यमंत्री जी ने मेरा सुझाव माना और यहां सभी को बताया परन्तु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 6 महीने हो गये हैं अभी तक राईट टू सर्विस एक्ट कमीशन के चेयरमैन ही नहीं हैं। जब चेयरमैन ही नहीं हैं तो कार्यवाही कहां होगी और किसके ऊपर होगी? तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही प्रोग्राम है। यह बात आज नीरज शर्मा नहीं कह रहा है। इस बात को भाजपा के महापौर चिल्ला–चिल्ला कर कह रहे हैं। भाजपा के पार्षद घोटाले की बात कर रहे हैं। मंत्री जी ने भी चण्डीगढ़ में मीटिंग की होगी। पूरे के पूरे केन्द्रीय पदाधिकारीगण, हरियाणा के महापौर और डिप्टी महापौर इक्ट्ठे किये ताकि यह जानकारी ली जा सके कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग में क्या हो रहा है? जब हम इस सदन में प्रश्न लगाते हैं तो हमें गलत जवाब देकर गुमराह किया जाता है। मैं उन सभी पर यहां चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ

इतना बताना चाहूंगा कि जहां कहीं भी घोटाले हुए हैं उनमें दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। आज प्रदेश में प्राईवेट सैक्टर में प्रदेश के युवाओं को 75 परसैंट रोजगार देने का बहुत डंका पीटा जा रहा है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह 100 परसैंट होना चाहिए लेकिन इससे पहले सरकार को प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग लेकर आने पड़ेंगे। हरियाणा में जब सरकार रोजगार ही नहीं लायेगी तो यह कैसे होगा? इस समय हरियाणा प्रदेश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के आगमन का आंकड़ा तो जीरो परसैंट है। फिर चाहे जीरो को 75 परसैंट बता दिया जाये या फिर चाहे जीरो को 100 परसैंट बता दिया जाये तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में रोजगार क्यों नहीं आ रहे हैं। इसमें पुलिस का चेहरा सामने नजर आ रहा है। यह सभी जानते हैं कि गुरूग्राम में व्यापारियों के साथ क्या–क्या काण्ड हो रहे हैं यह किसी से छिपा नहीं है। जहां पर पुलिस काम करना चाहती है वहां पर सरकार के मंत्री ऐसे ब्यान देते हैं जिनसे पुलिस का मनोबल गिर जाये। सरकार के किसी भी फैसले पर पूरी कैबिनेट एकमत होती है लेकिन हमें यह बात समझ में नहीं आती कि मुख्यमंत्री जी ठीक हैं, फिर गृह मंत्री जी ठीक हैं, डी.जी.पी. साहब ठीक हैं या फिर पुलिस ठीक है? हमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में कौन ठीक है? किसी भी विषय पर सरकार की स्थिति किसी भी दृष्टि से स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर भी सरकार द्वारा बड़े लम्बे–चौड़े दावे किये जा रहे हैं। मैंने अपने हल्के में अस्पतालों को लेकर प्रश्न लगाये थे। आखिरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में जो प्राईवेट अस्पताल और प्राईवेट स्कूल हैं ये पैरेलल गवर्नमैंट बन चुके हैं। कोरोना काल के अंदर किसी ने भी इस विषय पर बात नहीं की कि पहली क्लास का बच्चा कहां से और कैसे ऑन–लाइन पढ़ाई करेगा? कोरोना काल में प्राईवेट स्कूलों ने अपना स्टॉफ कम कर दिया। ये प्राईवेट स्कूल सरकार से करोड़ों की जमीनें कोड़ियों के भाव में लेते हैं और अभिभावकों का बड़ी बेरहमी से खून चूसते हैं। इन पर कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं है। ये बच्चों को पेपर भी नहीं देने देते। अभिभावकों की कहीं भी सुनवाई नहीं होती। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : नीरज जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए अब आप बैठें। यदि आपकी कोई बात कहने से रह गयी है तो उसको आप लिखित रूप में दे दें ताकि उसको हाउस की कार्यवाही का हिस्सा बना लिया जाये।

श्री नीरज शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी लिखित स्पीच सदन के पटल पर रख देता हूं । आप उसको हाउस की प्रौसीडिंग का पार्ट बनवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आप लिखकर दे दीजिए उसे प्रौसीडिंग का पार्ट बना दिया जायेगा।

***श्री नीरज शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है कि सरकार द्वारा हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके तहत तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए राज्य के 18 हजार 121 तालाबों को लिया गया है। इस योजना के तहत मेरी विधान सभा क्षेत्र के 12 तालाबों को शामिल किया गया लेकिन एक तालाब पर भी आज तक किसी प्रकार का कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन तालाबों का कार्य कब तक शुरू हो जायेगा? इसी तरह से एच. आर.डी.एफ. स्कीम के तहत एन.आई.टी.–86 विधान सभा के फरीदाबाद के विभिन्न गांवों के विकास कार्यों की फाईल आचार संहिता लगने के कारण लम्बित रह गई थी। अब उक्त 50970000 रुपये के विकास कार्यों की फाईल निदेशक, प्रधान सचिव और माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से अनुमोदित होकर श्री सतीश कुमार, ओ.एस.डी. के कार्यालय में लम्बित है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कृपया करके इन गांवों में लम्बित पड़े विभिन्न विकास कार्यों को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए संबंधित विभाग को दिशा–निर्देश दिये जायें। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी विधायकों को स्वेच्छा से कार्य करवाने के लिए 5 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गांवों के विकास कार्य करवाने के लिए भी 11024000 रुपये दिये गये थे लेकिन दिनांक 10.07.2020 को 7734000 रुपये की फाईल पास होने के लिए माननीय उप–मुख्यमंत्री जी के पास उनके हस्ताक्षर के लिए गई लेकिन अभी तक उसके ऊपर उनके हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इस कारण से वह फाईल अभी तक लम्बित पड़ी हुई है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि कृपया उस फाईल को पास करवाने का काम किया जाये। इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव खेड़ी गुजरान की लगभग _

*** चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को कार्यवाही का पार्ट बनाया गया।**

8 एकड़ जमीन आयुष मंत्रालय भारत सरकार को National Institute of Unani Medicine for non communicable diseases एवं साथ में 120 बैड के अस्पताल खोले जाने के लिए दी हुई है लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि आज तक उक्त जमीन पर किसी प्रकार का कार्य शुरू नहीं किया गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस प्रोजैक्ट को स्टार प्रोजैक्ट के तहत लिया जाये और उक्त अस्पताल के कार्य को भारत सरकार के खर्चे से करवाने का काम किया जाये। इसी तरह से मेरे फरीदाबाद शहर में टॉय सिटी भी स्थापित हो इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है। उपाध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी खिलौना उद्योग और उससे जुड़ने वाले रोजगार के बारे में कहा है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाये ताकि जो भी इस प्रोजैक्ट में रूकावटे आ रही है उनको दूर करके इस प्रोजैक्ट को जल्द से जल्द शुरू किया जाये। मेरे फरीदाबाद शहर में अफॉर्डेबल ग्रुप हाउसिंग में ''TOD Policy'' को लागू किया जाये ताकि गरीब परिवारों को भी मेट्रो के आस–पास रहने का फायदा मिल सके। इसी तरह से मेरे फरीदाबाद और गुरुग्राम शहर को मेट्रो के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार प्याली चौक पर मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए डी.एम.आर.सी. को पुनः डी.पी.आर. तैयार करने के निर्देश दें। मेरा यह भी अनुरोध है कि इस कार्य के लिए बजट में भी विशेष प्रावधान करे और संशोधित डी.पी.आर. में प्याली चौक मेट्रो स्टेशन रखा जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे फरीदाबाद में माइनिंग का कार्य चालू करवाने का काम किया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव घौज में स्टेडियम बना हुआ है उसमें युवाओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए माननीय खेल मंत्री महोदय को व्यक्तिगत रूप से मिलकर एक पत्र दिया था लेकिन उस पत्र पर आज तक किसी प्रकार की कोई सुविधा युवाओं को नहीं मिली है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरे फरीदाबाद शहर की बड़खल झील की दुर्दशा को भी ठीक करने का काम भी किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल इस महान सदन में माननीय उप मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया था कि कोई भी व्यक्ति राशन वितरण में धांधली का सिंगल एविडैंस लेकर देगा तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जायेगी, परन्तु चंडीगढ़ में टैक्नोलॉजी/आई.टी. के नाम से एक कम्पनी आती है। वह कम्पनी कई सौ करोड़ रुपये के ठेका लेने का काम करती है। उस

समय यह कहा गया था कि इससे इस पारदर्शिता आयेगी, वेटिंग मशीन में पर्ची निकलेगी, मोबाइल पर एस.एम.एस. आयेगा, परन्तु धरातल पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं इस सदन को उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि दिनांक 4 अप्रैल, 2020 को मुझे सूचना मिली थी कि डबुआ कॉलोनी में राशन डिपो वाला राशन वितरण करने में धांधली कर रहा है तो मैं मौक पर जाकर देखा और पाया कि राशन डिपो वाला बिना तोल मशीन के बाल्टी में भर–भर के अनाज बांट रहा है। जिसका लिंक मेरे फेसबुक आई.डी. नम्बर– https://m.facebook.com/story.php?story_fbid = 2644357745845590 &id =100008141706239 एवं मेरे द्वारा सरकार को एस.एम.एस./व्हाट्सप के माध्यम से भी भेज दिया गया है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि टैक्नोलॉजी के नाम से कई सौ करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं परन्तु उसके बावजूद बाल्टियों में राशन का वितरण हो रहा है। उपभोक्ता को उसके हक का आधा राशन ही मिल रहा है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि राशन डिपो पर केवल गरीब व्यक्तियों को ही राशन दिया जाता है इसलिए कोई व्यक्ति इसकी आवाज नहीं उठा पाता है। अगर कोई व्यक्ति इसकी आवाज उठाता है तो उसका राशन कार्ड 1–2 महीने में काट दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कल महिला दिवस के मौक पर माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 33 प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को मिलेंगे जो कि एक सराहनीय कदम है इसलिए इस कड़ी में मेरे कुछ सुझाव है जो मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मातृ शक्ति को राशन डिपो के वितरण में 33 प्रतिशत का जो आरक्षण दिया है इस कड़ी में मैं कहना चाहता हूं कि कहीं यह आरक्षण दिखावा न बनकर रह जाये। जिन व्यक्तियों ने पहले डिपो ले रखे हैं कहीं ऐसा न हों कि वहीं व्यक्ति अपनी महिलाओं के नाम पर डिपो ले लें। मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार आंगनवाड़ी की भर्ती में उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है जो विधवा हैं या फिर जिसका आदमी दिव्यांग है। इस आरक्षण में भी ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाये ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हर एक पी.डी.एस. दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया जाये जिस पर स्टाक की डिटेल, राशन वितरण की तिथि आदि का ब्यौरा हो। पी.डी.एस. की जो सरकारी वेबसाइट epos.haryanafood.gov.in/ है उसका प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। ज्यादातार राशन डिपो वाले महीने की 30 तारीख को राशन वितरण करते

हैं। मेरा इस संबंध में यही कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि 20 तारीख तक राशन वितरण हो जाये लेकिन बिना पर्ची के राशन वितरण न हो। जहां पर भी राशन की दुकान है वहां पर Latitude/Longitude का विवरण हो ताकि एक ही व्यक्ति 10–10 लोगों का राशन डिपो न हड़प सके।

श्री लक्ष्मण यादव (कोसली) : डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए अवसर दिया सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। वैसे तो सभी जानते हैं कि गत एक वर्ष कोरोना काल में ही बीत गया। इस कोरोना काल के समय में सरकार की कमाई चवन्नी थी और खर्च एक रूपया था लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस पूरे एक साल में पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास के पहिए को रूकने नहीं दिया। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र था, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र था, चाहे वह बिजली का क्षेत्र था, चाहे वह पानी का क्षेत्र था, चाहे वह सोशल वैलफेयर के काम थे और चाहे सड़कों के निर्माण कार्य थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया। अध्यक्ष जी, मेरा आज सुबह एक क्वैश्चन लगा था उसके जवाब में शिक्षा मंत्री जी ने यह लिखा कि –"सवाल ही नहीं उठता।" अगर मंत्री जी उसके जवाब में यह लिख देते कि यह काम नहीं हो सकता तो भी ठीक रहता लेकिन माननीय मंत्री जी ने तो वही काम कर दिया जैसे किसी अपराधी को फांसी की सजा देते समय फाईल पर यह लिख देता है कि 'hang till death.' जिस पैन से ये शब्द लिखे जाते हैं अंत में उस पैन को भी तोड़ दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले वर्ष 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय में हरियाणा भर में पहले स्थान पर रही किशनगढ़ भालावास निवासी मेधावी छात्रा भावना यादव, बोड़िया कमालपुर के सरकारी स्कूल से पढ़ी है तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र कोसली से संबंध रखती है जिसको आपने सम्मानित भी किया था। इतना ही नहीं कला संकाय में भी पिछले वर्ष प्रदेश भर में तीसरे स्थान पर रही बेटी वर्षा यादव मेरी विधान सभा क्षेत्र कोसली के गांव झाडरा से सम्बन्ध रखती है। इस प्रकार से कॉलेज की छात्राओं ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में टॉप करके रिकार्ड बनवाने का काम किया है। हरियाणा भर में सबसे ज्यादा नैट और जे.आर.एफ. क्वालीफाइड बेटियां कोसली विधान सभा क्षेत्र से आती हैं। पिछले वर्ष भी बास बिटोड़ी की होनहार छात्रा पूजा यादव ने 10वीं कक्षा में हरियाणा में छठा स्थान

प्राप्त किया था। बेटियों की इतनी ज्यादा उपलब्धियां होने के कारण मैंने उस इलाके में विश्वविद्यालय का एक रीजनल सैंटर बनाने की मांग यहां विधान सभा में की थी लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब इतनी होनहार बेटियां हैं तो अब मैं वहां पर विश्वविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। जमीन उपलब्ध करवाने का काम हम करेंगे सरकार को केवल मंजूरी देनी है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों न तो टैक्निकल एजुकेशन में एडमिशन पूरे हो पाए हैं और न ही अकैडमिक एजुकेशन में एडमिशन पूरे हो पा रहे हैं इसलिए अब हमें ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। गांव मंदौला में गर्ल्ज स्कूल खोला जाए। इसी तरह से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि गांव खुर्शीदनगर में वैटर्नरी कॉलेज को मंजूरी देने का काम सरकार यथासम्भव करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि गांव भाकली में एक आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना करवाई जाए क्योंकि पिछले दिनों आपने देख लिया है कि कोरोना काल में आयुर्वेद ने ही लोगों की जान बचाई है। आयुर्वेद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। इसी प्रकार से गांव निमोठ में होम्योपैथिक कॉलेज के लिए जमीन तैयार है और प्रस्ताव भी विभाग के पास आया हुआ है इसलिए वहां पर होम्योपैथिक कॉलेज का निर्माण किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे हल्के में एच.एस.आई.आई.डी.सी. का सैक्टर काटा जाए। इस काम के लिए मसीद और दीदौली गांव में जमीन भी उपलब्ध है। आज जो टैक्निकल एजुकेशन में एडमिशन कम हो रहे हैं वे इसीलिए कम हो रहे हैं क्योंकि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अगर यहां पर इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी और उनका टैक्निकल एजुकेशन की तरफ रूझान बढ़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उप–मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया था और अब इस महान सदन के सामने कह रहा हूं कि जिस प्रकार नांगल चौधरी का टोल टैक्स हटाया गया है उसी प्रकार से गांवों से तहसील तक की सड़कों पर जो टोल लगे हुए हैं उनको हटाया जाए। लोगों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए तहसील तक जाना होता है और उनको अपने काम निपटाने होते हैं। गांव पालावास से चौकी नम्बर 1 पर जो टोल टैक्स लगाया हुआ है उसको हटाया जाये। इसी प्रकार से नाहड़ से कनीना रोड़ पर भी एक कमर्शियल टोल टैक्स लगाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि या तो इस टोल को बिल्कुल समाप्त किया जाये या अगर लगाना

अनिवार्य ही हो तो कम से कम 10 किलोमीटर तक के लोगों को उस टोल प्लाजा से छूटा प्रदान की जाए क्योंकि मेरे एक विधान सभा क्षेत्र कोसली में ही तीन टोल टैक्स लगे हुए हैं जिसके कारण लोगों को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी से निवेदन है कि पिछले 3 साल से बिजली के जो कनैक्शन पैंडिंग पड़े हैं उनको यथाशीघ्र रिलीज किया जाये क्योंकि किसानों ने अपना पूरे का पूरा पैसा जमा करवाया हुआ है। इसी प्रकार से अब मैं खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कोसली में लोगों का राष्ट्रीय खेल हॉकी के प्रति बहुत लगाव है। खेल मंत्री जी नैशनल हॉकी प्रतियोगिता पर कोसली में भी आये थे और इन्होंने उस प्रतियोगिता की ओपनिंग भी की थी जिसमें हरियाणा प्रदेश से सभी जिलों की टीमें आई थी। मेरा आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से अनुरोध है कि कोसली में हॉकी का एक एस्ट्रोटर्फ स्थापित किया जाये ताकि युवाओं को बेहतरीन खेल सुविधा उपलब्ध हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं तीन कृषि कानूनों के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। ये तीन कृषि कानून छोटे किसान की बड़ी आस हैं, मध्यम किसान का विश्वास हैं ये कानून, देश का किसान तो अपने खेत में है क्योंकि उनको तो पूरी तरह रास हैं ये कानून। जो लोग कृषि के उन तीन कानूनों को काला कानून कह रहे हैं। वे ये बताएं कि उन्होंने वर्षों तक केन्द्र व प्रदेश की सत्ता में रहते हुए किसानों के लिए क्या किया है? किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना सियासी मकसद हल करने की फिराक में जो राजनीति हो रही है उसे प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है इसलिए मैं उन लोगों के लिए ही कहना चाहूंगा कि–

''हमारी नियत सवाली थी, तम्हारी नीति भी सवाली थी।
तुमने तो अपने राज में किसानों की जमीन ही खा ली थी,
हमारी दाल में काला ढूंढने वालो,
तुम्हारी तो पूरी दाल ही काली थी।''

धन्यवाद। जय–हिन्द, जय भारत।

श्री मामन खान (फिरोजपुर झिरका): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सारा पढ़ा है। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने तो कह दिया था कि इसको पढ़ा हुआ समझा जाए। मगर उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सदन में सभी विधायकों ने खासकर हमारे देश का जो किसान आज दिल्ली के बोर्डर्ज पर बैठा

हुआ है, उनके बारे में अपनी–अपनी बात रखी। जो लोग यह कहते हैं कि किसान बोर्डर्ज पर गलत बैठे हुए हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि हमारा किसान इतना बावला नहीं है कि बिना बात के वह दिल्ली बोर्डर्ज पर जाकर धरने पर बैठे। जिन लोगों ने हमें एम.एल.ए. और एम.पी. बनाकर भेजा हुआ है वह बहुत सयाने व समझदार हैं। यदि उनको ये कृषि बिल पसंद नहीं है फिर तो सरकार को ये तीनों कृषि बिल वापिस लेने चाहिएं। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने अपने अभिभाषण में जिन चार मार्गीय सड़कों का जिक्र किया है उसमें गुरूग्राम–पटौदी सड़क भी है। अच्छी बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सोहना से लेकर नूहं तक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने जो चार लेन का रोड बनवाया था उस पर आज तक कोई कैजवल्टी नहीं हुई है। मगर नूंह से लेकर राजस्थान बोर्डर तक बहुत खराबे हालात हैं। मैं इस बारे में आंकड़े बता देता हूं। वहां पर कम से कम 1576 आदमियों की दुर्घटना में मौत हुई है और तकरीबन 3746 आदमी घायल हुए हैं। मैं यह कहता हूं कि कभी किसी मंत्री या एम.एल.ए. का बच्चा वहां पर रोड एक्सीडैंट में गुजर जाता तो उनको दुःख का पता चलता कि उस रोड की कितनी कीमत है। मैंने इसके बारे में दिनांक 04.03.2020 को भी एक प्रश्न लगाया था लेकिन उस समय सरकार ने उसको भी नकार दिया था। ऐसी क्या बात है कि मेवात को कंसीडर ही नहीं किया जाता है? उपाध्यक्ष महोदय,

> ''सरकारें बदल गई, समय बदला लेकिन नहीं बदली तो आज तक मेवात की बदहाली नहीं बदली।''

मैं यह बताना चाहता हूं कि जितना भी जल्दी हो सके इस रोड को नूंह तक ही नहीं बल्कि राजस्थान बोर्डर तक चार लेन किया जाए क्योंकि यहां से 30 हजार से ज्यादा व्हीकल्ज हर दिन अप–डाउन होते हैं। अगर इस रोड पर कोई एम्बुलैंस फंस जाती है या कोई एक्सीडैंटल केस लेकर भी जाते हैं तो वह भी दिल्ली या जयपुर नहीं पहुंच सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मेवात में ट्रामा सैंटर की सुविधा नहीं है और ट्रामा सैंटर की सुविधा न होने की वजह से एक्सीडैंट वाले लोगों के पास जयपुर या दिल्ली पहुंचने के लिए केवल दो घंटे का ही गोल्डन चांस होता है लेकिन उस रोड पर ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वह होस्पीटल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैंने अपने क्षेत्र के लिए एक ट्रामा सैंटर खोलने की मांग की थी। मेवात बहुत बड़ा है उसमें 550 गांव हैं और 11 लाख के करीब जनसंख्या है इसलिए वहां पर एक ट्रामा सैंटर खोलने की बहुत जरूरत है। सरकार ने इसके

लिए 'हां' तो की थी लेकिन अभी तक खोला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को ट्रामा सैंटर खोलने के बारे में कह रहा हूं कि सरकार हमारे वहां पर एक ट्रामा सैंटर को खोलने का प्रस्ताव कंसीडर करे। जब हम अपने इलाके के किसानों के पास जाते हैं तो वे हमारे सामने चिल्लाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने वर्ष 2017 में ट्यूबवैल के कनैक्शन के लिए सिक्योरिटी भरी थी मगर आज तक उनके कनैक्शन रिलीज नहीं किये गये हैं। ऐसा क्यो? वे किसान बिना पानी के अपनी खेती कैसे कर पाएंगे, कैसे अपनी फसलों को पानी दे पाएंगे? मेरा सरकार से आग्रह है कि उन किसानों के ट्यूबवैल के कनैक्शन जल्दी से जल्दी रिलीज किये जाएं।

17.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां से बड़ौदा एक्सप्रैस हाइवे जाता है जिसके साथ मेवात की राजधानी कही जाने वाले बड़कली का एरिया लगता है। अगर इस हाइवे पर रोड कट मिल जाये तो इससे यहां के लोगों को बहुत फायदा होगा। उनको बिजनेस के नए अवसर मिलेंगे और साथ ही आने–जाने की भी सुविधा हो जायेगी। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा इस तरफ गौर फरमाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, नगीना में वर्ष 1970 में एक कालेज बनाया गया था। शुरू में यह प्राइवेट हाथों में था लेकिन वर्ष 1980 में इसको सरकार द्वारा टेक–ओवर कर लिया गया। इस कालेज में सिर्फ एक ही ब्लॉक है और सात कमरे हैं जबकि 1200 बच्चे पढ़ते हैं। आप यह बताइये कि सात कमरों में किस तरह से 1200 बच्चे पढ़ सकेंगे? अतः इन बच्चों को पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है। अतः मेरा निवेदन है कि यहां पर साईंस ब्लाक के साथ–साथ आर्ट ब्लॉक का भी प्रावधान किया जाये और इस कालेज में स्टेडियम भी बनाया जाये। कितनी विडम्बना की बात है कि यहां पर पीने के पानी तक की भी सुविधा नहीं है। जहां तक इरिगेशन की बात है, के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां एक ही ड्रेन है जिसको बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से जाना जाता है। इसमें कभी भी लास्ट तक पानी नहीं आता है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बार–बार अनुरोध करने पर भी इसमें पानी नहीं छोड़ा जाता है। सरकार ने दिल्ली के अन्दर चीफ इंजीनियर, इरिगेशन बैठा रखे हैं। जब उनसे इस बारे में कहा जाता है तो जवाब मिलता है कि अभी पानी छुड़वाता हूँ लेकिन कुछ नहीं किया जाता। उपाध्यक्ष महोदय, यहां के लोगों की फसल खराब हो गई है अतः इस तरफ अवश्य ध्यान दिया जाये। जहां तक शादीपुर और उमरा माइनर की बात है, के परिपेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि ईटों से बनी यह माइनर्ज 25 साल से ज्यादा पुरानी हो गई हैं अतः वर्तमान परिपेक्ष्य में इनको दोबारा से

बनाने की बहुत आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र के किसानों को कोई दिक्कत न आये। जहां तक इंडस्ट्रीज की बात है, के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में आज तक एक भी इडस्ट्री नहीं लगाई गई है। सोहना के पास कुछ प्रावधान किया गया है लेकिन यह हमारे एरिया से बहुत दूर है अतः यदि फिरोजपुरा झिरका में जहां पर हजार–हजार एकड़ पंचायती जमीन अवेलेबल है, इंडस्ट्रीज लगा दी जायें तो बहुत अच्छा होगा और इससे मेवात एरिया के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर यहां पर इंडस्ट्रीज डिवेल्प की जाये और उनको कम से कम पांच साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाये तो लोगों को रूझान मेवात में इंडस्ट्री लगाने की तरफ बढ़ेगा और इससे रोजगार के नए–नए अवसर पैदा होंगे और मेवात के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेवात क्षेत्र के काफी बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में हैं लेकिन बावजूद इसके मेवात में कोई भी सैनिक बोर्ड या सैनिक कैंटीन की सुविधा नहीं है। इनको इस प्रयोजन के लिए गुरूग्राम में आना पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेवात में सैनिक कैंटीन और सैनिक बोर्ड भी बनाया जाये। इसके अतिरिक्त मेरा अनुरोध यह भी है कि मेवात को जिला तो बना दिया गया है लेकिन यहां पर एस.ईज. नहीं लगाए गए हैं। अतः अनुरोध है कि यहां पर पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट, डी.एच.बी.वी.एन. तथा इरिगेशन डिपार्टमैंट के एस.ईज. लगाने का काम किया जाये ताकि लोगों को अपने ग्रीवेंशिज के लिए दूर–दूर न जाना पडे।. उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पुलिस के बारे में बात करूंगा। हरियाणा में पुलिस द्वारा धारा 379–बी को सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाता है। यह धारा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश में ही लागू है। वास्तव में इस धारा को मैट्रो सिटीज में स्नैचिंग जैसी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। इस धारा के लगने पर छह महीने तक जमानत तक नहीं होती है। पुलिस सबसे पहले इस धारा को लगा देती है और बिना किसी तफतीश के सीधा जेल भेजने का काम करती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसकी तरफ संज्ञान लेने की बहुत जरूरत है। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे यहां मैडिकल कालेज में कैंसर स्पेशिलिस्ट और न्यूरो सर्जन की भी सुविधा दी जाये। जहां तक पीने के पानी की बात है मेवात के लोगों को 1000 रूपये का पानी का टैंकर खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। यहां पर 54 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी आए 10–10 साल हो गए हैं। अतः मेरी अर्ज है कि चूंकि पानी लोगों की बेसिक नीड्ज में शामिल है,

अतः लोगों को पानी की बेसिक नीड्ज से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। जब हमारे लोगों को सरकार पानी तक नहीं दे रही है तो फिर सदन में किस आधार पर सरकार के फेवर में बड़े–बड़े कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि सरकार ने यह कर दिया–सरकार ने वह कर दिया, सरकार नम्बर वन है और न जाने क्या–क्या बातें कही जा रही है? अतः मेरा अनुरोध है कि पानी की समस्या पर सरकार को गौर करने की बहुत जरूरत है। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे यहां साकरस एक बहुत बड़ा गांव है जिसकी आबादी लगभग 30000 से ज्यादा है, अतः वहां पर भी एक पी.एच.सी. जरूर खोली जाये।(विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः मामन जी, आपका बोलने का समय पूरा हो गया है, अतः आप प्लीज बैठिए और अब संजय सिंह को अपनी बात रखने दें।

श्री संजय सिंह (सोहना): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद। हमारी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के कुछ महीने बाद ही कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी शुरू हो गई थी लेकिन बावजूद इसके हमारी सरकार ने धैर्यतापूर्वक उसका सामना करते हुए सारी व्यवस्थाओं को बढ़िया ढंग से संभालने का काम किया। जब पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा था उस वक्त हमारे डाक्टर्ज व वैज्ञानिक कोरोना की दवाई ढूंढने में लगे हुए थे। उपाध्यक्ष महोदय, कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों से ही हमारे देश में कोरोना वैक्सीन बनी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में बनी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाकर यह साबित कर दिया है कि यह वैक्सीन वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये काफी कारगर सिद्ध होगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भारत देश में बनी कोरोना वैक्सीन के बारे में पूरे देश में एक भय का वातावरण बनाया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश विकासशील देश है और हर परिस्थितियों का सामना करना जानता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतागण कह रहे हैं कि भारत में बनी कोरोना वैक्सीन ठीक नहीं है, इसको लगाने से विपरीत असर पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि नूंह जिले से तीन कांग्रेसी विधायक हैं और संयोग से मैं भी उस क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। नूंह जिले से संबंधित तीनों कांग्रेस पार्टी के सदस्य कहते हैं कि नूंह जिले में शिक्षा के संबंध में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों में हमारे जिले से शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं लेकिन जब से हरियाणा

प्रदेश में नूंह जिला बना है तब से लेकर शिक्षा के विकास को लेकर कोई काम नहीं हुए थे अर्थात् स्कूल्ज अपग्रेड तक भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन हमारी सरकार ने केवल 6 वर्षों की अवधि में इस क्षेत्र में इतने नये स्कूल्ज खोल दिये और अपग्रेड कर दिये, जितने पहले कई वर्षों तक भी नहीं हुये थे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समान क्षेत्र समान विकास के साथ आगे बढ़ रही है। फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र से हमारी पार्टी का विधायक न होते हुए भी करोड़ों रुपयों की ग्रांट से मेवात कैनाल योजना बनाई है, जिससे पूरे जिले को फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रोजैक्ट पर बहुत जल्दी ही कार्य शुरू हो जायेगा। मैं समझता हूँ कि नूंह जिले में विकास के काम बहुत काम हुए हैं। विकास के इतने काम पिछली सरकारों ने कभी नहीं किये, जितने विकास के कार्य हमारी सरकार ने केवल 6 वर्षों की अवधि के दौरान कर डाले हैं। यह हमारे क्षेत्र के लिये रिकॉर्ड की बात है, इसके लिए मैं अपने क्षेत्र के निवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी की नेतृत्व वाली सरकार को बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। हमारी सरकार ने नम्बरदारों का मानदेय में बढ़ौत्तरी करके 3000 रुपये प्रति महीना कर दिया, यह हमारे नम्बरदारों के लिये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उनके पास आय का कोई भी साधन नहीं होता है। सरकार ने 'बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ' योजना के तहत छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये 150 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा देने की सुविधा प्रदान की है। उपाध्यक्ष महोदय, श्री मनोहर लाल जी की नेतृत्व वाली सरकार ने 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' का दायरा बढ़ाकर अब 51000/– रुपये शगुन राशि कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग 98 करोड़ रुपये भी खर्च कर दिये हैं। मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान की समस्त विधान सभाओं में से हमारी पहली ऐसी सरकार होगी जो हर क्षेत्र और हर वर्ग का बिना भेदभाव के विकास के अनेकों काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेतागण किसानों को तीन कृषि कानून के बारे में न जाने क्या–क्या कहते रहते हैं, जिनके बहकावे में आकर आज किसान आंदोलनरत है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में भाईचारे का माहौल बना हुआ था लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सत्ता के लालच में भाईचारे के माहौल को खराब कर दिया है। मैं भी किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, इसलिए किसानों की हालत भलीभांति जानता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वायदा किया हुआ है कि वर्ष

2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार किसानों के विकास के लिय अनेकों काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के से संबंधित कुछ मांग और समस्याएं सदन में रखना चाहता हूं । तावडू ब्लॉक में जो नागरिक अस्पताल बना हुआ है उसमें पूरा स्टाफ डैप्युट नहीं है । अतः मेरा आपसे निवेदन है कि उसमें स्टाफ की कमी को जल्द–से–जल्द दूर किया जाए । इसके अलावा तावडू में एक नया बाई पास बनवाया जाए क्योंकि वह एक बहुत ही पुराना कस्बा है । जब हम पटौदी या किसी अन्य जगह पर जाते हैं तो हमें शहर के बीच से होकर जाना पड़ता है । अगर वहां पर सही ढंग से एक बाई पास बना दिया जाए तो वहां के निवासियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछले सत्र में सोहना में मिनी सैक्रेटेरियट बनवाने के लिए कहा था । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार उसे जल्दी ही बनवाने का काम अवश्य करे। इसके अलावा तावडू में भी मिनी सैक्रेटेरियट बनवाया जाए । सरकार ने तावडू में एच.एस.वी.पी. के सैक्ट्र्स काटने की घोषणा की हुई है अतः तावडू में जल्द से जल्द ये सैक्ट्र्स काटे जाएं । (विघ्न) सोहना अपने आप में एक बहुत ही विकसित क्षेत्र बन रहा है अतः वहां पर मल्टी लैवल पार्किंग की व्यवस्था की जाए । के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे और एक नैशनल हाईवे सोहना से होते हुए गुजरते हैं । वहां से जाने वाला नोएडा एक्सप्रैस–वे बहुत जल्दी बनना भी प्रस्तावित है । मेरा निवेदन है कि सोहना में एक बड़ा हॉस्पिटल भी बनवाया जाए । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं ।

श्री मेवा सिंह (लाडवा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी लेकिन सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बजाय उनकी लागत दोगुनी करने का काम किया है । आज डीजल, यूरिया, डी.ए. पी. के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं । इनके रेट बढ़ने से किसान की लागत तो दोगुनी हो चुकी है लेकिन आमदनी दोगुनी नहीं हुई है । सदन में जीरी की खरीद की बात की गई । पिछले दिनों सरकार ने जीरी के रेट में सौ–सौ रूपये और 2–2

सौ रूपये कट लगाने का काम किया । इसी तरह से सदन में भारतीय जनता पार्टी का जो भी सदस्य बोला उसने प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने का रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा देने की बात कही । चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उस समय गन्ने का रेट 117 रूपये प्रति क्विंटल था । उन्होंने अपने कार्यकाल के 10 वर्षों में गन्ने का रेट 193 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 310 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया था । आज भाजपा गन्ने के रेट के विषय में ढिंढोरा पीट रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें भाजपा का क्या योगदान है ? इस सरकार ने सिर्फ 40 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है । इतने रूपये की तो गन्ने की कटाई की अकेली लेबर बढ़ चुकी है जबकि सरकार इसी रेट का ढिंढोरा पीट रही है । सत्ता पक्ष के जितने भी साथियों ने सदन में अपने विचार रखे हैं सभी ने एक ही बात कही कि विपक्ष ने किसानों को बहकाया हुआ है । मेरा कहना है कि अगर हम किसानों को बहकाने में इतने माहिर होते तो इनमें से यहां पर कोई भी सदस्य के रूप में बैठा न होता । आज हमारा किसान इतना समझदार हो चुका है कि वह अपने भले–बुरे के विषय में अच्छी प्रकार से स्वयं निर्णय कर सकता है । अगर सरकार उनका भला नहीं कर सकती तो कम से कम दिल्ली बॉर्डर्ज पर आंदोलन के दौरान मरे हुए किसानों को शहीद का दर्जा देकर उनके लिए आर्थिक सहायता की घोषणा ही कर दे । सदन में भूजल संकट के विषय पर बात की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको सुधारने के लिए किसान के बोरवैल की बात थी । भूजल संकट को नहरों के पानी के द्वारा सुधारा जा सकता है लेकिन इस सरकार ने खुदी–खुदाई दादूपुर–नलवी नहर को अटवाने का काम किया । ऐसे में भूजल संकट से कैसे छुटकारा मिलेगा ? मुझे चिन्ता है कि आने वाले समय में यह संकट बहुत बड़ा होने जा रहा है । मेरा कहना है कि भूजल संकट से निपटने के लिए सरकार को जलस्तर को ऊपर उठाना होगा । इसके जो भी तरीके हैं उनकी समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया जाए । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 'विवाह शगुन योजना' की बात की है। सरकार उन परिवारों को 51 हजार रूपये देती है लेकिन वे पैसे 2–2 साल तक उनके खातों में नहीं आते । इस तरह देरी से आने की वजह से वे पैसे शादी में काम नहीं आ पाते बल्कि वे पैसे तो उनके बच्चों के पैदा होने के समय काम आते हैं । मेरा सुझाव है कि ये पैसे शादी से पहले ही दिए जाएं ताकि ये पैसे गरीब लोगों के काम आ सके। इसके अलावा सदन में नशे की भी बात की गई है। नशे को रोकने के लिए

सरकार द्वारा मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गयी है, परन्तु 9 महीने का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उसका न तो कहीं पर दफ्तर है और न ही अधिकारी/कर्मचारी हैं। मैं इसी सिलसिले में कुरूक्षेत्र जिले के एक केस का जिक्र करूंगा। एक एफ.आई.आर. नम्बर 580 दिनांक 30.10.2020 को दर्ज हुई थी। इसमें 7 क्विंटल चूरा पोस्त, 3 क्विंटल डोडा पोस्त और 38 किलो गांजा पकड़ा गया था। यह एफ.आई.आर. लगभग 4 महीने पहले दर्ज हुई थी और डी.एस.पी. कुरूक्षेत्र ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। इसकी जांच करने के लिए 4 महीने में 3 बार अधिकारियों को बदला जा चुका है। डी.एस.पी. कुरूक्षेत्र को इस जांच से हटाकर डी.एस.पी. पिहेवा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और उसके थोड़े दिनों के बाद ही डी.एस.पी. पिहेवा को इस जांच से हटाकर डी.एस.पी. अंबाला कैंट को इसकी जांच करने के लिए कहा गया। मुझे अब भी उम्मीद नहीं है कि सरकार इस जांच को पूरी करने देगी। सरकार में बैठे कौन लोग इस केस की जांच करने के लिए बार–बार अधिकारियों को बदलवाकर अपराधियों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ? सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि इसकी जांच करने के लिए अधिकारियों को बार–बार न बदलें ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। दूसरी बात सरकार ने डी.टी.ओ. लगाकर ओवरलोड वाहन रोकने की बात की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि एक केस में कुरूक्षेत्र में एफ.आई.आर. नम्बर 590 दिनांक 30.11.2020 को दर्ज हुई थी। पिछले सैशन के दौरान भी मैंने यह मुद्दा उठाया था। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर कहा था कि इसमें संबंधित एस.डी.एम. को सैस्पेंड कर दिया है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। इसमें पांच महीने का समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इसमें एस.पी. कुरूक्षेत्र ने चीफ सैक्रेटरी को इस केस की जांच में संबंधित एस.डी.एम. को शामिल करवाने के लिए पत्र लिखा था, परन्तु पांच महीने का समय व्यतीत होने के बाद भी आज तक सरकार द्वारा यह परमिशन नहीं दी गयी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से उस एस.पी. के पास चिट्ठी आयी कि आप इस इन्वेस्टीगेशन में एस.डी.एम. को क्यों शामिल करना चाहते हैं और उससे क्या पूछेंगे? क्या ये सब बातें उस एस.डी. एम. को बचाने के लिए नहीं की जा रही हैं ? मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि उस एस.डी.एम. को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टीगेशन में शामिल करने की परमिशन दी

जाए ताकि जल्दी से जल्दी अपराधियों को सजा दी जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्षः मेवा सिंह जी, अगर आप कोई और बात कहना चाहते हैं तो उसको लिखित में दे दें।

श्री मेवा सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के लाडवा में बाई पास न होने के कारण बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि युमनानगर से जितने भी ट्रक रेत, बजरी, रोडी और पत्थर लेकर आते हैं, वे लाडवा से होते हुए राजस्थान में जाते हैं। इसके कारण जाम की स्थिति बनी रहती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर एक बाई पास बनवाया जाए। धन्यवाद।

श्री प्रवीण डागर (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रदेश सरकार का प्रदेशवासियों के विकास के लिए दिशामय उद्बोधन है। हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और हम यहां पर सदन में बैठे हुए सभी जन प्रतिनिधि कहीं न कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे सभी किसान परिवारों से ताल्लुकात रखते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की भलाई के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। उन्होंने किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों ने जाना कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार 'सबका साथ–सबका विकास और सबका विश्वास' की नीति को अपनाते हुए प्रदेश में चहुंमुखी विकास करने के लिए कार्य कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दक्षिण हरियाणा के लिए जो सिंचाई योजना हेतु बजट मंजूर किया है, वह किसान कल्याण का एक आधार है। सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है और पूरे प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे पूरे प्रदेश के साथ–साथ दक्षिण हरियाणा का किसान मुख्यतः लाभांवित होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय

मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से विधायक चुनकर आता हूं, वहां पर सिंचाई के साधनों का बहुत अभाव है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इस बारे में उस क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मेवात कैनाल का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। इसके अतिरिक्त मेरे हथीन क्षेत्र के किसानों की लगभग 25 वर्षों से यह मांग थी कि हमारे वहां पर किसानों के लिए लडमाकी माईनर का निर्माण होना चाहिए लेकिन किसी कारणवश पूर्व की सरकारों ने वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज मैं इस महान सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे हथीन क्षेत्र की लडमाकी माईनर का निर्माण करवाया जाये। जिससे वहां के किसान अपने खेतों में सिंचाई कर सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र हथीन में लगभग 20 वर्षों से एक ही मांग चली आ रही है कि मेरे हथीन क्षेत्र में रास्ते बहुत छोटे हैं और आने–जाने के कारण वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का समाना करना पड़ रहा है इसलिए वहां पर जल्द से जल्द बाईपास बनाने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महादेय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2016 में हथीन में एक रैली की थी और उसमें अनाउंसमैंट की थी कि हथीन क्षेत्र को बाईपास की सौगात दी जायेगी। पिछले वर्ष मैंने भी प्रगति रैली के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि हमारे हथीन क्षेत्र में बाईपास का निर्माण करवाया जाये। मैं उप–मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने कल इस महान सदन में हथीन बाईपास को बनाने के लिए आश्वासन दिया है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे हथीन बाईपास का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाने का काम किया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों ने ई–भूमि पोर्टल पर 89 परसैंट अपने सहमति पत्र दे दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पलवल जिला उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है तथा यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का ज्यादा अभाव है। पिछले 6 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कुछ सुविधाएं जरूर हुई हैं लेकिन वह नाकाफी है। जिला पलवल को स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए जिला फरीदाबाद व दिल्ली प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है जोकि काफी जटिलता भरा हुआ है। मेरे जिले के साथ लगते हुए नूंह और फरीदाबाद में कई वर्ष पूर्व मैडीकल कॉलेज का निर्माण हुआ था लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में जिला पलवल में अभी तक मैडीकल कॉलेज के निर्माण की कोई योजना नहीं बनाई गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि जिला पलवल के गांव फुलवाड़ी जो कि हमारे

पलवल चुनाव क्षेत्र, हथीन चुनाव क्षेत्र और होडल का सैंटर भी है, जहां पर पंचायत की लगभग सैंकड़ों एकड़ जमीन पड़ी हुई है और उस जमीन को पंचायत देने के लिए भी तैयार है, में मैडीकल कॉलेज का निर्माण करवाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रवीण जी, आप अपनी स्पीच लिखकर दे दीजिए ताकि वह प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन सके।

श्री प्रवीण डागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करूंगा। मुझे और बोलने का मौका दिया जाये क्योंकि मैंने कल भी दो बार अध्यक्ष महोदय को अपना नाम लिखकर दिया था। मेरा हथीन क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछले कार्यकाल के दौरान मेरे गांव में लड़कियों के लिए एक महाविद्यालय की सौगात देने का काम किया था। उसी तरह से हमारा मानपुर गांव एक बहुत बड़ा गांव है, उसमें भी लड़कियों के लिए एक कॉलेज की सौगात दी जाये ताकि हमारे क्षेत्र की लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो समय दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र पंवार (सोनीपत) : उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सभी विधायक साथियों ने बहुत जोर से मेजें थपथपाई। सत्ता पक्ष के सभी साथियों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह कहा कि हरियाणा नम्बर वन है। उनकी इस बात से मैं भी सहमत हूं कि हरियाणा नम्बर वन है लेकिन आज अपराध में हरियाणा नम्बर वन है, आज गरीबी में हरियाणा नम्बर वन है, आज बेरोजगारी में हरियाणा नम्बर वन है, आज भ्रष्टाचार में हरियाणा नम्बर वन है और महंगाई में भी आज हरियाणा नम्बर वन है। अगर हरियाणा प्रदेश में रोजगार की बात की जाये तो भाजपा सरकार के साढ़े 6 साल के शासनकाल के दौरान हरियाणा के युवाओं को कितना रोजगार मिला वह किसी से भी छिपा नहीं है वह हम सभी के सामने है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना तो दूर बल्कि पुरानी सरकारों के समय में जिनको नौकरी मिली थी उनको भी बर्खास्त करने का काम यह सरकार कर रही है। जिन नौकरियों को कोर्ट में चैलेंज किया गया था अगर उन मामलों की कोर्ट में ठीक से पैरवी होती तो लोगों को अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ता। सरकार ने भविष्य में प्राईवेट सैक्टर में भी

हरियाणा के युवाओं को 75 परसैंट नौकरियां देने का वायदा किया है। इस सम्बन्ध में मेरा तो यही कहना है कि प्राईवेट सैक्टर में हरियाणा के युवाओं को 75 परसैंट नौकरियां तो तभी मिलेंगी जब हरियाणा प्रदेश में उद्योग धंधे स्थापित होंगे। सरकार ने यह नहीं बताया कि नये उद्योग धंधे कहां से आयेंगे? जब आज की तारीख में हरियाणा प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है तो फिर हरियाणा प्रदेश में नये उद्योग धंधे कहां से आयेंगे? वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश में नये उद्योग तो कहां से आयेंगे बल्कि जो उद्योग हरियाणा में लगे हुए भी थे वे भी धीरे–धीरे हरियाणा से पलायन कर रहे हैं। आज हरियाणा में भ्रष्टाचार का यह आलम है कि हरियाणा में आज अगर कहीं भी रजिस्ट्री होती है तो वहां पर सरेआम रजिस्ट्री करने के लिए पैसे लिये जाते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी को टाऊन एण्ड कंट्री प्लॉनिंग डिपार्टमैंट या अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट से एन.ओ.सी. लेनी है तो वह भी बिना पैसे दिये नहीं मिलती। लोगों को एन.ओ.सी. लेने के लिए कई–कई महीने तक धक्के खाने पड़ते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट में जो हाउस टैक्स का सर्वे हुआ वह ऐसी कम्पनीज को दे दिया जिन्होंने कई–कई गुणा बढ़ाकर हाऊस टैक्स की कैलकूलेशन की। आज लोगों को उसको भी पैसे देकर ठीक करवाना पड़ रहा है। इस प्रकार से यह हरियाणा में भयावह भ्रष्टाचार की तस्वीर है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, आम व्यक्ति को शिक्षा, चिकित्सा की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाना, सस्ते आवास उपलब्ध करवाना और रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। अगर शिक्षा की बात की जाये तो शिक्षा मंत्री जी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हरियाणा में कितने नये स्कूल खुले हैं और कितने स्कूलों को अपग्रेड किया गया है? शिक्षा मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करें कि सरकार ने सरकारी स्कूल्ज की बेहतरी के लिए क्या–क्या कदम उठाये जिससे हरियाणा प्रदेश के नागरिकों में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने का रूझान बढ़ता। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, जब प्रदेश के लोगों के पास प्राईवेट स्कूलों की फीस देने के पैसे नहीं रहे उसी स्थिति में उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाया। आज हरियाणा प्रदेश में कोई भी अभिभावक खुश होकर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल नहीं करवाना चाहता। हरियाणा प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बहुत ज्यादा दुर्दशा हो चुकी है। अगर हरियाणा प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं की बात की जाये तो सभी ने देखा है कि

स्वास्थ्य मंत्री सदन में ही लम्बे समय से हरियाणा प्रदेश में डॉक्टर्ज की बड़ी भारी कमी होने की बात करते आ रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि प्रदेश में डॉक्टर्ज की कमी को पूरा करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी किसी भी सूरत में विपक्ष के विधायकों की नहीं है। जब प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं की बात आई तो मंत्री जी खुद ही संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये। डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सीता राम यादव (अटेली) : डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा शुक्रवार, 05 मार्च, 2021 को दिये अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर सर, गत वर्ष कोविड–19 महामारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र व राज्य सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाये जिनका नतीजा यह हुआ कि देश में कोविड–19 महामारी की संक्रमण दर बहुत कम रही। मैं कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, दूसरे सभी विभागों के कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों और कोरोना योद्धाओं द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा करता हूं। कोरोना वैक्सीन की खोज करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल. परिवारों और असहाय लोगों तक राशन पहुंचाने में सहायता करना, प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाना, परिवार पहचान पत्र बनाना, निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत हरियाणावासियों को आरक्षण देकर सरकार ने ये जो सारे कार्य किये हैं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप–मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एम.एस.पी. पर फसल खरीदने, ओलावृष्टि आपदा आदि में किसानों को मुआवजा देने, राजस्व विभाग में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड व गांवों को लाल डोरा मुक्त करने, प्रदेश में पशु चिकित्सा गौशाला अनुदान, पशु ज्ञान केन्द्र खोलने, सिंचाई से वंचित दक्षिणी हरियाणा में पम्पों का नवीनीकरण व मरम्मत करके आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने व एस.वाई.एल. नहर पर सरकार बड़ी गम्भीरता से कार्य कर रही है। इन सभी कार्यों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत भागीदारी देना, सरकारी आंगनवाड़ी केन्द्र, ग्रामज्ञान केन्द्र,

पशु चिकित्सा आदि को बढ़ावा देने का जो काम सरकार कर रही है वह बहुत ही सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत वाटरशेड दीनदयाल उपाध्याय अन्तोदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह, सरकारी चीनी मिलों, दुग्ध उत्पादक आदि योजनाओं को बढ़ावा देना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत लेनदेन शुरू करने पर देश में हमारे राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कोविड–19 महामारी के दौरान भी एम.एस.पी. पर लाखों मीट्रिक टन गेहूं, सरसों, धान व बाजरे की खरीद हरियाणा सरकार ने की है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार टीकाकरण की शुरूआत, स्वास्थ्य व फ्रंटलाईन कर्मचारियों व वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त टीका उपलब्ध करवाने का, 8 लाख आयुष्मान कार्ड जारी करने, सरकार द्वारा आयुर्वेदिक औषधालय व आयुष विश्वविद्यालय खोलने पर मैं सरकार को बधाई देता हूं। इसी प्रकार से सरकारी अस्पतालों को मैडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने पर तथा नर्सिंग संस्थानों की स्थापना करने पर भी सरकार बधाई की पात्र है। शिक्षा के क्षेत्र में 4000 प्ले वे स्कूल खोल कर सरकार ने एक नई शुरूआत की है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नीट और जे.ई.ई. की परीक्षाओं के लिए एस.सीज. स्टूडैंट्स को मुफ्त कोचिंग सरकार द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। जिला स्तर पर संस्कृति मॉडल स्कूल खोलना तथा पहली से आठवीं तक के बच्चों को सूखा राशन घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करके सरकार ने रोजगार के नये विकल्प तैयार किये हैं जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके अतिरिक्त हर घर को नल से जल उपलब्ध करवाने के लिए जो योजना बनाई है जिसके 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार से सरकार ने नगर निगमों, नगरपालिकों और नगर परिषदों के चुनाव सफलतापूर्वक करवाने का जो काम किया है उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक केवल अढ़ाई रुपये प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध कराना भी अच्छा कदम है। नये सब–डिविजन व डिविजनों की क्षमता बढ़ाने का कार्य करना भी बहुत सराहनीय है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष

महोदय, इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र की दो–तीन मांगों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिक्कत कच्चे रास्तों की है जोकि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 16.02.2020 को गांव दोंगड़ा अहीर में एक घोषणा की थी कि जो भी 6 करम के रास्ते एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं उनको पी.डब्ल्यू.डी., (बी. एण्ड आर.) विभाग से पक्का करवाने का काम करें और जो 5 करम के रास्ते एक गावं से दूसरे गांव को जोड़ते हैं उनको हर साल 50 किलोमीटर तक मार्केटिंग बोर्ड द्वारा पक्का करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सीता राम जी, आप अपनी बाकी डिमांड्स को रिटन में दे दें, उनको प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बना दिया जाएगा।

श्री सीता राम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जो 22 फीट के रास्ते हैं उनको पंचायती राज विभाग द्वारा पक्का करवाया जाए। इसी के साथ मेरी अटेली विधान सभा के नौ गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 हजार के आस–पास है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन गांवों को महाग्राम योजना में शामिल किया जाए और वहां ट्रीटमैंट प्लांट लगाकर उन गांवों को सीवरेज सिस्टम से जोड़ा जाए। इसके बाद समय कम होने की वजह से उपाध्यक्ष महोदय के कहने पर मैं अपनी बाकी डिमांड लिखित में दे रहा हूं कृपा करके मेरी इन सभी डिमांड्स को प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बनाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सीता राम जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है। अब आप प्लीज बैठ जाईये।

श्री सीता राम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र अटेली की कुछ और मांगे भी हैं जो मुझे अभी कहनी हैं। अगर आपकी सहमति हो तो मैं इनको सदन के पटल पर रख देता हूं। आप इनको प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बनवा देना।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, अगर आपकी इसके अतिरिक्त कुछ और मांगे हैं तो आप उनको रिटन में दे दें, उनको प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बना दिया जाएगा।

* **श्री सीता राम यादव** : ठीक है जी। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी निम्नलिखित मांगें हैं:– उपाध्यक्ष महोदय, अटेली विधान सभा में 9 गांव क्रमशः बाघोत, सेहलंग, खेड़ी तलवाना, धनौन्दा, पाथेड़ा, भोजावास, दोंगड़ा अहीर,

---

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

कांटी व मिर्जापुर बाछोद ये बड़े गांव हैं और इनकी आबादी 10 हजार है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन गांवों को महाग्राम योजना से जोड़ा जाए और इन गांवों में ट्रीटमैंट प्लांट लगाकर इनको सिवरेज सिस्टम से जोड़ा जाए। इसी के साथ अटेली विधान सभा में निम्न सड़कों पर वाहनों का आवागमन बहुत ज्यादा है और उन सड़कों पर दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अटेली विधानसभा की निम्नलिखित सड़कों को चार मार्गीय किया जाए। रेवाड़ी–महेन्द्रगढ़ रोड पर भडफ बस स्टैण्ड से उन्हानी मोड़ से बाघोत के बोर्डर तक, कनीना में अटेली टी प्वाईंट से वाया अटेली, भेजावास, सेदपुर तथा बिहाली से होती हुई खेड़ी बोर्डर तक, अटेली से महेन्द्रगढ़ रोड तथा अटेली कनीना रोड से मोहनपुर बस स्टैण्ड से फैजाबाद चौंकी महेन्द्रगढ़ रोड वाया दोंगडा अहीर, बेवल और सीहमा तक आदि सड़कों को चारमार्गीय किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ जिले में पुलिस थानों में चौंकियां बहुत कम हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री व गृहमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ जिले में महावीर चौंक, कनीना शहर और निजामपुर में थाना तथा सेहलंग व भोजावास में पुलिस चौकी बनाने की कृपा करें जिससे कि लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके। इसी के साथ उपाध्यक्ष महोदय, अटेली विधान सभा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में दो छोटी–छोटी नगरपालिकाएं हैं। इस क्षेत्र में केवल खेती–बाड़ी ही मुख्य साधन है। आपके माध्यम से मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो अवार्ड बावल क्षेत्र में सरकार द्वारा वर्ष 2016 में रद्द किया गया था जिसमें 4700 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई थी लेकिन किसानों तथा सरकार की रेट में सहमति न होने की वजह से सरकार ने अवार्ड रद्द कर दिया था। अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव बजाड, गनियार, अटेली, बेगपुर और बिहाली आदि गांवों के किसानों की जमीन का सर्वे भी किया गया था लेकिन यह प्रोजैक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रोजैक्ट का कुछ हिस्सा जो 1200 एकड़ के लगभग है और जो नांगल चौधरी के गांव घाटाशेर, बशीरपुर, तलोट आदि में घोषित हो गया जिसमें 100 एकड़ भूमि के करीब सरकार ने खरीद ली बाकी लगभग 3500 एकड़ भूमि का अवार्ड अटेली विधन सभा क्षेत्र के गांव बजाड, गनियार, अैली, बेगपुर, बिहाली आदि गांवों में किया जाये। जिससे यह क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हो सके तथा जिससे यहां रोजगार का सृजन होने से बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके। इसी के साथ उपाध्यक्ष

महोदय, अटेली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कृष्णावती नदी से कोजिंदा, शाहपुर दोयम, सराय बहादुर, कुंजपुरा, भीलवाड़ा, ताजपुर, नांगल तथा नीरपुर राजपूत (खण्ड अटेली नांगल) तक हरियाणा सरकार ने 1967 में लगभग 15 कि.मी. कच्ची नहर बनाने के लिए जमीन अधिगृहित की थी, उक्त कच्ची नहर की खुदाई की जाए। जिसमें बरसात के दिनों में पानी छोड़कर पानी को रिचार्ज किया जाए, जिससे पानी का जलस्तर ऊपर आ सके और किसानों को सिंचाई में फायदा हो सके। इस महान सदन ने मेरी बात को शांति से सुना उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सुरेंद्र पंवार (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के से संबंधित एक–दो बात रह गई हैं, इसलिए आपकी अनुमति से एक मिनट और बोलना चाहता हूं। मेरी सोनीपत विधान सभा में कम से कम 50–60 हजार मकान ऐसे हैं जो सोनीपत नगर पालिका बनने के वक्त के होंगे। उन मकानों में जो लोग बसे हुए थे वे 70–80 साल से किराए पर बैठे हुए हैं। आज कॉरपोरेशन उनसे 100 रुपये प्रति महीना किराया ले रही है। सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि उन लोगों को मालिकाना हक देने का काम करें। पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में एस.सीज. और बी.सीज. जाति व गरीब परिवारों को 100–100 गज के प्लॉट दिये गये थे लेकिन वे लोग 50–50 गज के मकानों में बैठे हुए हैं। अगर सरकार उन परिवारों को मालिकाना हक दिलवाने का काम करेगी तो यह बड़े उपकार का काम होगा। इसी तरह से सोनीपत में ड्रेन नं. 6 को जो पक्की करने का काम चल रहा है उसके बीच में 1000–1500 घर आते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर उन लोगों के घर बच सकते हैं तो उनको बचाया जाए, अगर नहीं बच सकते हैं तो उनको वहीं कहीं आस–पास में जमीन देकर बसाने का काम करे लेकिन सरकार उनको उजाड़ने का काम न करें बल्कि उनको मालिकाना हक दिलवाने का काम करें। यही सरकार से मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। जस हिन्द।

श्री चिरंजीव राव (रिवाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आज मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। जब मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने आखिर इसको क्यों नहीं पढ़ा, क्यों जब मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि

मैं शायद कपिल शर्मा का कॉमेडी नाईट शो देख रहा हूं। इस अभिभाषण के अन्दर सारी बातें झूठ थी।

श्री उपाध्यक्ष : चिरंजीव राव जी, राज्यपाल महोदय, यह तो कह ही सकते हैं कि अभिभाषण पढ़ा हुआ समझा जाए, जरूरी नहीं कि वे सारा ही अभिभाषण पढ़ें।(**इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।**)

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह खुद कह रहा हूं कि उन्होंने शायद इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे स्वयं लगा कि शायद मैं कॉमेडी कपिल शर्मा का नाईट शो देख रहा हूं लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण की शुरूआत कोरोना से की। कोरोना काल को हम सब कैसे भूल सकते हैं। वह एक ऐसा समय था जिसमें हमारे लाखों प्रवासियों को पैदल पलायन करना पड़ा था।

श्री अध्यक्ष : चिरंजीव राव जी, आप गवर्नर एडर्स पर बोल रहे हैं और गवर्नर एड्रैस के बारे में बात कर रहे हैं। यह सदन कपिल शर्मा का कॉमेडी शो नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को और सब्जैक्ट को ठीक रखियेगा। आप केवल गवर्नर एड्रैस पर बोलिए। आप इस अभिभाषण को कॉमेडी कपिल शर्मा का शो बता रहे हैं।

श्री राव चिरंजीव : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको झूठ का पुलिंदा बता देता हूं। अगर आपको वह शब्द पसंद नहीं आ रहा है तो मुझे गवर्नर एड्रैस झूठ का पुलिंदा लगा।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आप संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें।

श्री राव चिरंजीव : अध्यक्ष महोदय, लॉक डाउन में हमारे लाखों श्रमिकों को हरियाणा से पलायन करना पड़ा। जो यह पलायन हुआ उसमें लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, इस बात का सदन को भी पता है। मैं गवर्नर एड्रैस में पढ़ रहा था कि लाखों लोगों को लॉक डाउन के दौरान राशन बंटवाया गया। इस सदन में इतने सारे विधायक बैठे हुए हैं आप लोग मुझे बता दीजिए कि कितने ऐसे लोग थे जिनको सरकार ने उस समय में राशन वितरित किया था? अध्यक्ष महोदय, जहां तक महंगाई की बात है जब पैट्रोल– डीजल के दाम 60 रूपये के आस पास होते थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग आधे नंगे होकर प्रदर्शन किया करते थे। मेरे हाथ में यह फोटो है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि यह लोग आधे नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन आज इनके राज में पैट्रोल–डीजल का रेट 100

रूपये से भी ज्यादा हो गया है पर आज यह लोग न तो किसी प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं और न कुछ बोल रहे हैं। आज एल.पी.जी. के सिलेंडर की कीमत 850 रूपये से भी ज्यादा हो गई है लेकिन यह लोग उसके उपर भी बात नहीं कर रहे हैं। पिछले 100 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख–हड़ताल करके रोड्ज पर बैठे हुए हैं लेकिन सरकार ने एक बार भी उनकी सुध लेने का काम नहीं किया है। महिला सुरक्षा के विषय पर बड़ी–बड़ी बातें कहीं जाती हैं, के परिपेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां मोहनपुर गांव में एक दलित लड़की जोकि पिछले कई सालों से लापता है, पुलिस आज तक उसका सुराग नहीं लगा पाई है। मैंने इस बारे में पिछले सत्र में भी आवाज उठाई थी कि इसकी सी.बी.आई. इंक्वायरी करवाई जाये लेकिन बावजूद इसके इस दिशा में कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए गए। जहां तक आवारा पशुओं की बात है, सरकार द्वारा आवारा पशुओं से मुक्ति के विषय पर बड़ी–बड़ी बातें कही जा रही हैं। सरकार कहती है कि हमारा प्रदेश आवारा पशुओं से मुक्त प्रदेश है परन्तु मैं शहर में रहने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बात में कहीं भी सच्चाई नज़र आती है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को तो सत्ता में आए अभी छह साल ही हुए है। रेवाड़ी का तो इससे पहले भी बुरा हाल था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री चिरंजीव रावः अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि रेवाडी का बुरा हाल है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे प्रदेश का बुरा हाल कर दिया है। अभी टोहाना के विधायक देवेन्द्र बबली जी ने अपने एरिया के सिविल हॉस्पिटल के हालत बयान किए थे ठीक उसी प्रकार के हालात हमारे सिविल हॉस्पिटल के भी बने हुए हैं। अगर सबसे कम डॉक्टर किसी जगह पर हैं तो वह हमारे रेवाड़ी में हैं। धारूहेड़ा स्थित पी.एच.सी. में एक भी एंबुलैंस नहीं है और न ही कोई दूसरी मशीनरी अवेलेबल है। पिछले दिनों जब यह कोरोना महामारी आई थी तो उस वक्त यहां पर वेंटिलेटर तक उपलब्ध नहीं थे। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कम से कम हमारे सिविल हॉस्पिटल में तो वेंटिलेटर की सुविधा प्रदान करवाई जाये। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं भी की हैं लेकिन बावजूद इसके आज तक हमारे दक्षिण हरियाणा में कोई भी सैनिक स्कूल नहीं बनाया गया है और न यहां पर कोई डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार 75 पार का झूठा नारा देकर सत्ता में आई। आज मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सबका साथ– सबका विकास की बात की

जाती है लेकिन हमारे दक्षिण हरियाणा के मनेठी के एम्स बनाने के लिए सरकार ने एक ईंट तक लगाने का काम नहीं किया। हमारे रिवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए एक ईंट तक लगाने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिह यादवः अध्यक्ष महोदय, अगर यह जमीन दिलवा दे तो सरकार यह काम भी कर देगी।

श्री चिरंजीव रावः अध्यक्ष महोदय, जमीन दिलाने का काम सरकार का होता है। यह व्यक्तिगत काम नहीं होता है। हमारे उप–मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद हैं। यह निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 परसेंट आरक्षण प्रदान करने वाली स्कीम लेकर आये हैं जिसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करते हुए कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश में ऐसे हालत बनते जा रहे हैं कि जो उद्योग प्रदेश में पहले से लगे हुए हैं, वे प्रदेश से बाहर जाते जा रहे हैं। अतः इन उद्योगों को प्रदेश से बाहर जाने से रोकने की हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नए उद्योगों का विषय तो इसके बाद ही आयेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से तथा उप–मुख्यमंत्री जी से एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि निजी उद्योगों में 10 परसैंट लोकल युवाओं को लगाने की जो कैप रखी गई है इसमें भी बदलाव की बहुत आवश्यकता है क्योंकि गुरूग्राम, फरीदाबाद तथा रिवाड़ी यह ऐसे जिले हैं जहां पर प्रदूषण की बहुत ज्यादा समस्या है और यहां पर वाटर भी कैमिकल युक्त मिलता है। प्रदूषण और कैमिकल युक्त पानी से प्रभावित इन क्षेत्रों के युवाओं को भी अगर 10 परसेंट के हिसाब से लोकल इंडस्ट्रीज में रोजगार दिया जायेगा तो यह इन युवाओं के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। अतः इन क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत के कैप को ज्यादा बढ़ाकर यहां के युवाओं को होने वाले नुकसान की भरपाई करने का काम सरकार को करना चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आज मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भय अगर किसी के अंदर है तो वह मीडिया के अंदर है। यह सब लोग चुप रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, कोई घोटाले की बात तक नहीं करता है तथा कोई महंगाई की बात नहीं करता है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को इनके उपर थोड़ा कंट्रोल कम करना चाहिए क्योंकि इनको देश के तीसरे स्तम्भ के रूप में जाना जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि कल सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जायेगा और जजपा और निर्दलीय विधायक अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करेंगे तो कृपया

करके उनके ऊपर ई.डी./सी.बी.आई. रेड की सिफारिश न करे। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात और आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि दाढ़ी बढ़ाने से झूठ नहीं छिपते। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

श्री प्रमोद कुमार विज (पानीपत शहर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे एक बार तो ऐसा लग रहा था कि मुझे बोलने का समय ही नहीं मिलेगा, फिर भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत–बहुत शुक्र गुजार हूँ। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2020–21 तो कोविड–19 वैश्विक महामारी के भेंट चढ़ गया है। क्या हमने कभी यह सोचा था कि इस महामारी के दौरान ऐसे–ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे? क्या हमने कभी यह सोचा था कि इस महामारी के दौरान लाखों लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा? क्या हमने कभी यह सोचा था कि इस महामारी के दौरान लाखों लोगों के लिये राशन और मैडिकल सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी? क्या हमने कभी यह सोचा था कि इस महामारी के दौरान लाखों मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी? और क्या हमने कभी यह सोचा था कि लाखों लोगों को घरों में कैद रहना पड़ेगा? इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये पूरे प्रदेश में ठीक ढंग से व्यवस्था की थी। जिसकी प्रशंसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी की थी। हरियाणा सरकार की तरफ से इस महामारी के दौरान सभी निर्वाचन क्षेत्रों और सभी वर्गों का ख्याल रखा गया था। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने अपने–अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सर्दी–गर्मी, धूप–छांव व दिन–रात खेतों में काम करता है और देश का पेट भरता है जबकि हम सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों के साथ व गर्मी के मौसम में ए.सी. के कमरों में रहते हैं लेकिन किसान वर्ग खेतों में काम करता रहता है, इस बात को हम सभी लोग मानते हैं। मुझे एक फिल्म का डायलॉग अच्छी तरह से याद है। बॉर्डर फिल्म में यह कहा गया था कि–

'हमीं हम है तो हम क्या है, तुम्हीं तुम हो तो तुम क्या हो।

हम है तो तुम हो, तुम हो तो हम हैं।'

अध्यक्ष महोदय, किसान भाइयों का हम सभी लोग मान सम्मान करते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किसान आंदोलन को राजनीति का आंदोलन बना रखा है। किसान आंदोलन में किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं, जिससे व्यापारियों के उद्योग–धंधे चौपट हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष कहता है कि प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि जिसने विकास को देखना है वह पानीपत में आकर देखें। भारत वर्ष में हजारों की संख्या में ब्लैंकेट के कंटेनर चाइना से आते थे लेकिन आज एक भी कंटेनर चाइना से नहीं आता है क्योंकि आज 100 प्रतिशत ब्लैंकेट की मैन्यूफैक्चरिंग पानीपत में हो रही है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) कांग्रेस पार्टी ने व्यापारियों की चिंता कभी भी नहीं की बल्कि उनका शोषण ही किया है। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस पार्टी को न तो किसानों की चिंता है और न ही व्यापारियों की है। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी और राजनीति के कारण किसानों द्वारा रास्ते रोकने से करोड़ों रुपयों की लागत से सैंकड़ों की तादाद में उद्योग–धंधे ठप्प हो गये हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की एम.एस.एम.ई. (माइक्रो स्माल एण्ड मीडियम एंटरप्राइज) योजना थी। इस योजना के अन्तर्गत व्यापारियों को 2.4 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से पैसा मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा उद्योगों को बढ़ावा देती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात भी सदन में कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रयासों से पानीपत के लोग पूरी तरह से सक्षम हैं और पानीपत का एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हरियाण में सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को जो 75 परसैंट आरक्षण दिया है वह हमारी सरकार की एक बहुत अच्छी सोच है । हरियाणा के युवाओं को रोजगार की सख्त जरूरत है । मेरा सुझाव है कि जब इसकी डिटेल वर्किंग की जाए तो उसमें पानीपत, जगाधरी, यमुनानगर, गुरूग्राम और फरीदाबाद के उद्योगपतियों के भी सुझाव ले लिये जाएं । अब मैं जल के विषय में कुछ कहना चाहूंगा । हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी जल के विषय पर बहुत चिन्तित हैं । मुझे नहीं पता कि फील्ड के अधिकारी सरकार को पानीपत में पानी के प्रतिदिन दोहन का ठीक डाटा देते हैं या नहीं लेकिन मैं अनऑफिशियली बताना चाहता हूं कि

पानीपत में 15 करोड़ लीटर पानी का प्रतिदिन दोहन होता है । यह फिगर इतनी बड़ी है कि इसे सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी । पानीपत में बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है । इसका कारण यह है कि वह पानी रिसाइकिल नहीं हो रहा है । इसके लिए हमें 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' (जैड.एल.डी.) की जरूरत है । मेरी प्रार्थना है कि पानीपत में इंडस्ट्रीज के वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करने के लिए जैड.एल.डी. सिस्टम स्थापित किया जाए । जैड.एल.डी. की कॉस्ट लगभग 1600 करोड़ रूपये है । मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि पानीपत में जैड.एल.डी. जल्द से जल्द अरेंज किया जाए । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिस प्रकार से अलग–अलग बिंदुओं के माध्यम से सरकार के कार्यों को इंगित किया है उससे मैं एक चीज सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, क्या प्रदेश के उप–मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पर बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : गीता जी, प्रदेश के उप–मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल सकते हैं । He is also a Member of the House. He can speak. Why not?

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, उप–मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सरकार को सपोर्ट करने के लिए बोलेंगे । माननीय सदस्य बोलेंगे, but minister will not speak. It is not a tradition or precedent that a Minister will speak in support of the President's Address or the Governor's Address.

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बतरा से आग्रह करता हूं कि क्या उनका कोई प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है ? इसके अलावा माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल ने कल सदन में सभापति के रूप में सदन की परम्पराओं को आगे बढ़ाया था । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, कल 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर हमको हाउस को चलाने का मौका दिया गया था । मुझे लगता है कि माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को इससे तकलीफ हुई है । (विघ्न)

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कल 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' था । मैं तो कल आपसे पूछना चाहता था कि आप अपनी प्रदेश अध्यक्ष के साथ हैं या सदन में अपनी पार्टी के नेता के साथ हैं?(शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्या को सरकार के खिलाफ कुछ काम करना है तो वह कल कर लें । अब मैं अपनी बात रख रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया । वर्ष 1990 में पूर्व उप–प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी लोकसभा के सदस्य थे तो उस समय उन्होंने लोकसभा में मांग रखी कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का पार्लियामैंट में स्टैच्यू लगवाया जाए । अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं इस विधान सभा का सदस्य और प्रदेश का उप–मुख्यमंत्री हूं तो आपने विधान सभा में बाबा भीमराब अम्बेडकर जी का जो स्टैच्यू लगवाया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं । महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदन में सरकार के चहुंमुखी विकास की बात रखी । माननीय सदस्य राव चिरंजीव कह रहे थे कि हरियाणा से इंडस्ट्रीज पलायन कर रही हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में सवा साल में लगभग 17,500 करोड़ रूपये की इनवेस्टमैंट आई है । इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी लीथियम आयन बैटरी बनाने वाली कम्पनी ने आई.एम.टी., सोहना में 7,500 हजार करोड़ रूपये लीथियम आयन बैटरी की मैनुफैक्चरिंग के लिए इनवैस्ट किया है । इस प्रकार हमारी सरकार के कार्यकाल में इन्डस्ट्रीज का पलायन नहीं हुआ है बल्कि उनका विश्वास बढ़ा है। यह हमारी सरकार की नीतियों का ही नतीजा है। फिर उसमें चाहे स्टेट की नयी एन्टरप्राईज एंड इम्पलायमैंट पॉलिसी बनाने की बात हो, हमारे युवा साथियों के लिए 75 प्रतिशत प्राईवेट सैक्टर की नौकरियों में रिजर्वेशन की बात हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स पर प्रोडैक्ट की कलस्टराइजेशन की बात हो या हरियाणा प्रदेश में पहली बार एम.एस.एम.ई. के लिए अलग डायरैक्टोरेट बनाने की बात की हो, हमारा यही प्रयास रहा है कि इन्डस्ट्रीज फ्रैंडली एन्वायरमैंट बनाकर नये उद्यमियों को जोड़ा जाए। हमारे एक युवा साथी जिनको कल बैस्ट एम.एल.ए. का अवार्ड मिला है,

उन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रखी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने एक बात कोट की थी कि लोग प्रदेश से बाहर इन्डस्ट्रीज लगा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के टाईम पर प्रदेश से कोई इन्डस्ट्री बाहर नहीं गयी है। बल्कि यह कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में हुआ था और उस दौरान लोगों पर गोलियां भी चलायी गयी थी और लाठीचार्ज भी किया गया था। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को याद होगा कि एक जी.एम. को बन्द कमरें में जला दिया गया था। आज हरियाणा प्रदेश में इन्डस्ट्रीज अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही हैं और यहां पर आकर अपना प्लांट लगाना चाहती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी सदन में सही नहीं बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के एक माननीय विधायक आज सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनको चोट लगी हुई है अन्यथा वे इस बारे में बता देते। यह हमारी सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि हमारे प्रदेश के खरखौदा में 800 एकड़ जमीन की डिमांड प्लांट लगाने के लिए आयी है। इसके अतिरिक्त सुजूकी कम्पनी ने 100 एकड़ जमीन की डिमांड की है और वे वहां पर अपना प्लांट लगाना चाहते हैं। यह हमारी सरकार की ही नीतियां हैं कि आज प्रदेश में कम्पनीज अपने प्लांट लगाना चाहती हैं। यह हमारी सरकार की प्रदेश में इन्वैस्टमेंट को लाने की नीति है। अध्यक्ष महोदय, सदन में बारी–बारी किसानों की बात की जा रही है। आज इस सदन का एक–एक माननीय सदस्य किसानों के प्रति गम्भीर है। किसानों को आर्थिक मजबूती देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात सदन के साथ सांझा करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में पिछले 2 सालों से मूंग भी परचेज की जा रही है, परन्तु इससे पहले प्रदेश में किसी भी सरकार ने मूंग की परचेज नहीं की। मक्का की फसल को 1850 रुपये प्रति क्विंटल की एम.एस.पी. पर 4085 मीट्रिक टन खरीदा गया है। इतिहास के अन्दर पहली बार 6.75 लाख मीट्रिक टन बाजरा 2150 रुपये प्रति क्विंटल की एम.एस.पी. पर किसानों का खरीदा गया है। हमारी सरकार ने 10,700 करोड़ की पैडी खरीदी है और उसकी सारी पेमैंट किसानों के खातों में डाली जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 16,200 मीट्रिक टन सूरजमुखी को 5650 रुपये प्रति क्विंटल की एम.एस.पी. पर खरीदा गया है। अगर मैं सरसों की बात करूं तो हमारी सरकार ने 7.30 लाख

मीट्रिक टन सरसों 4425 रुपये प्रति क्विंटल की एम.एस.पी. पर खरीदी है। पिछले साल 14,250 करोड़ रुपये की गेहूं की प्रोक्यूरमैंट 1925 रुपये प्रति क्विंटल की एम.एस.पी. पर की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात सभी माननीय सदस्यों से सांझा करना चाहूंगा कि 1 अप्रैल से पूरे हरियाणा के किसानों का एक–एक गेहूं का दाना जिस तरीके से पिछली बार खरीदा गया था, उसी प्रकार से अबकी बार भी खरीदा जाएगा। कोविड–19 के दौरान अगर कहीं पर मंडियां नहीं थी तो वहां पर प्रोक्यूरमैंट सैंटर बनाकर प्रोक्यूरमैंट प्रोसैस को समूथली चलाने का काम किया था। उसी प्रकार से आने वाली 1 अप्रैल के बाद हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक किसान का गेहूं का एक–एक दाना खरीदा जाएगा। हरियाणा सरकार गेंहू, चना, सरसों और दालों के साथ–साथ इतिहास में पहली बार जौ को भी एम.एस.पी. पर खरीदने जा रही है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मंडियां इसी तरह से चलती रहेंगी तथा इनको और मजबूत किया जाएगा। आज अनेक चीजें हैं जिनको भ्रम की तरफ फैलाया जाता है। मैं सदन के साथ एक चीज और सांझा करना चाहूंगा कि यह पहली बार हुआ है कि हमारे प्रदेश के किसानों का एक–एक दाना मंडियों से प्रोक्यूर करके स्पैशली उनके खातों में उनकी फसलों की पेमैंट सीधी पहुंचायी गयी। पहले हमें पेमैंट करने में 21 दिन का समय जरूर लगा होगा क्योंकि उस टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहली बार हुआ था। हमारा प्रयास रहेगा कि 1 अप्रैल के बाद जैसे ही किसानों की गेहूं की फसल खरीदी जाएगी। उनके 'जे' फार्म कटने के 48 घंटों में उनकी फसलों की पेमैंट उनके खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से डाल दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज इस सदन के माध्यम से सबके साथ सांझा करना चाहूंगा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि फसलों की एम.एस.पी. खत्म हो जाएगी। मैंने पहले दिन भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं कि जब तक हम हमारी सरकार है, हम किसानों की फसलों का एक–एक दाना एम. एस.पी. पर खरीदने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहुत से लोग कह रहे थे कि कांट्रैक्ट फार्मिंग आ गयी है। हमारे कांग्रेस के साथी श्री भारत भूषण बत्तरा जी ने इस महान सदन में कल कहा था कि हुड्डा साहब के कार्यकाल के दौरान कांट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लॉ लाने का काम किया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में कांट्रैक्ट फार्मिंग में लॉ लाने का काम किया गया है वहीं आज दूसरी तरफ इसके द्वारा उस लॉ का विरोध करने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब यह है

18:00 बजे

कि कांग्रेस पार्टी द्वारा दोगली नीति अपनाई जा रही है क्योंकि आज वह उल्टा कांट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध भी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि इस हाउस में यह बात समझा दें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान जो एक्ट लाया गया था, ये उसके साथ खड़े हैं या उसके विरोध में खड़े हैं? यह बात इस महान सदन में माननीय हुड्डा साहब खुद खड़े होकर बता सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है कि एम.एस.पी. खत्म हो जायेगी और कांट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों में भ्रम फैल जायेगा। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि जो आपकी दोगली सोच है उसके कारण कृषि क्षेत्र कहीं न कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में माननीय उप–मुख्यमंत्री द्वारा जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया कि हमारी दोगली सोच है तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह सोच हमारी नहीं है यह सोच तो हरियाणा सरकार की है। हमारी सरकार के समय में हम कांट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लेकर आये थे। हम आज भी प्राईवेट इन्वैस्टमैंट का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसान के इन्ट्रस्ट वाच किये जायें और उसके बाद ही कानून बनाये जायें। इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हम इस महान सदन में प्राईवेट मैम्बर बिल लेकर आये थे ताकि कृषि से संबंधित हरियाणा सरकार भी अपना अलग से कानून बनाये।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय हुड्डा साहब ने इस महान सदन में छाती ठोकर अपनी बात स्वीकार की है कि इनकी सरकार के समय में यह कांट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लेकर आये थे। मैं हुड्डा साहब से कहना चाहता हूं कि यह बात पूरे देश और प्रदेश को बतानी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में जिस एक्ट को बनाया था वही एक्ट तो हमारी सरकार लेकर आई है और अब वही एक्ट केन्द्र सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया है। मगर कांग्रेस पार्टी किसानों के बीच में जाकर बोलती है कि तीनों कृषि कानून लागू होने से किसान बर्बाद हो जायेगा। मैं यहां पर यह बात बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार न तो मंडियों को कमजोर होने देगी, न ही मंडियों को खत्म होने देगी बल्कि मंडियों को और बेहतर तरीके से बनाने का काम किया जायेगा। हमारी सरकार किसानों के खातों में पैसा भेजकर उसको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का काम करेगी। मैं पिछले 104 दिनों से किसान आंदोलन की तरफ देख रहा हूं। मुझे इस आंदोलन से

एक चीज जरूर समझ में आ गई है और अक्सर चौधरी देवी लाल जी भी इस बारे में एक बात कहा करते थे कि किसान को समझाना मुश्किल है लेकिन उसको बहकाना आसान है। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन यही लोग जो कानून बनाने वाले है, कानून लिखने वाले हैं वे किसानों के बीच में जाकर उनको बहकाने का काम कर रहे हैं। यह बात देश के किसानों को समझने की जरूरत है कि कौन बहका रहा है? (विघ्न) आज देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हालत क्या हो चुकी है, यह बात जगजाहिर है। आज अगर साउथ इंडिया के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछा जाये तो वे केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देंगे और नॉर्थ इंडिया इनके नेताओं से पूछो तो विपक्ष में खड़े हुए दिखाई देंगे। आज देखने वाली बात है कि किस तरीके से आज किसानों को बहकाने का काम किया जा रहा है। मैं यह बात इनके साथ जरूर सांझी करना चाहूंगा कि जहां हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक मजबूती दी है वहीं रूरल डिवैल्पमैंट के अंदर ऐतिहासिक कदम उठायें हैं। पहली बार प्रत्येक गांव को ऐतिहासिक तौर पर अधिकतम पैसा डिवैल्मैंट के लिए दिया है। इसके अलावा हमारी सरकार ने जिला परिषद् को भी पावर दी है ताकि वह ए.डी.सी. लैवल पर अपनी पैरवी कर पाये और गांव में जो सबसे छोटी सरकार होती है, वे गांव में अधिक से अधिक विकास कार्य करवा पायें। मै समझता हूं कि ऐसा पहली बार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐतिहासिक डाटा निकालने का मौका मिला था। मुझे इस बात का पता चला कि जिन्होंने प्रदेश में 10–10 साल तक राज किया, उन्होंने जिला परिषद को एक साल में डेढ़ करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये की अनुदान राशि से ज्यादा नहीं दी थी लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने एक–एक जिला परिषद को 25 करोड़ रुपये, 30 करोड़ रुपये और 40 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक साथी हैं वे पहले सत्ता पक्ष में हुआ करते थे, उस वक्त भी मुख्यमंत्री जी के सामने हाथ फैलाने का काम किया करते थे। हमारी सरकार ने चाहे वह सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, उनको ''विधायक आदर्श ग्राम योजना'' के तहत 5–5 करोड़ रुपये की एडिशनल राशि दी है। (विघ्न) मैं हुड्डा साहब से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री सुभाष गांगोली जी इस महान सदन में बैठें हुए हैं, इनसे पूछ लो कि ''विधायक आदर्श ग्राम योजना'' के तहत 5 करोड़ रुपये की राशि मिली कि नहीं मिली, श्री

शीशपाल जी भी बैठे हुए हैं, चाहे तो इनसे पूछ लो। इस महान सदन में कांग्रेस पार्टी के सदस्य खड़े होकर बोलने लग जाते हैं कि किसी भी विधायक को विकास के लिए कोई फंड नहीं दिया गया। (विघ्न) कल इस महान सदन में माननीय सदस्य श्री वरुण चौधरी जी ने एक सवाल पूछा था कि मुझे ''विधायक आदर्श ग्राम योजना'' के तहत 5 करोड़ रुपये की राशि नहीं मिली। (विघ्न) मैंने इस महान सदन में इन बातों का जवाब दिया है कि जब इनकी तरफ से डिमांड ही 75 लाख रुपये की आई है तो फिर 1 करोड़ रुपये देने का क्या औचित्य बनता है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार के पास कोई भी विधायक सवा चार करोड़ रुपये की डिमांड लिखकर भेजेगा तो सरकार उसको सवा चार करोड़ रुपये की ग्रांट देगी। ऐसा तो नहीं है कि उसको 5 करोड़ रुपये की ग्रांट दे देगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सैनी साहब मुझसे खुद इस बारे में अपनी फाईल साईन करवाकर गये हैं। इसी प्रकार से किरण चौधरी जी का मेरे पास एक फोन आया उसके बाद मैंने इनकी फाईल को भी एप्रूव करके भेज दिया। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, जिस–जिस विधायक ने अपने हल्के के विकास के कामों के लिए अपने एस्टीमेट्स बनाकर देने का काम किया उन तमाम विधायकों को सी.एम. अनाउंसमैंट कोड के माध्यम से पांच–पांच करोड़ रूपये की राशि जारी की गई। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, जहां तक प्रदेश में नई इनवैस्टमैंट लाने का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहूंगा कि यह हमारे प्रदेश में पहली बार हुआ है कि हिसार से देहरादून, हिसार से धर्मशाला और दो फ्लाईट्स चण्डीगढ़ के लिए शुरू की गई हैं। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश का एक दशकों पुराना संकल्प था कि हिसार के एयरपोर्ट के रन–वे की एक्सपैंशन हो। आज हिसार में 14 हजार फीट का रन–वे अण्डर कंस्ट्रक्शन है और सरकार उसे 15 महीने के अंदर हरियाणा की जनता को समर्पित करने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, मैं एक बात और आपके साथ सांझी करना चाहूंगा कि हरियाणा की सबसे बड़ी मांग थी कि इण्डस्ट्रियल डिवैल्पमैंट के लिए हमारे यहां एक ऐसा ट्रेन कॉरीडोर के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे के साथ–साथ बनाया जाये जिससे ट्रांसपोरटेशन को ईजी बनाया जाये और साथ ही साथ माल की ट्रांसपोरटेशन भी बढ़े। उसके लिए हमारी सरकार के साथ केन्द्र सरकार और प्राईवेट कम्पनीज का आज ज्वायंट वैंचर हुआ है जिसके अंदर 5618 करोड़ रूपये की लागत से पूरे के. एम.पी. एक्सप्रैस–वे के साथ पलवल से लेकर कुण्डली तक रेल कॉरीडोर बनाया जायेगा जिससे हरियाणा में उद्योगों को एक नई उच्चाई मिलेगी। मैं माननीय

सदस्य श्री सुभाष सुधा जी की स्पीच सुन रहा था। हमने अपने प्रदेश में पहला एलीवेटिड रेल कॉरीडोर रोहतक के अंदर बनाया है जिसकी कम्पलीशन एक महीने के अंदर पूरी होने वाली है। इसके साथ ही साथ हम यह भी चाहते है कि हमारे प्रदेश के दूसरे शहरों में भी रेल कंजैशन खत्म हो। रेलवे फाटकों की वजह से लोगों का ठहराव कम से कम हो इसके लिए हम दूसरे शहरों में भी एलीवेटिड रेलवे कॉरीडोर बनाने का काम करेंगे। अपनी सरकार की इसी योजना के तहत हमने कुरूक्षेत्र के अंदर एलीवेटिड रेलवे कॉरीडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है और उसका कार्य भी अलॉट हो चुका है। इस प्रकार से अब कुरूक्षेत्र शहर को भी एलीवेटिड रेल कॉरीडोर मिलेगा। इतना ही नहीं जींद शहर के अंदर जो एक बहुत बड़ी समस्या ट्रैफिक की थी हमारी सरकार ने उसको भी बाई–पास के माध्यम से ट्रैफिक को ईजी करने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात और क्लीयर करना चाहूंगा। यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहीं गई हैं। मैंने सुना कि कोई सदस्य डी.टी.पी. पर बात कर रहा है, कोई यू.एल.बी. पर बात कर रहा है और कोई माननीय सदस्य यह बात कर रहा है कि तहसील में ऐसा होता है। स्पीकर सर, हमारे प्रदेश में पहली बार ऐसी तहसीलें बनी हैं जिनके अंदर हरियाणा प्रदेश या देश का कोई भी नागरिक अगर अपनी डीड रजिस्टर करवाना चाहता है तो वह ऑनलाइन अपनी एन.ओ.सीज. एप्लाई कर सकता है, अपने प्रॉपर्टी टैक्स और डिवैल्पमैंट चार्ज के ड्यूज पे कर सकता है और तो और अब टोकन से लेकर तत्काल की अप्वायंटमैंट के लिए भी किसी को तहसील में कदम रखने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार ने आज यह नया कदम उठाया है। मैं सभी को सदन के माध्यम से यह विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि अगले 6 महीने के अंदर–अंदर हमारा प्रयास है कि प्रदेश की तहसीलों में registry from anywhere का कांसैप्ट भी लागू हो जाये अर्थात् अगर कोई गुरूग्राम का नागरिक पंचकूला में अपनी डीड रजिस्टर करवाना चाहता है तो वह प्रॉविजन देने का काम भी हमारी सरकार अगले वर्ष में करने जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि आज हमारे रेवेन्यू की बात की जाये, एक्साईज की बात की जाये और माईनिंग की बात की जाये तो हमारी सरकार ने प्रत्येक सैक्टर के अंदर कोविड–19 महामारी के बावजूद रेवेन्यू को इंक्रीज करके दिखाया है। हमारा यह संकल्प रहेगा कि आने वाले वित्त वर्ष के अंदर भी इसी जोश और उत्साह के साथ प्रदेश के अंदर इस

सरकार को हरियाणा की जनता के प्रति समर्पित करके रखें और हरियाणा के विकास के लिए पूरे तौर पर हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए ईमानदारीपूर्वक चलाने का काम करें। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, इस बजट सत्र के प्रारम्भ में हमारे हरियाणा के महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का अपना अभिभाषण दिया आज उसके ऊपर चर्चा करते हुए हम उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति धन्यवाद पारित करने का यह प्रस्ताव मंजूर करने का समय आया है। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधान सभा के अन्दर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों पक्ष रहते हैं और एक अच्छी मजबूत यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें कमियों पर भी चर्चा करते हैं। सरकार की उपलब्धियां सरकार बताती है और वह हम लोग बतायेंगे। अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष का यह काम है कि उन कमियों को उजागर करे। संविधान में यह व्यवस्था की गई है। अब यह अलग बात है कि उसकी जो आलोचना है या उसका विरोध है तो कई बार तो विरोध के लिए विरोध कर दिया जाता है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि एक परम्परा सी बन गई है कि हमने अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। मीडिया के माध्यम से जनता तक हमारी बात जाए कि हमने आपकी बात वहां रखी थी, वह ठीक है या गलत है उसका भी हम कई बार विवेक नहीं रख पाते। ठीक को ठीक कहना तो अच्छा लगता ही है लेकिन कई बार ठीक को गलत या गलत को ठीक कहना भी सदन में कई अवसरों पर हमको देखने को मिलता है। दो दिन से यह सारा काम चल रहा है। मैं आभार प्रकट करता हूं विपक्ष के लोगों का कि जिन्होंने कुछ बातें सरकार के ध्यान में करवाई हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि अगर कुछ कमी रह गई है तो आखिर यह ध्यान करवाना विपक्ष का काम है। काम करना हमारा काम है और उस पर नजर रखना विपक्ष का काम है। जनता यह चाहती है इसमें हम कहीं कोई बुरा नहीं मानते हैं। कई बार हमको सहयोग की भी अपेक्षा होती है। अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं तो यह कोरोना काल का समय निकला है। कोरोना काल का समय ऐसा था जो अनपेक्षित संकट था। इस बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार का संकट आयेगा। उसमें से हम एक

दम बाहर निकल गये हैं ऐसा तो नहीं कह सकते लेकिन वर्ष भर इस चुनौती को पार करने के लिए हमें विपक्ष का भी सहयोग मिला, जनता का भी सहयोग मिला और सभी संस्थाओं का भी सहयोग मिला। इसमें आगे बढ़ कर मैं कहता हूं कि एक प्रकार से हमने इस पर विजय पाई है। बहुत सी व्यवस्थाएं हमने की हैं। सरकारी व्यवस्थाओं के बिना कई बार चीजें आगे बढ़ नहीं पाती हैं। अगर मैं उनका उल्लेख करूं तो हमने इस समस्या से बाहर निकलने के लिए 1200 करोड़ रुपये का पैकेज तय किया था। उसमें विभिन्न प्रकार की सहायता की आवश्यकता थी जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके लिए हमने 10 लाख रुपये की राशि का बीमा करवाया था। अगर अचानक से कोई ऐसे कोरोना वॉरियर की मृत्यु होती है तो उसको 10 लाख रुपये दिया जायेगा। इसके लिए हमने एक मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड बनाया था जिसमें प्रारम्भ में ही 10 करोड़ रुपये की राशि अलग से उसमें से रखी थी। लगभग 280 या 290 करोड़ रुपये की राशि उसमें इकट्ठी भी हुई है और खर्च भी हुई है। आगे जो आवश्यकता है वह उसमें से हम पूरा करेंगे। 16 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको हमने 645 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता कोरोना काल के दिनों में दी है। बहुत से लोग जिनको राशन नहीं मिल पा रहा था, जिनके राशन के कार्ड नहीं थे, दरबदर हो गये थे उनके लिए हमने एक स्पेशल स्कीम बनाई डिस्ट्रैस राशन टोकन (डी.आर.टी.)स्कीम। यह स्कीम हमने सबसे पहले बनाई थी तो बहुत प्रदेशों ने इसका अनुसरण भी किया। इस स्कीम के माध्यम से हमने 4,86,000 परिवारों को 3 महीने तक मुफ्त राशन दिया। इसी प्रकार से नवम्बर, 2020 तक केन्द्र सरकार ने भी डबल राशन देने की जो घोषणा की थी वह भी लगातार चलता रहा। आंकड़े बहुत हैं लेकिन कुल मिला कर इतना ही है कि इन सभी व्यवस्थाओं में से चाहे वे श्रमिक जो अपने घर जाना चाहते थे, उनके लिए भी हमने व्यवस्था की। हमने अलग–अलग प्रदेशों में ट्रेन भेजी। 6600 बसों के माध्यम से 4,44,000 श्रमिकों को अपने–अपने गृह राज्यों में पहुंचाया। उनको वापिस लाने के लिए भी हमने प्रयत्न किये क्योंकि कोरोना जब समाप्त हुआ तो अपनी इंडस्ट्रीज जो कोरोना के कारण बंद हो गई थी, उसको फिर से चालू करने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उसको ठीक करने के लिए उसे हम पटरी पर लाए हैं। जो प्रदेश का नुकसान हुआ है उसको हम वापिस पटरी पर लाए हैं। चाहे वह रेवेन्यू की बात है चाहे वह खर्चे की बात है। थोड़ा बहुत अन्तर रहा होगा तो मैं समझता हूं कि इन दो महीनों में बजट के जो फाइनल आंकड़े आयेंगे, हमारे अपने अनुमान के हिसाब से थोड़ी बहुत

कमी रही होगी लेकिन हम उसके बहुत निकट पहुंच पायेंगे। प्रदेश के हर समय को अलग–अलग फोकस करने के कुछ बिन्दु होते हैं। पिछली बार के बजट में हमने बहुत सी चीजों पर फोकस किया है। हमने शिक्षा पर फोकस किया, स्वास्थ्य पर फोकस न करने के बावजूद भी उस पर खर्च करने की आवश्यकता थी तो उस पर हमने खर्च किया है। हमने किसान के लिए खेती पर फोकस किया, उसके लिए जितने खर्चे आवश्यक थे, वे सब हमने किये हैं। मैं पिछली बार के कार्यक्रम का उल्लेख करके अपनी बात को शुरू करूंगा। जब हमने ध्यान किया कि पानी एक ऐसा विषय है जिस पर हमने फोकस करना चाहिए तो वह भी हमने किया है। पानी का विषय एक प्राकृतिक चीज है कहीं इसका निर्माण नहीं होता है। हमारे पास पानी को प्राप्त करने के साधन उतने नहीं हैं जितने होने चाहिएं क्योंकि नदियों का जो जल प्रवाह है वह या तो पंजाब में है या उत्तर प्रदेश की तरफ है। हमारे यहां तो एक यमुना नदी है जिसका थोड़ा पानी हमें मिलता है, कुछ पानी यू.पी. को मिलता है, कुछ पानी राजस्थान को मिलता है और कुछ पानी दिल्ली को मिलता है। उसी का हम बंटवारा करते हैं। हमारे कई अन्तर्राष्ट्रीय संकट हैं जैसे हांसी बुटाना नहर का है, एस.वाई.एल. नहर का है लेकिन उनका उल्लेख इस समय करना ठीक नहीं है क्योंकि वह सारी कहानी हम सभी को मालूम है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वे किसी न किसी तरीके से हल हो। कहने को तो हम एक–दूसरे के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं लेकिन हर किसी को अच्छा लगेगा कि एस.वाई. एल. नहर का पानी हमें मिले, हांसी–बुटाना नहर बने ताकि जहां पानी नहीं पहुंच पाता है वहां हम पानी पहुंचा सकें। फिर भी हमने काफी प्रयत्न किये हैं। हमने लखवार डैम का समझौता किया, किसाऊ डैम का समझौता किया, रेणुका डैम का समझौता किया। आज जितना पानी हमारे पास है उसका ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और जहां पर ठीक से पानी नहीं पहुंचता था वहां ठीक से आखिर तक उसकी उपलब्धता हो जाए, वे सभी प्रयत्न हमने किये हैं। फिर भी एक विषय जो महत्वपूर्ण है, बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पानी की खपत कौन सी फसल में ज्यादा होती है। यह धान की फसल में ज्यादा होती है। उसके बारे में हमने किसानों से अपील की। उस अपील में थोड़ा रिस्क भी था। शुरू में कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। हमने किसानों से अपील की कि धान की खेती कम करें और उसके बदले में विविधीकरण के माध्यम से दूसरी फसलों की बिजाई करें। उसके लिए हमने आठ ब्लॉक छांटे थे जहां डार्क जोन एरिया था वहां पर हमने अपील की कि धान की

खेती कम से कम करनी चाहिए। उसके लिए हमने एक स्कीम बनाई कि जो किसान प्रति एकड़ दूसरी फसल पर बोएगा उसको 7 हजार रुपये का इंसैंटिव देंगे। वह इंसैंटिव हमने 2000/–रुपये तुरंत दिया और बाकी 5000/–रुपये बाद में दिया। मुझे बताते हुए खुशी है कि 96250 एकड़ जमीन ऐसी वैरिफाई हो चुकी है जिस पर लोगों ने धान न बोकर के दूसरी फसलें बोई हैं और उन किसानों को हमने इंसैंटिव का लाभ भी दे दिया है। मैं आगे भी अपेक्षा करूंगा कि इसमें प्रदेश के सभी लोग सहयोग करें क्योंकि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। चूंकि डार्क जोन एरिया बढ़ता जा रहा है और कल को पानी का संकट न हो जाए क्योंकि इसलिए इसके लिए हमने एक स्पैशल वाटर अथोरिटी बनाई है जो यह निर्धारण करेगी कि ये–ये एरिया डार्क जोन में हैं। यहां भी कुछ शिकायतें की गई कि जो एरिया डार्क जोन नहीं है उसको भी सैंट्रल वाटर अथोरिटी ने डार्क जोन घोषित कर दिया, इसलिए अपनी वाटर अथोरिटी बनाकर उस एरिया का दोबारा से निरीक्षण करने के बाद हम उस एरिया की घोषणा दोबारा से करेंगे। हम पानी की और भी योजना लाने वाले हैं जिनमें से कुछ की घोषणा हम बजट में और कुछ बजट के बाद करेंगे। जो वाटर पौंड अथोरिटी बनाई गयी है, जो वाटर अथोरिटी है या जो माईक्रो ईरीगेशन के कुछ प्रोजैक्ट्स हैं, उनका मैं निश्चित रूप से बजट में उल्लेख करूंगा। एक विषय के बारे में मुझे और बोलना था। हमारे उप–मुख्यमंत्री जी ने जो जमीनों की रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है उसमें मैं एक बात का उल्लेख करूंगा। बहुत सी शिकायतें आती थीं कि हमारे गांव का जो लाल डोरा है उसकी सीमा बढ़ा दी जाए। डिमांड यही आती थी लेकिन जब इस विषय पर अध्ययन किया गया तो पता चला कि इस लाल डोरे का संकट तो पहले ही ज्यादा है इसलिए इसको समाप्त किया जाए। इसका कारण क्या है कि अगर लाल डोरे के अन्दर किसी का कब्जा हो जाता है तो वही अपने आप को उस जमीन का मालिक मानने लग जाता है क्योंकि उसका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता है। उसमें दुनिया भर के झगड़े होते हैं। हमने सोचा कि क्यों न हम इसको सिस्टेमैटिक ढंग से करें ताकि लाल डोरे की बजाए वहां भी रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाया जाए और वंश फॉर ऑल जिसकी जमीन है आज तो उसका गवाह केवल पंचायत और ग्राम सभा है लेकिन जब उसको एक बार रजिस्ट्री मिल जाएगी और बाद में जब वह जमीन रिकॉर्ड पर आएगी तो उसके बाद उसको बेचना, उसकी मलकीयत, उस जमीन से बैंक में से कोई लाभ उठाना हो, कोई कर्ज लेना हो वे सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। यह

प्रयोग सफल भी रहा है। करनाल के सिरसी गांव से इस काम को शुरू किया गया था। दिनांक 26 जनवरी, 2019 में इसके लिए योजना बनाई गई थी और 2020 में इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया गया था। बड़ी खुशी की बात है कि इस योजना का बाद में प्रधानमंत्री जी ने भी अध्ययन करवाया और इस संदर्भ में तो मुझे स्पेशली फोन आया था कि किस प्रकार से इस योजना को बनाया और लागू किया गया है। सारा कुछ बताने के बाद इसी योजना को केन्द्र ने स्वामित्व योजना के नाम देकर पूरे देश में लागू करने का काम किया। आज लोग इस योजना के लागू होने से खुश भी है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के 6500 गांवों में से इस दिशा में लगभग 5200 गांवों का सर्वे किया जा चुका है और रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो चुका है। अभी पिछले दिनों जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रखा गया था तो उस दिन रजिस्ट्रेशन की संख्या 242 थी लेकिन उसके बाद से भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है और संभव है कि किसी न किसी फंग्शन के माध्यम से रजिस्ट्रियों को देने का काम भी शुरू कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, सदन में किसानों के विषय पर 2 दिन से खूब चर्चा हो रही है। हमारे उप–मुख्यमंत्री जी भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं इसलिए मैं समझता हूँ कि इस विषय पर मुझे आज नहीं बोलना चाहिए। मैं कल इस विषय पर बोलूंगा और पूरा बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि विपक्ष द्वारा सदन में कल नो कांफिडेंस मोशन लाया जाने वाला है। अध्यक्ष महोदय, इस नो कांफिडेंस मोशन में विषय को इस प्रकार रखने का प्रयास किया गया है जैसेकि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को अखबार के माध्यम से ही नो कांफिडेंस मोशन के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हुई जबकि विधान सभा के माध्यम से यह जानकारी सबको सर्कुलेट कर दी गई है। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, चाहे विधान सभा की तरफ से यह नोटिस सर्कुलेट हो गया है लेकिन मुझे अभी तक यह नहीं मिला है या फिर यह भी हो सकता है कि मैं देख ही नहीं पाया हूँ लेकिन बावजूद इसके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के दौरान तय हो गया था कि इस बार नो कांफिडेंस मोशन विपक्ष द्वारा लाया जायेगा। इस तरह की बात महत्व नहीं रखती, महत्व है विषय का। मैं पुनः विषय पर आता हूँ कि कल मैं किसान, सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों, प्राइवेट मैम्बर बिल तथा एम.एस.पी. के विषयों पर अच्छी प्रकार से तथा

तर्कसंगत तरीके से अपनी सारी बातें रखूंगा। वैसे न चाहते हुए भी किसी न किसी रूप में, किसी ने शुरू किया तो किसी ने जवाब दिया, ऐसा करके कई विषय और भी आ गए हैं, मैं उन सब विषयों के बारे में भी सारी बातें सदन के सामने रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब किसानों को गन्ने की पेमेंट का विषय आया तो हमारे कुछ बंधुओं ने दो शुगर मिल क्रमशः नारायणगढ़ शुगर मिल तथा यमुनानगर शुगर मिल का जिक्र किया। जहां तक नारायणगढ़ शुगर मिल का विषय है, हमने जो इसका अध्ययन किया है उससे पता चलता है कि यह एक प्राइवेट मिल है लेकिन बावजूद इसके हमारी किसान के लिए चिंता बराबर बनी हुई है क्योंकि अगर कोई मिल लगातार घाटे में जायेगी तो आगे आने वाले समय में घाटा होने के कारण मिल का मालिक कभी भी मिल को बंद करके भाग जायेगा, ऐसी स्थिति में किसान का क्या होगा, उसके गन्ने की पेमेंट कौन करेगा और उसका अगला गन्ना जो आयेगा उस गन्ने को लेकर वह कहां जायेगा? अध्यक्ष महोदय, यह मिल वर्ष 2013 से लगातार घाटे में चल रही है। अगर वर्ष 2013 में ही इसको संभाल लिया जाता तो आगे समस्या पैदा न होती। अध्यक्ष महोदय, हमने इस मिल का लगातार तीन साल तक अध्ययन किया और वर्ष 2016 में जब हमको लगा कि अगर इस मिल को नहीं संभाला गया तो वे किसान जिन्होंने अपना गन्ना उस मिल को दिया हुआ है, उस किसान की बहुत दुर्गति हो जायेगी। किसान को किसी तरह की समस्या न आये, इसके लिए हमने इस मिल को हरको बैंक के माध्यम से कर्ज दिलवाया और साथ ही यह प्रावधान भी किया कि यह शुगर मिल सरकारी अधिकारियों की देखरेख में चलेगी। आज इस मिल के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर हैं। फाईनेंस डिपार्टमैंट के अधिकारी इस मिल का फाईनेंशियल मैटर देखते हैं और एच.सी.एस. लैवल के अधिकारी को इस मिल का एम.डी. लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात भी सामने आई कि जिस साल यह मिल लगाई गई थी उस साल कई चीजों के रेट में गड़बड़ की गई थी, फर्जी कंपनियों को चीनी बेची गई थी और आवश्यकता की चीजों को हॉयर रेट पर खरीदकर इस मिल को घाटे में लाने का काम किया गया था। इस मिल को 25–26 करोड़ तक के घाटे में लाने का काम किया गया। वर्ष 2015–16 तक भी घाटे का सिलसिला चल रहा है। अब चूंकि यह प्राइवेट मिल है तो संभव सी बात है कि बहुत अंदर तक जाने का हमारे लिए कोई कारण नहीं बनता परन्तु किसानों को डी–पेमेंट्स वापिस नहीं हो रही थी, के ध्यानार्थ सरकार की कोशिश से आज इस मिल को घाटा में नहीं जाने दिया जा रहा है और इस

साल 10 करोड़ रूपये का प्रोफिट इस मिल से होगा। इस प्रकार से जो 60 करोड़ रूपये की किसानों की पैंडिंग पेमेंट है वह भी अब घटकर 50 करोड़ हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इस मिल की इंकम को बढ़ाने की दृष्टि से थोड़ी बहुत सहूलियतें देकर यहां पर बिजली निर्माण का प्रोजैक्ट स्थापित करवाया है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में गन्ने की कीमत देशभर में सर्वाधिक है। 350 रूपये प्रति क्विंटल का रेट इस देश में अन्य कहीं पर नहीं है और अगर चीनी का रेट बढ़ता है तो गन्ने का रेट और ज्यादा बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इंकम तो शुगर से ही होनी है। अब यहां पर एथनोल जैनरेशन प्लाँट के साथ पावर जैनरेशन प्लाँट भी लग गए है तो निःसंदेह इससे इंकम बढ़ेगी। मैं फिर से यह बात दोहराना चाहूंगा कि आज पूरे भारत वर्ष में हरियाणा प्रदेश गन्ने का रेट देने के मामले में नम्बर–1 पर है। प्राईवेट शुगर मिल्ज पर जब तक सरकार का लोन बकाया है या किसानों की पेमैंट बाकी है, सरकार अपना कंट्रोल उन शुगर मिल्ज पर जरूर रखेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस बात की गारंटी देती है कि हमारे गन्ना किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी जायेगी। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) अध्यक्ष महोदय, यमुना नगर की प्राईवेट सरस्वती शुगर मिल के बारे में कहा गया है कि यह मिल यू.पी. का सस्ता गन्ना लेती है और हरियाणा के किसानों का गन्ना नहीं लेती है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार की चिंता हरियाणा के गन्ना किसानों से है। यदि हरियाणा के गन्ना किसानों का बाँड भरा गया हो और वह शुगर मिल गन्ना न खरीदे तो वहां के किसानों को लिखित रूप में शिकायत करनी चाहिए। उस मिल के खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। व्यापारी तबका यहां–वहां से सस्ता या महंगा गन्ना खरीदे और उस मिल में दे यह उसका धंधा है लेकिन हमारी सरकार का मकसद केवल और केवल हरियाणा के गन्ना किसानों का हित करना है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहना चाहता हूँ कि गन्ने की बाँडिंग कम होती है और गन्ना किसानों को अपना बाकी गन्ना सस्ते रेट पर यू.पी. जाकर बेचना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना गन्ना किसानों का होता है उससे कम कर बाँडिंग होती है अर्थात् गन्ने की पैदावार के हिसाब से ही बाँडिंग होनी चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास लिखित रूप में आयेगी तो हम जांच करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, हर शुगर मिल का

कमांड एरिया होता है। अगर यमुनानगर की शुगर मिल के कमांड एरिया के गन्ना किसानों की लिखित शिकायत आती है तो हम आगामी कार्रवाई करेंगे और शुगर मिल से कहेंगे कि हमारे हरियाणा प्रदेश के गन्ना किसानों से गन्ना न खरीद कर यू.पी. से गन्ना क्यों खरीदते हो? अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में 11 शुगर मिल्ज हैं और उनमें से कई शुगर मिल 10 साल पहले या 15 साल पहले लगी हुई है। अधिकतर शुगर मिल्ज की क्रशिंग की कैपेसिटी प्रायः कम हो गई है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पलवल, सोनीपत, करनाल, असंध आदि शुगर मिल्ज की क्रशिंग की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। जैसे–जैसे शुगर मिल की ऐसी स्थिति सामने आती है तो उस हिसाब से ही हम उनकी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं और रेनोवेट भी कर रहे हैं। किसी क्षेत्र में एक आध जगहों पर गन्ना बचता होगा, ऐसी स्थिति जरूर आती होगी। पिछले दिनों पलवल शुगर मिल में तकनीकी खराबी आ गई थी लेकिन यह किसी के हाथ में नहीं है। हमारी सरकारे वहां का गन्ना रोहतक, सोनीपत, गोहाना आदि शुगर मिलों में लेकर गयी। इस प्रकार की स्थिति आ जाती है लेकिन हमारी सरकार किसी भी प्रकार से गन्ना किसानों को परेशान नहीं होने देती। अकस्मात कोई चीज हो जायेगी तो उसका तुरंत प्रबंध किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एक जानकारी यह भी देना चाहता हूँ कि करनाल की जो शुगर मिल है, उस शुगर मिल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिये रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। उस शुगर मिल में नई–नई मशीनें भी लगाई जा रही है और बॉयलर आदि की टेस्टिंग भी हो चुकी है। दिनांक 30 मार्च, 2021 तक वह शुगर मिल नई शुगर मिल के रूप में प्रारम्भ कर दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, एक विषय कानून व्यवस्था का आया था। हमारे माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स जी ने कानून व्यवस्था के संबंध में एक आंकड़ा सदन में रखा था। मुझे नहीं मालूम कि वे यह आंकड़ा कहां से लेकर आये थे? उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में क्राइम के अलग–अलग कैटेगरी के कुल 67,972 केसिज रजिस्टर हुए थे और उससे अगले वर्ष में ये केसिज 70,000 पार कर गये ।

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाऊस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जवाब कुछ ज्यादा ही लम्बा हो गया है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहता हूं कि इन्होंने पिछली बार भी मेरा जवाब पूरा नहीं सुना था । मेरा कहना है कि विपक्ष को अपना रोल जिम्मेवारी से निभाना चाहिए । विपक्ष को या तो सरकार के कार्यों की आलोचना नहीं करनी चाहिए और यदि आलोचना करते हैं तो फिर इनको पूरा जवाब शांति से सुनना चाहिए । मैं आज सदन में केवल उन्हीं विषयों पर जवाब दे रहा हूं जोकि विपक्ष ने पिछले 2 दिनों में सदन में उठाए थे । यह भी हो सकता है कि सदन में विपक्ष द्वारा उठाया गया कोई विषय कवर न हो पाए क्योंकि सदन में विषय ही इतने ज्यादा उठाए गए हैं कि सभी विषयों का जवाब देने में मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा । अभी तक मैंने सदन में जिन विषयों पर जवाब दिया है वे सभी विषय विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा ही उठाए गए थे । विपक्ष चाहे एक लाइन में प्रश्न पूछ ले लेकिन हमको तो उसका पूरा जवाब देना पड़ेगा फिर चाहे वह कितना ही लम्बा क्यों न हो । अतः हमें अपना जवाब तो पूरा ही देना पड़ेगा । क्राइम के विषय पर मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 2019 में क्राइम के कुल केसिज की संख्या 69,363 थी जबकि माननीय सदस्य ने यह संख्या 67,972 बताई थी । इसके अलावा वर्ष 2020 में क्राइम के कुल दर्ज केसिज की संख्या 60,274 थी । इस तरह से वर्ष 2020 में केसिज की संख्या बढ़ी नहीं अपितु घटी थी । वर्ष 2020 में केसिज की संख्या 9,000 कम हुई थी । मैं सिर्फ आंकड़े बता रहा हूं । मैं इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं । (विघ्न) विपक्ष के माननीय सदस्य को बोलने की जरूरत ही क्या थी कि एक साल में केसिज की संख्या 67 हजार से 70 हजार हो गये । (शोर एवं व्यवधान) अगर वे ऐसा न कहते तो मैं इसका उत्तर कभी नहीं देता। (विघ्न)

श्री कुलदीप वत्स : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास डी.जी.पी. की रिपोर्ट है और ये आंकड़े मैंने उसमें से ही देखकर बोले हैं । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य के दिए हुए आंकड़ों को कहीं पर चैक नहीं करवाना है । अगर माननीय सदस्य के पास इन आंकड़ों का कोई ऑथैंटिक सॉर्स है तो वे उनकी ऑथैंटीसिटी लेकर आयें । (विघ्न) मैं सदन में जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं वे आंकड़े डी.जी.पी., हरियाणा की रिपोर्ट से पढ़कर ही प्रस्तुत कर रहा हूं । मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य के पास कौन–सी रिपोर्ट है? (विघ्न) मैं कह रहा हूं मैं सदन में वे आंकड़े बता रहा हूं जो मुझे डी.जी.पी., हरियाणा ने दिए हैं । अगर माननीय सदस्य के आपस कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जो डी.जी.पी., हरियाणा ने उनको दिया हो तो वे बतायें अदरवाइज केवल माननीय सदस्य द्वारा अपने स्तर पर आंकड़े प्रस्तुत करने का कोई अर्थ नहीं है । मेरे पास डी.जी.पी. की रिपोर्ट है और ये आंकड़े मैंने उसमें से ही देखकर बोले हैं। (विघ्न)

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने हल्के के एक केस के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अगर मैं इस तरह से हर इंडीविजुअल मैटर पर जवाब देने लगा तो फिर इसमें बहुत समय लग जाएगा । हमें सारे प्रदेश के मुद्दों को देखना है । माननीय सदस्य मुझे ऐसी घटनाओं के बारे में लिखित में दे दें । मैं विभाग से उनका उत्तर लेकर माननीय सदस्य के पास भिजवा दूंगा । व्यक्तिगत घटनाओं की संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी । हम सदन में केवल जनरल विषयों पर ही जवाब दे सकते हैं । मुझे हर विभाग का उत्तर देना है और वह भी सिर्फ आधा–एक घंटा में ही पूरा करना है । माननीय सदस्य श्री वरूण चौधरी की ओर से कहा कि सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई के लिए एक सैल बनाने की बात कही गई थी । हाँ, हमने 'पुलिस कम्पलेंट अथॉरिटी' की स्थापना करने की बात कही थी । अब 'पुलिस कम्पलेंट अथॉरिटी' बन गई है और उसके चेयरमैन भी अप्वॉयंट हो चुके थे । दुर्भाग्यवश उनका देहान्त हो गया और अब हमने इसका चेयरमैन और इसके सदस्य पुनः नियुक्त करने हैं । इसके अलावा 'पुलिस कम्पलेंट अथॉरिटी' के रूल्ज बनाने का भी विषय था । अब इसके रूल्ज बन गए हैं और बहुत जल्दी इसका गठन हो जाएगा । एक विषय हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन का आया था । अब अगर मैं इस विषय पर जवाब दूंगा तो विपक्षी सदस्य फिर नाराज हो जाएंगे । गीता में कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई बात कही जाती है तो उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए अपितु उसको

शांति से सुनना चाहिए । सदन में पी.टी.आई. टीचर्ज का विषय उठाया गया । पी.टी.आई. टीचर्ज का विषय ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन से शुरू हुआ था । पी.टी.आई. टीचर्ज की भर्ती ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन से कैंसिल हुई थी । जब ऑनरेबल हाई कोर्ट किसी मामले में कोई डिसिजन देता है तो सरकार को उस डिसीजन को मानना पड़ता है । ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में दिया हुआ डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी अपहैल्ड हुआ । ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस डिसीजन को अपहैल्ड करने के बाद हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया और फिर उस भर्ती को रद्द किया गया । ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था उस भर्ती के कैंडीडेट्स का उन्हीं शर्तों पर दोबारा टैस्ट ले लिया जाए और तब तक न तो कोई नई भर्ती की जाए और न ही उनकी ऐज वगैरह पर कोई कट लगाया जाए । (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब जजिज ने सरकार से प्रश्न पूछा कि क्या आपके पास इन पी.टी.आईज. टीचर्ज को कहीं पर ऐडजस्ट करने के लिए कोई वेकैंसी है तो सरकार ने 'ना' में जवाब दिया था जबकि उस टाईम सरकार के पास पोस्ट्स वेकैंट थी । वे बच्चे उस समय नौकरी लग सकते थे और उस टाईम सरकार के पास पोस्ट्स भी वेकैंट थी । ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह ऑफर दिया था । ये बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज में भी हैं । ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज में यह बात है कि क्या उस टाईम सरकार के पास पोस्ट्स भी वेकैंट थी। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया गया था, उसकी वजह से ही उन बच्चों को माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में ठीक जवाब दिया जाता तो उन बच्चों को रिलीफ मिल जाती। मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी के समय में 1800 सिपाहियों को भर्ती किया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको नौकरी से निकालने का ऑर्डर कर दिया था, परन्तु हमने उनको दोबारा से नौकरी पर लगाया था। अगर कोई सरकार गलती करती है तो उसमें उन बच्चों का क्या कसूर है ? अगर हमारी सरकार ने गलती की है तो उसमें उन पी.टी.आईज. टीचर्ज की क्या गलती है ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को यह गलती ऑन कर लेनी चाहिए। अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर की डिटेल पूछना चाहेंगे तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माननीय हाई कोर्ट के डिसीजन पर ही मोहर लगायी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिखा है कि–

"I upheld the decision given by the High Court."

माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस का डिसीजन देने से पहले क्या वार्तालाप हुआ है, क्या तकरीर हुई है और क्या दलीलें दी गयी हैं ? यह एक अलग विषय हो सकता है। आज भी विपक्ष के माननीय सदस्य माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उठाकर पढ़ सकते हैं, उसमें ऐसा कोई विषय नहीं है। दूसरी बात माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है कि –

"Therefore, all eligible candidates be called for interview."

पहले क्या करते हैं कि candidates on the basis of minimum academic qualifications prescribed for each category but thereafter all candidates were called for interview and the reason assigned for taking such a decision is that candidates who could not be shortlisted, resorted to agitation in the House of the Chief Minister, Haryana which weighed in the mind of the Chairman of the Commission to call all the eligible candidates for interview, which again is not justified."

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब माननीय हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो सरकार के हाथ में क्या है ?

श्री अध्यक्षः बतरा जी, पहले आप माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुन लें।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस जजमैंट को नहीं पढ़ा है।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, जब एक विषय के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो उसी विषय को हाउस में बार–बार उठाने का क्या फायदा है ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही भंयकर डिसीजन दिया है। जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मैं समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल संबंधित कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने तक ही सीमित रखा

है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इससे भी आगे बढ़ सकता है और यह बात भविष्य पर निर्भर है।

Shri Bharat Bhushan Batra: What is the use of reading this here?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त यही स्थिति आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्ज के केस की है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्ज के केस में भी माननीय हाई कोर्ट ने मैच्ड डिसीजन दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पी.टी.आई. टीचर्ज के संबंध में अपने दिए गए डिसीजन के साथ ही यह डिसीजन भी क्लब किया है। यानी जो डिसीजन पी.टी.आई. टीचर्ज के विषय में दिया है, वही आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्ज के ऊपर भी लागू होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने Art and Craft टीचर्ज के बारे में लिखा है कि–

"There are basic defects in the process of the selection from the very beginning as the Commission had not been working as a multi-Member Body. There was no decision taken by the Commission as such the entire decision making was by the Chairman individually in consultation with the Secretary of the Commission. No criteria was laid down for selection before and immediately after the advertisement was issued. Rather the criteria on the basis of which the selection are sought to be justified was tailor-made."

इसमें tailor-made का मतलब यह है कि पहले ही सूची बनाकर दे दी कि इसके हिसाब से क्राईटेरिया बना दें। यह बात आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्ज के उस डिसीजन में माननीय कोर्ट ने लिखी है। यह मैंने नहीं लिखा है। अब मैं अगली बात पर आता हूं। यह कहा गया कि आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्ज के पेपर में एक एग्जामिनेशन हाल में अलग पेपर था और बाकी जगहों पर अलग पेपर था। यह सारा विषय भी क्लीयर है और इस संबंध में माननीय हाई कोर्ट का लेटैस्ट डिसीजन बता देता हूं जोकि कल ही आया हुआ है। जिन्होंने इसके लिए रिट दायर की थी, उसको माननीय हाई कोर्ट ने सैट असाईड कर दिया है। किसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाना होगा तो वह जा सकता है। पहले यह प्रॉसीजर होता था कि पहले क्वैश्चन पेपर बनते थे और उनको ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं कि क्वैश्चन पेपर कहां पर बना है ? इस प्रकार की शिकायतें हमें भी मिली हैं

और पहले भी आती रही हैं। लेकिन उसको चैक कैसे किया जाए ? इसके लिए कमिशन ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि प्रत्येक पेपर के 2 सैट बनाएंगे। एक पेपर को रैड डिब्बे में रखा जाता है और दूसरे पेपर को ग्रीन डिब्बे में रखा जाता है। उन दोनों डिब्बों को इकट्ठा भेजकर पहले चीफ एग्जामिनर से इक्वलाईजेशन करवाते हैं ताकि दोनों की मार्किंग एक जैसी हो। यानी उनमें कोई भी पेपर न तो ज्यादा मुश्किल हो और कोई न ज्यादा आसान हो। लेकिन दोनों में से कौन से डिब्बे को खोला जाएगा, उसके बारे में एग्जामिनर को भी पता नहीं होता। सिर्फ एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले संबंधित सैंटर के एग्जामिनर को मैसेज दिया जाता है कि आपने फ्लां रंग का डिब्बा खोलना है। उसमें जो पेपर निकलता है, उसी का एग्जाम लिया जाता है और दूसरा डिब्बा बन्द ही वापिस चला जाता है। इस मामले में भी यही हुआ "All the brown packets were packed in boxes with packing material, writing material, pen etc. and thereafter, these boxes were wrapped in red and green colour sheets with red and green tape. All these boxes, both red and green, were delivered in the treasury before the examination in the District Headquarter where the exam was to be held with red and green boxes. " कुल मिलाकर उन्होंने फिर उसको बोल दिया कि आप लोग जो ग्रीन बॉक्सिज है उसको खोल दो। इस बात की जानकारी उनको आधा घंटा पहले बताई गई थी लेकिन एक एग्जामिनेशन सैंटर में सैंटर सुपरिंटैंडैंट की गलती है। (विघ्न) हुड्डा साहब, ने जो बात कही है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। पेपर दो टाईप के भेजे गये थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले मैसेज भेजा गया कि ग्रीन बॉक्सिज को खोल दिया जाये लेकिन उस सैंटर के सैंटर सुपरिंटैंडैंट ने गलती से ग्रीन बॉक्सिज खोलने की बजाए रेड बॉक्सिज खोल दिया और कैंडीडेट्स को बांट भी दिया। मैं हुड्डा साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी उस एग्जामिनेशन सैंटर का रिजल्ट आया नहीं है। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य की तरफ से कहा गया है कि उस सैंटर पर एक ही जगह के बच्चे थे। यह बात गलत है। उन्होंने मुझे चैक करके बताया कि different corners of the State से बच्चे उस सैंटर पर आये थे। मैंने उनको कहा कि मुझे इस बारे में एक बार कंफर्म करके बताया जाये कि वहां पर कितने बच्चों ने परीक्षा दी और क्या उस सैंटर पर किसी एक ही जगह के बच्चे थे? यदि ऐसा होगा तो वह एक्शन अलग हो जायेगा।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उस सैंटर में जिन परीक्षार्थियों को पेपर दिया गया था वे सलेक्टिड रोल नम्बर थे। उस सैंटर में छांट–छांट कर परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए भेजा गया था।

श्री मनोहर लाल : सैनी साहब, उन्होंने मुझे इस बारे में जानकारी दे दी है कि वे सलेक्टिड रोल नम्बर नहीं थे। पूरे हरियाणा प्रदेश से बच्चे परीक्षा देने के लिए आये हुए थे। At random jumbled computerized तरीके से बच्चे सिलैक्ट किये जाते हैं। अब मान लो कोई कहीं से है और कोई कहीं से है तो वहां पर कोई न कोई तो होगा ही। अगर कोई आकर यह कह देगा कि वहां पर तो छांट–छांट कर कैंडीडेट्स लाये गये थे तो यह ठीक नहीं है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। माननीय कोर्ट ने भी इस बारे में एक शब्द प्रयोग किया था कि आप लोग जो विषय लेकर आए हैं वह केवल अंदाजे के आधार पर कह रहे हैं और इसके हिसाब से निर्णय नहीं किया जायेगा इसलिए माननीय कोर्ट ने उसको रिजैक्ट कर दिया। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि पेपर सब परीक्षार्थियों का हो गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि जिस सैंटर सुपरिंटैंडैंट से गलती हुई है। हमने उसको सस्पैंड कर दिया है। ऐसी बात नहीं है कि उस सैंटर सुपरिंटैंडैंट को बख्श दिया गया है। As per Staff Slection Commission and affidavit has been given to the High Court. इसमें सिर्फ सैंटर सुपरिंटैंडैंट की गलती है और कोई गड़बड़ नहीं हुई है उन्होंने माननीय हाई कोर्ट में सब कुछ लिखकर दे दिया है। मेरे पास एक विषय ग्राम सचिव की भर्ती के संबंध में भी आया था। जब ग्राम सचिव की पोस्ट के लिए एग्जाम हुए थे और एग्जाम होने के तुरन्त बाद हमें इसकी यह जानकारी मिल गई थी कि जो एग्जाम की ''आंसर की'' है, उसको स्टाफ के कुछ लोगों ने ही प्रिक्योर किया था। प्रदेश में जो लोग इस गैंग में शामिल थे, उस गैंग के माध्यम से यह ''आंसर की'' चली गई। जब यह ''आंसर की'' चली गई तो इसकी हमें शाम तक रिपोर्ट मिल गई। जब हमें इस ''आंसर की'' की रिपोर्ट मिल गई तो हमने उनको कहा कि अब इस मामले में किस प्रकार का एक्शन लिया जा सकता है, इस बारे में हमें बताया जाये तो उन्होंने हमें कुछ एक्शन लेने के बारे में बताया। जैसे हम एक बार ''आंसर की'' को चैक कर लेते हैं कि कितने बच्चे पास होते हैं और कितने बच्चे फेल होते है। यह ''आंसर की'' जहां–जहां पर भेजी गई है, उसकी कितने

परीक्षार्थियों ने नकल की है और कितनों ने नहीं की है? हमने इस बारे में सोचा कि अल्टीमेटली इस प्रकार का सख्त मैसेज देने का जो काम है वह गलत होगा। जो व्यक्ति कलप्रिट है, पहले उसको पकड़ना चाहिए और उनके खिलाफ ही कार्रवाई करनी चाहिए। जब हमने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि इस पेपर को रद्द कर दिया जाये तो कैसे रहेगा? इस पर उन्होंने हमें बताया कि अगर हम पेपर रद्द करते हैं तो इस पर 35 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। हमने उनको कहा कि इसके लिए आपको सरकार 35 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है लेकिन हमारी सरकार को यह बात मंजूर नहीं है कि प्रदेश के सरकारी संस्थानों में गलत ढंग से कोई भी सलेक्शन हो। मैं इस महान सदन में बताना चाहूंगा कि सरकार को 35 करोड़ रुपये का खर्च देना है, बाकी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का काम है। वह इस बारे में निर्णय करेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कहा गया कि ठीक है हम इस पेपर को कैंसिल करके दोबारा करवा देंगे। हमने कहा कि ठीक है, इस पेपर को दोबारा करवा लें हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि अलग–अलग जगहों पर 8 एफ.आई.आर. लिखी गई थी और 8 एफ.आई.आर. के माध्यम से 50 लोगों को अरैस्ट कर लिया गया है। अभी भी 19 लोग भगौड़े हैं, इनको भी जल्द अरैस्ट कर लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस बात से पता चलता है कि इसमें कितना बड़ा गिरोह काम कर रहा था? इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह के गिरोह एकदम से पैदा नहीं होते हैं। ये कहीं न कहीं साइबर क्राइम के जो खेल खेलने वाले लोग हैं। इनके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए होते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि कई बार कुछ बातें सरकार के ध्यान में नहीं आती हैं, वह अलग बात है लेकिन सरकार के संज्ञान में यदि कोई बात आ जाये तो फिर उसे बख्शा नहीं जायेगा क्योंकि यह मनोहर लाल की सरकार है। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)** अध्यक्ष जी, एक विषय श्री भारत भूषण बतरा जी ने यह उठाया था कि स्टाफ सिलैक्शन कमीशन के मामले में पंचकूला में एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। उस पंचकूला की एफ.आई.आर. की जानकारी मैंने मंगवा ली है। इसमें भी बहुत सी धारायें लगी हैं। इसमें यह किया जाता था कि जब एग्जाम हो गया और उसका जब रिजल्ट तैयार किया जाता था तो उस रिजल्ट को वे किसी न किसी प्रकार से प्रक्योर करते थे। जो मैरिट पर हाईएस्ट पोजीशन पर होते थे उन लोगों को सम्पर्क करने का काम करते थे कि तुम्हारी सिलैक्शन करवा देंगे। इस प्रकार से अंदर ही अंदर खेल चलता था। उसमें मैरिट में अंतर नहीं

था लेकिन यह धोखा तो है ही क्योंकि जो कैंडीडेट्स मैरिट में हैं वे उनसे भी पैसे बटोरने लग गये। अल्टीमेटली वह गैंग पकड़ा गया है। इसके अंदर भी नौ लोगों का नाम है। इसमें सारे के सारे लगभग स्टाफ सिलैक्शन कमीशन के कर्मचारी हैं। इन सभी नौ लोगों के खिलाफ कार्यवाही करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है।

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, in this connection I want to submit that in this case Kuldeep Singh, Justice, High Court has given an observation कि इस पूरे स्कैंडल के अंदर बहुत सारे लोग इंवॉल्व हैं। इस मामले में कमीशन के चेयरमैन और मैम्बर्ज भी इंवॉल्व हैं इसलिए मेरा यह कहना है कि why a C.B.I. inquiry should not be instituted in this regard? स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मैनेज भी किया और उसके बाद इसकी इंक्वॉयरी के लिए एस.आई.टी. बनाने की बात आयी। उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन यह भी आई थी कि थ्री आई.पी.एस. ऑफिसर्ज की एस.आई.टी. बने जो इस इंक्वॉयरी को करे लेकिन सी.एम. साहब ने तो इस सारे के सारे मामले को ही स्कटल कर दिया। इसी मामले में सरकार ने चेयरमैन को भी सस्पैंड कर दिया। इसके अतिरिक्त जो मैम्बर्ज थे उनके फोन पर भी कॉल आये। Everything is under investigation but it is not a fair investigation. क्योंकि सरकार द्वारा चेयरमैन और मैम्बर्ज को सेव करना था इसलिए सरकार के स्तर पर इस मामले को स्कटल कर दिया गया।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री बतरा जी को यह बताना चाहूंगा कि इस मामले की इंक्वॉयरी करने के लिए एस.आई.टी. गठित हुई है। जिस प्रकार की बात बतरा जी बता रहे हैं एस.आई.टी. में कहीं पर भी इस प्रकार का विषय नहीं है। मेरा यह कहना है कि अगर कहीं यह बात कमीशन के चेयरमैन और मैम्बर्ज तक जायेगी तो उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी क्योंकि उस सिलैक्शन बॉडी को हमारी सरकार के लोग उनके काम काज के तौर तरीकों को और सारे सिस्टम को अच्छी प्रकार से देख कर ही सिलैक्ट करते हैं कि कौन आदमी कैसा है? अगर उस सिलैक्शन में कहीं कोई दोषी पाया जायेगा तो उसको भी बख्शा नहीं जायेगा लेकिन एस..आई.टी. के बारे में जो बात श्री बतरा जी बता रहे हैं यह गलत तथ्य है। जो एस.आई.टी. के अंदर नाम आये हैं उनके बारे में मैंने बता दिया है। उनमें एक असिसटैंट कैशियर, गोपनीय शाखा, एक लिपिक, एच.एस.वी.पी., एक प्राईवेट ठेकेदार, एम.एस.एस.सी. की गोपनीय शाखा का असिसटैट, आई.टी. विंग का डी.सी. रेट पर एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक हरियाणा

सिंचाई विभाग, सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़ का अटैंडैंट है। ये डिफरैंट डिपार्टमैंट्स के लोग इस मामले में इंवॉल्व मिले हैं। इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसा कोई मामला जिस पर हम स्वयं एक्शन न ले सकें उसकी इंक्वॉयरी हम सी.बी.आई. से करवा सकते हैं लेकिन हमारे घर के अंदर यदि हमें ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसकी इंक्वॉयरी के काम को अगर हम सी.बी. आई. को दें तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हमें अपनी इंवैस्टीगेटिंग एजेंसीज पर भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है हमको अपनी इंवैस्टीगेटिंग एजेंसीज पर पूरा भरोसा है और जब तक हमारा यह भरोसा कायम है तब तक किसी बाहरी एजेंसी को इस इंक्वॉयरी के काम को देने का कोई कारण नहीं है।

श्री सोमवीर सांगवान : स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिकवैस्ट है कि इस मामले में और भी ज्यादा सख्ताई की आवश्यकता है क्योंकि यह सरेआम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। नकल का सहारा लेने वाला बच्चा आगे निकल जाता है और जो बच्चे काबिल होते हैं वे पीछे रह जाते हैं इसलिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बार–बार यही रिकवैस्ट है कि इस प्रकार के मामलों में और सख्ती की जाये।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, जो सुझाव माननीय सदस्य श्री सोमवीर सांगवान जी ने दिया है मैं भी उससे सहमत हूं।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि स्पोर्ट्स कोटे में निर्धारित मापदण्ड चेंज करके जो बच्चे वर्ष 2015 में सिलैक्ट किए गए थे उनके सिलैक्शन को भी बाद में वर्ष 2016 में रद्द कर दिया। वे बच्चे भी अभी बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके बारे में सरकार क्या करने जा रही है?

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्रीमती किरण चौधरी जी को यह बताना चाहूंगा कि इस मामले में भी कोर्ट का ही डिसीजन हुआ है। इस मामले में यह हुआ था कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी पहले बनी हुई थी उस पॉलिसी में स्पोर्ट्स पर्सन को जो ग्रेडेशन का सर्टीफिकेट दिया जाता था उसके पैरामीटर्ज अलग थे। बाद में जो वर्ष 2018 की स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी उसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि स्पोर्ट्स पर्संज को पारदर्शी और जैन्युन तरीके से ग्रेडेशन सर्टीफिकेट मिले। पहले वाली पॉलिसी में बहुत से लूप होल्स थे जिसमें कोई भी ग्रेडेशन सर्टीफिकेट बनवाकर के फायदा उठा लेता था। हमारे

पास यह भी खबर है कि दो–दो लाख रूपये देकर के बहुत से लोगों ने अपने ग्रेडेशन सर्टीफिकेट्स बनवा लिये थे। ऐसा एक मामला नहीं था बल्कि ऐसे बहुत से मामले थे। जब ग्रेडेशन सर्टीफिकेट्स गलत बन गये उसके बाद ही यह विषय कोर्ट में गया। उसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि वह भर्ती नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के बाद हुई है इसलिए सरकार बाद की स्पोर्ट्स पॉलिसी के अनुसार भर्ती करे। जो रिजल्ट निकाला गया था उसमें पहले वाले और बाद वाले सभी मिक्स कर दिये थे। जो पहले वाली पॉलिसी के हिसाब से क्वॉलीफाई करते थे उनको यही कहा कि अगर आप बाद वाली पॉलिसी में क्वॉलीफाई करते हैं तो ही आपको सिलैक्टिड माना जायेगा। स्पोर्ट्स पर्सन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं इसलिए उसका ग्रेडेशन सर्टीफिकेट भी बदलता रहता है। इस मामले में अब यही फैसला लिया गया है कि जिस स्पोर्ट्स पर्सन के पास नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का ग्रेडेशन सर्टीफिकेट होगा वह ही सिलैक्ट होगा। इसके अलावा जिन स्पोर्ट्स पर्संज के पास पुरानी पॉलिसी का ग्रेडेशन सर्टीफिकेट था उन सभी को हमने रिजैक्ट कर दिया है।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने टी.जी.टी. और पी.जी.टी. की पोस्ट्स के लिए विज्ञापन निकाला था। लगभग 600 पद संस्कृत के थे और लगभग 200 पद इंगलिश के थे। वर्ष 2015 में इन पदों के लिए विज्ञापन निकलता है और इनके लिए परीक्षा 2016–17 में हो जाती है। उसके बाद यह मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में मामला आज भी चल रहा है, बाद में आप उन पोस्ट्स को विद्ड्रा कर लेते हैं। उन बच्चों के फेट का क्या होगा जिन्होंने 2015 में अप्लाई किया था ? वर्ष 2020 में आप उनकी ऐज मिलाते रहेंगे। उनको दोबारा मौका देते रहेंगे। This is a mockery of the system. This is incompetence of the Haryana Staff Selection Commission. This is not one example. There are so many examples. आपने एल.आर. की, ए.जी. की एडवाइस लेकर 1500 पोस्ट्स विद् ड्रा कर ली।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। ये दो अलग–अलग केस हैं। एक तो टी.जी.टी. इंग्लिश का है और दूसरा टीचर संस्कृत का है। होता यह है कि विभाग अपने हिसाब से कुछ शर्तें बनाकर भेज देता है और जो शर्तें विभाग ने बनाकर भेजी, एच.एस.एस.सी. उन्हीं के हिसाब से भर्ती करता है लेकिन बीच में कोई व्यक्ति जिसका सिलैक्शन नहीं होता वह उनको कोर्ट में चैलेंज

कर देता है। मैं आपको संस्कृत टीचर के बारे में बताता हूं। वर्ष 2012 में पिछली सरकार ने पॉलिसी बनाई जिसमें संस्कृत के शिक्षा शास्त्री और आचार्य को बाहर कर दिया और केवल एम.ए. (संस्कृत) और बी.एड को कम्पीटैंट रखा। हमारे पास बहुत सी रिप्रैजैन्टेशन्ज आई जिसके बारे में हमने बहुत से संस्कृत विषय के जानकार लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि संस्कृत की शिक्षा के लिए तो एम.ए. (संस्कृत) की बजाय आचार्य (संस्कृत) ज्यादा निपुण हैं और बी.एड (संस्कृत) की बजाय शिक्षा शास्त्री संस्कृत ज्यादा निपुण हैं। वर्ष 2012 से पहले यही स्थिति होती थी लेकिन 2012 में पिछली सरकार ने इनको उड़ा दिया। फिर हमने वर्ष 2017 में इसको दोबारा जोड़ दिया। शिक्षा शास्त्री और बी.एड को बराबर कर दिया। अब मैं इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर देता हूं। 2017 में यह पॉलिसी बदल गई। 2015 में इनका विज्ञापन निकला। इनका जो रिजल्ट आया वह 2017 की पॉलिसी बदलने के बाद आया। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। एच.एस.एस.सी. कब भर्ती करेगा, कब इग्जाम लेगा और कब रिजल्ट निकालेगा यह उसका काम है। यह सिलैक्शन उसी पॉलिसी के तहत हुई जो 2012 में आपने बनाई थी। हमने सिलैक्शन वही की। लेकिन बाद में 2017 की पॉलिसी में कवर होने वाले लोग कहने लगे कि इन पोस्ट्स पर हमारा भी क्लेम बढ़ गया है क्योंकि शिक्षा शास्त्री बी.एड के बराबर हो गये हैं। ये कोर्ट में चले गये और कोर्ट की एक बेंच ने फैसला पहले वालों के फेवर में दिया और दूसरी बेंच ने दूसरे वालों के फेवर में फैसला दिया। इस प्रकार 2016–17 से लेकर 2021 यानी 4 साल से भी अधिक समय से यह मामला कोर्ट में चल रहा है, हरेक का प्रैशर है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो इसमें 5 साल सुप्रीम कोर्ट में और लग जायेंगे। हमको बच्चों की पढ़ाई का मामला भी पता है। हमको उनकी नियुक्तियां भी करनी हैं। अल्टीमेटली हमें यह विचार आया कि क्यों न इन पोस्ट्स को विद्ड्रा करके दोबारा से विज्ञापन निकाला जाए। हमने इस बारे में एच.एस.एस.सी. और विभाग से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हां अगर हम इन पोस्ट्स को विद ड्रा करके दोबारा नई भर्ती करते हैं तो यह भर्ती तुरन्त हो जायेगी वर्ना यह मामला ऐसे ही लटका रहेगा और इसमें 5 साल और लग जायेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इसमें 5 साल तो अब भी लग जायेंगे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब को कहना चाहूंगा कि अब इसमें 5 साल नहीं लगेंगे। अब हमने सभी कारण समाप्त कर दिये

हैं। कांग्रेस सरकार के समय की 2012 की पॉलिसी थी और हमारी 2017 की पॉलिसी है इनका जो कंट्राडिक्शन था उसको अब समाप्त कर दिया गया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जो भर्ती होगी वह 2017 की पॉलिसी के अनुसार होगी। यह भर्ती 2012 की पॉलिसी के हिसाब से नहीं होगी। जो वर्ष 2015 का विज्ञापन था उसको समाप्त कर दिया है अब उसका दोबारा से विज्ञापन देकर उसका एग्जाम होने जा रहा है। अब हमने निर्णय ले लिया है और निर्णय लेना हमारे अधिकार क्षेत्र में है। हम बजाय इसके कि और 5 साल इस मामले को कोर्ट में धकेले इससे अच्छा तो यही होगा कि हमने इन पोस्ट्स को विद् ड्रा करके दोबारा से नई भर्ती करने का निर्णय लिया है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में तो कोई भी अभी भी जा सकता है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अब हम नई भर्ती करेंगे। अगर फिर भी कोई कोर्ट में जायेगा तो जायेगा। हमें अपना काम करना है हम करते रहेंगे। हमें यह काम ठीक लगा तो कर दिया। अगर हम यह काम नहीं करते तो 5 साल और लग जाते। आज सरकार के नाते जो अधिकार हमारा है उसका उपयोग करना हमारा धर्म है और वह हम जरूर करेंगे।इसी प्रकार से टी.जी.टी., पी.जी.टी. (इंग्लिश) विषय पर भी झगड़ा है। आप उस झगड़े को सुन लीजिए क्योंकि मैं इन चीजों का बहुत डिटेल में अध्ययन करके आता हूं। इसमें झगड़ा क्या है कि अगर इंग्लिश के टीचर लगाने हैं तो उसमें विवाद क्या खड़ा हुआ कि आवेदक इंग्लिश (इलैक्टिव) होना चाहिए या इंग्लिश (कम्पलसरी) होना चाहिए। अब अगर इलैक्टिव सब्जैक्ट को देखें तो इलैक्टिव सब्जैक्ट तो ऐसा है कोई ले और कोई न ले। कम्पलसरी सब्जैक्ट का मतलब ये है कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात में कोर्ट भी उलझ गया, डिपार्टमैंट और यूनिवर्सिटी उलझ गये कि इलैक्टिव सब्जैक्ट ठीक है या कम्पलसरी ठीक है। कोर्ट में ये बात चलते–चलते पांच साल हो गये कि it should be English elective or it should be English compulsory. फैसले से डिपार्टमैंट, कोर्ट और यूनिवर्सिटीज सहमत नहीं हैं। आखिर हमने इसको स्पैसिफाई किया कि अब दोनों ही सब्जैक्ट चाहे इंग्लिश इलैक्टिव है चाहे इंग्लिश कम्पलसरी है, के लिख कर के एग्जाम लेंगे। जिसके बारे में डिपार्टमैंट बता रहा है कि अब जल्दी ही रूल्ज बन जाएंगे । उसमें हम दोनों सब्जैक्ट्स का लिखेंगे। आखिर एग्जाम तो बाद में भी होना है। उस एग्जाम में जो मैरिट में आएगा वह बच्चों को पढ़ा लेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इसमें आयु में रिलैक्सेशन होना चाहिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम उसमें आयु में रिलैक्शेसन देंगे। (शोर एवं व्यवधान) बत्तरा जी, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये सारे विभाग न हों तो आप और कोर्ट मिलकर क्या करेंगे? लोगों ने इस पर इतने सारे विवाद खड़े किये हैं। आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। पिछली सरकारें भी हिस्सेदार हैं। गलती हमसे भी हो सकती है लेकिन उसको ये विभाग सुलटाएंगे। समाधान करना हमारा काम है और हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। We are going ahead with solution. अब आपका एक विषय आता है महंगाई का जिसको आप लोगो ने बड़े जोर–शोर से उठाया है। इस महंगाई के विषय में मुख्य रूप से पैट्रोल और डीजल की बात आई है। इसमें मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2021 तक आठ साल के आंकड़े मेरे पास हैं। इन आठ साल में पैट्रोल की 12–13 प्रतिशत बढ़ौतरी हुई है। ये रेट रोजाना बदलता है क्योंकि ये कम्पनियों के रेट हैं कभी 20 पैसे कम है कभी ज्यादा है। ऐसे ही डीजल के रेट में 25 से 30 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको तीसरा आंकड़ा बताऊं तो वह है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की जो बढ़ौतरी है वह 24 से 30 प्रतिशत है। इन आठ सालों में आप महंगाई दर को देख लें तो आठ साल में कोई भी चीज 30–40 या 50 प्रतिशत बढ़ना एक लोजिकल इंक्रीज है। इसमें चाहे हम अपनी इंकम देख लें, सभी की सैलरीज देख लें, सभी के खर्चे देख लें या यह आठ साल का विषय हो गया है। आठ साल में 4–5 प्रतिशत की बढ़ौतरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सभी को डी.ए. भी मिलता है, सब चीजों पर महंगाई दर होती है। क्या फसल पर नहीं होगी, क्या फसल के रेट नहीं बढ़ेंगे? आपको मैं वह भी बता देता हूं कि आठ साल में क्या–क्या बढ़ाए हैं इसलिए केवल एक एक्सप्लायटेशन के लिए किसी को भड़काना कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई ठीक नहीं है। हां, इतना जरूर है वह केन्द्र सरकार का विषय है क्योंकि केन्द्र सरकार ने इसके ऊपर टैक्सिज भी लगाए हुए थे। थोड़ा वैट हमने भी लगाया हुआ होता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आपने तो वैट बढ़ाया है।

श्री मनोहर लाल : हां, वह थोड़ा था इसलिए 5–7 प्रतिशत वैट बढ़ा था। वह तब बढ़ा था जब रेट काफी कम हो गये थे। जब रेट कम हुए थे तो हमने इसकी एक लोअर सिलिंग भी लगा दी थी कि अगर रेट ज्यादा कम होंगे तो वैट का इतना रेट लेना ही चाहिए। अगर वह वैट लेना बन्द कर देंगे तो इसी पैसे में से सभी की तनख्वाएं देनी होती हैं। इसी पैसे में सभी के खर्चे करने हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : मुख्यमंत्री जी, जब गैस सिलेंडर 400 रुपये का हुआ था तो उस समय अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किये जाते थे। तब भी आप लोगों ने ही प्रदर्शन किये थे। उस समय आप कहते थे कि यह तो अनलोजिकल है। आज गैस सिलेंडर 860 रुपये का हो गया है तो क्या अब ये लोजिकल हो गया? क्या उस समय वह बर्बादी थी? आप जो ये वैट और सारा कुछ क्यों लगा रहे हैं? आप कच्चे तेल की कीमतों को कम कर दीजिए इससे कम से कम लोगों को राहत तो मिलेगी।

श्री मनोहर लाल : किरण जी, आप मेरी बात सुनिये कुछ चीज हमारे हाथ में है जैसे पैट्रोल–डीजल की कीमत तो थोड़ी बहुत हमारे हाथ में है लेकिन गैस की कीमत के बारे में तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सब मिलकर के प्रयत्न करें। कांग्रेस की सरकारें भी कम करें, बी.जे.पी. की सरकारें भी कम करें, सैंट्रल की सरकार भी इसमें मूव लें। इसमें हम भी प्रयत्न करते हैं, आप भी कीजिए।

श्रीमती किरण चौधरी : मुख्यमंत्री जी, आप यहां से प्रस्ताव पास करवाईये उसमें विपक्ष भी आपका साथ देगा।

.....

बैठक का समय बढ़ाना

19.00 बजे

श्री अध्यक्षः यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 15 मिनट के और लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी,

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अब मैं बड़े भारी मन से एक विषय सदन के सामने रखना चाहूंगा **(इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आखें नम हो गई।)** अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े भारी मन से एक विषय रखना चाहूंगा। इस विषय के ध्यान में आने के कारण मुझे कल सारी रात नींद नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, कल महिला दिवस था। महिला दिवस को देश और दुनिया ने खूब अच्छी प्रकार से मनाया।

विधान सभा में भी पूरे सत्र का संचालन महिलाओं को समर्पित किया गया। अध्यक्ष महोदय, यहां से जाने के बाद जब मैं टी.वी. देखता हूँ तो मुझे बंधुआ मजदूरों से भी बुरा व्यवहार महिलाओं के साथ दर्शाने वाला एक बड़ा भोंडा दृश्य दिखाई दिया। मैं देखता हूँ कि भूपेन्द्र सिंह हुडा जी और रघुवीर सिंह कादियान जी ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं और उस ट्रैक्टर को कांग्रेस की कलानौर की एम.एल.ए. हमारी बहन शकुंतला खटक और कई दूसरी बहनें खींच रही है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सभ्यता नहीं है। क्या इसको शिष्टाचार माना जा सकता है? मीडिया कभी झूठ नहीं बोलता है जो सच्चाई होती है उसको ही दिखाता है। यह दृश्य टी.वी. पर चला। अगर इनको प्रदर्शन ही करना था तो अच्छा यह होता कि हमारी बहनें ट्रैक्टर पर बैठती और ये लोग उस ट्रैक्टर के आगे लगकर ट्रैक्टर को खीचते। जिस तरह बहनों से बंधुआ मजदूरों की तरह ट्रैक्टर खिचवाया जा रहा था यदि ये खुद उस ट्रैक्टर को खींचते तो प्रदर्शन करने का मजा भी आता? इनको कुछ अता–पता भी लगता कि ट्रैक्टर खींचने से क्या हाल होता है? यहां सदन में सभी कांग्रेस के विधायक बैठे हैं, वे बता दें कि यह दृश्य था कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, इस तरह का दृश्य देखकर मैं सारी रात सो नहीं पाया। इन लोगों को शर्म करनी चाहिए। हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए एक से बढ़कर एक योजना बनाने की दिशा में आगे बढ़ती जा रही है और यह लोग उस मातृशक्ति का अपमान करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा को पहले कन्याओं को गर्भ में मारने वाला प्रदेश माना जाता था। दिनांक 22 जनवरी, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए हमने पिछले पांच साल से काम करना शुरू किया था और इसका ही यह परिणाम है कि जो जैंडर रेशो पहले एक हजार पुरूषों के मुकाबले 850 हुआ करता था आज वह बढ़कर 922 हो गया है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, कोई भी शुरूआत एक दम से नहीं होती है। अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिए कि यह जैंडर रेशो कब बढ़ना शुरू हुआ था? देखिए, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकार के गुमान में यह कहना कि केवल मैं ही बड़ा हूँ ठीक नहीं है। सरकार हमारी भी गई थी और इनकी भी जायेगी इसलिए तथ्यों के साथ बात की जाये तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, बात गुमान की नहीं है बात तथ्यों की है। इन लोगों ने इस तरह के अभियान के लिए नारे तो बहुत लगाए लेकिन कभी शुरूआत

नहीं की जबकि हमारी सरकार ने तो एक्शन लेने का काम किया है। हमारे होम डिपार्टमैंट, बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा एन.जी.ओज. ने इस दिशा में मिलकर काम करते हुए ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम किया है। जब हरियाणा प्रदेश में गर्भपात जैसे कार्यों पर सख्ती होने लगी तो लोगों ने प्रदेश के साथ लगते दूसरे प्रदेशों की बाउंडरीज पर स्थित सैंटर्ज पर गर्भपात कराने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। मैंने इस विषय पर सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और सभी मुख्यमंत्रियों का इस कार्य में मुझे पूरा सहयोग भी मिला। अब अगर दूसरे प्रदेशों के अंदर या हरियाणा प्रदेश के साथ लगते प्रदेश की बाउंडरीज पर स्थित सैंटर्ज पर हरियाणा नम्बर की गाड़ी खड़ी भी हो जाती है तो डॉक्टर्ज थर–थर कांपने लग जाते हैं कि कहीं ऐसा केस न आ जाये और उनको फंसा न दे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के केसिज में 350 से उपर पुलिस केस बनाकर लोगों को अरेस्ट किया गया है। कहने का भाव यह है इस तरह के कामों को शिद्दत से करने की जरूरत होती है और केवल कहने या नारे लगाने से यह काम सिरे तक नहीं पहुंचा करते है लेकिन हमारी सरकार ने इस असंभव कार्य को हकीकत में संभव करके दिखाया है। हमने 40 से 50 हजार बेटियां जो गर्भ में मरने वाली थी, को बचाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए यह बड़े ही संतोष का विषय है। मैं आज से नहीं लगातार पांच सालों से कहता आ रहा हूँ कि महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया हुआ है लेकिन हरियाणा प्रदेश में हर रोज खुलेआम बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं घट रही हैं। उनके ऊपर भी सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह विषय भी 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' से संबंधित होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आज किसान आंदोलन के दौरान लाखों की संख्या में हमारी बहन व बेटियां अपने छोटे–छोटे बच्चों के साथ सर्दी के मौसम में दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठी हुई हैं, क्या उनकी पीड़ा देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को दर्द नहीं होता? यह बात भी सदन को बताई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के ऊपर हो रही अपराधिक घटनों के बारे में सरकार बिल्कुल चिंतित है और ठोस से ठोस कदम भी उठा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात सदन से कहना चाहता हूँ कि मैं महिलाओं के विरूद्ध अपराध के विषय को स्पष्ट तौर पर स्वीकार करता हूँ। यह विषय सरकार की कानून व्यवस्था का विषय नहीं है। यह कानून व्यवस्था का केवल एक पार्ट है और इससे ज्यादा तो यह सामाजिक विषय है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में महिलाओं के साथ जो रेप की घटनाएं हो रही हैं या छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं, के बारे में कहना चाहूँगा जब तक हम सामाजिक तौर पर जागरूक नहीं होंगे, स्वयं संस्कारित नहीं होंगे और अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक इस विषय में कोई विशेष सुधार आने की संभावना लगती नहीं है। सरकार इस विषय में अपने लेवल पर जो काम करेगी सो करेगी लेकिन इस विषय पर हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। चाहे विपक्ष, एन.जी.ओज., सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग, नौजवान, नवयुवतियां आदि हों, इस विषय के ऊपर हम सभी लोगों को मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जो भी सुझाव इस संबंध में आयेंगे सरकार उन सुझावों को मानने के लिये तैयार है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' पर महिला सदस्य ट्रैक्टर खींच रही थीं और कांग्रेस के कुछ नेता ट्रैक्टर पर बैठे थे। यह बात ठीक है, हम ट्रैक्टर पर बैठकर महँगाई के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से पूछना चाहता हूँ कि आज महँगाई के कारण रसोई का खर्चा किस पर पड़ता है? पैट्रोल डीजल में हर रोज हो रही बढ़ौत्तरी और रसोई गैस की कीमत कितनी पहुँच गई है? इस प्रकार से इन सब चीजों की महँगाई की तकलीफ हमारी बहनों को ही पता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी साहब की बात को मानता हूँ लेकिन उसमें यह विषय कहां से आ गया कि हमारी बहनों को और ज्यादा तकलीफें दें। हमारी बहनों को बैलों की तरह जोत कर उन पर और ज्यादा अत्याचार किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने अगर महँगाई के खिलाफ रोष प्रदर्शन करना ही था तो अच्छा यह होता कि कांग्रेस के नेता ट्रैक्टर खींचते और हमारी बहनें ट्रैक्टर पर बैठतीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो हमारी बहन और बेटियां अपने छोटे–छोटे बच्चों के साथ दिल्ली बॉर्डर्ज पर बैठी हुईं हैं, उनकी तकलीफ नजर नहीं आ रही है। वहाँ पर उनके बिजली और पानी के कनैक्शन काट दिये गये और उनके शौचालयों को उखाड़ दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, एक मुख्यमंत्री के बराबर का बड़ा नेता बैल के रूप में स्वयं जुतता और हमारी बहनें ट्रैक्टर पर बैठतीं, इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को महँगाई के खिलाफ राजनीति दावपेंच करने से जरूर लाभ मिलता। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बात आपके माध्यम से सदन में रोजगार और बेरोजगारी के विषय के संबंध में रखना चाहता हूँ। यदि विपक्ष का इस संबंध में लिखित में कोई जवाब आयेगा तो फिर उसका उत्तर दूंगा। (विघ्न)

श्री अमित सिहाग : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा प्रदेश में 7 महिला कॉलेजिज खोले गये थे । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनको एक हफ्ते बाद को–ऐड कर दिया गया था । मेरे हल्के के गोरीवाला गांव में भी एक महिला कॉलेज को उस दौरान को–ऐड कर दिया गया था । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने 7 महिला कॉलेजिज को को–ऐड किया था और उनमें एक कॉलेज माननीय सदस्य श्री अमित सिहाग के हल्के का भी था । मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि उन कॉलेजिज को को–ऐड करने के लिए हमारे पास लिखित में डिमाण्ड आई थी । (विघ्न)

श्री अमित सिहाग : अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड तो महिला कॉलेज के लिए की गई थी । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, उस कॉलेज को को–ऐड करने से संबंधित डिमाण्ड मेरे पास है । उस डिमाण्ड को मैं माननीय सदस्य को दिखा भी दूंगा । (विघ्न)

श्री अमित सिहाग : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उस कॉलेज का उद्घाटन भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ही किया था, मैं पूछना चाहता हूं कि फिर उस कॉलेज को एक हफ्ते बाद ही को–ऐड कॉलेज में कंवर्ट क्यों किया गया ? (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे पास किसी महिला कॉलेज को को–ऐड कॉलेज में कंवर्ट करने के लिए रिकवैस्ट आती है तो हम उस कॉलेज को को–ऐड कर देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, हमने भी अपने हल्के के एक महिला कॉलेज को को–ऐड कॉलेज में कंवर्ट करवाया है क्योंकि महिला कॉलेज की सीटें अकेली महिलाओं से भरती ही नहीं थी ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने इसीलिए इन कॉलेजिज को को–ऐड कॉलेज में कंवर्ट करवाया है । इसके अलावा अगर कोई माईनर चेंज होगा तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा । सरकार ने जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए प्राईवेट सैक्टर की नौकरियों में 75 परसैंट आरक्षण का कानून बनाया है उसकी सभी ने प्रशंसा की है । उसका किसी ने विरोध नहीं किया है । इसमें एक जो आपत्ति आ रही है उसका मैं एक घोषणा करके दूर कर रहा हूं । (विघ्न)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अभी कहा कि इस कानून को सभी ने 'यूनानीमसली' पास किया है । अध्यक्ष महोदय, मैं इस कानून के हक में नहीं हूं । मैं इसका विरोध करता हूं । मेरा कहना है कि सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए प्राईवेट सैक्टर की नौकरियों में 75 परसैंट आरक्षण का कानून बिल्कुल गलत है । (विघ्न) हमारा सारा देश एक है । अन्य प्रदेशों के लोग हमारे राज्य में काम करते हैं और हमारा घर तक अन्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर बनाते हैं । अगर सभी प्रदेश ऐसे कानून बनाने लगे तो एक दिन हमारा देश टूट जाएगा । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय सदस्य की बात को नोट कर लिया है । इस कानून के संबंध में लोगों को जो आपत्ति थी मैं उसको दुरूस्त कर रहा हूं । कहा गया कि हरियाणा प्रदेश के डोमिसाइल बनवाने की शर्त 15 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई जिस कारण से अनुसूचित जाति के होने की वजह से आरक्षण लेने वाले लोग बढ़ जाएंगे क्योंकि अन्य प्रदेशों से जो प्रवासी लोग 5 साल से हरियाणा में रह रहे होंगे वे भी हरियाणा प्रदेश का डोमिसाइल बनवा लेंगे । मैं इस संबंध में घोषणा करना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए जो मापदण्ड, जो पैरामीटर्स और जो नोटीफिकेशंज पहले मान्य थे अब भी वे ही रहेंगे । (शोर एवं व्यवधान) डोमिसाइल से संबंधित ये रूल्ज केवल प्राईवेट सैक्ट्र्स

की नौकरियों में लागू होंगे । ये नियम सरकारी नौकरियों में लागू नहीं होंगे । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय जो बदलाव कर रहे हैं इससे सोशल सैक्टर की स्कीम्ज पर काफी बोझ बढ़ जाएगा तो क्या सरकार इन बदलावों के बाद जो नये लोग इस क्राइटेरिया में आएंगे उनको भी बैनीफिट देगी ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अब हम जो बदलाव कर रहे हैं वह केवल प्राईवेट सैक्टर की नौकरियों के लिए कर रहे हैं । सरकारी नौकरियों और स्कीम्ज में पहले वाले नियम और शर्तें ही लागू होंगी । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बारे में मैंशन नहीं किया है। अगर डोमिसाइल 5 साल में बन जाएगा तो he will be bonafide resident of the State. Amendment can be made in this regard also because it has been written that 15 साल की बजाय 5 साल होगा । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार के कानून में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि डोमिसाइल उसी व्यक्ति का बनेगा जो 15 साल से हरियाणा में रह रहा होगा । यह तो मात्र एक पोलिसी मैटर है । (विघ्न) 15 वर्ष की कंडीशन तो केवल पोलिसी नोटिफिकेशन में है । निजी उद्योगों में नौकरी के लिए हम 5 साल से हरियाणा में रहने वाले लोगों को भी हरियाणा का निवासी ही मान लेंगे । इस कानून की वजह से हमको बहुत–सी चीजों का विरोध भी सहन करना पड़ रहा है । हमें इंडस्ट्रीज का विरोध भी सहन करना पड़ रहा है, इसलिए हम एकतरफा नहीं चल सकते । हमें यह भी देखना है कि जिन्होंने युवाओं को रोजगार देना है इसकी वजह से कहीं वे ही हरियाणा में आना पसन्द न करें । अतः हमें इसका बीच का रास्ता निकालना है, इसलिए हमने बीच का रास्ता 5 साल से हरियाणा में रहने वाले लोगों को हरियाणा का निवासी मानकर निकाला है । किसी अन्य प्रदेश का जो व्यक्ति 10–15 साल से हरियाणा में नौकरी कर रहा है तो उसके बच्चे भी यहीं पर नौकरी करना चाहेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि यह फैसला हरियाणा सरकार ने ही क्यों लिया ? (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में हमने ही सबसे पहले यह फैसला लिया है बल्कि हमसे पहले दूसरे प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ले चुके हैं । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से एस.सीज., बी.सीज. कैटेगरी के व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में अधिकार के तौर पर आरक्षण मिला हुआ है उसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री महोदय इन प्राईवेट सैक्टर की नौकरियों में भी एस.सीज., बी.सीज. कैटेगरी के व्यक्तियों को आरक्षण का अधिकार एश्योर करें ।अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा प्रदेश में पहले ही सरकारी नौकरियां कम हैं और प्राईवेट सैक्टर में नौकरी मिलेंगी नहीं। सरकार ने दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों के लिए हरियाणा का डोमिसाईल बनवाने के लिए 15 साल के स्थान पर 5 साल की कंडीशन लगा दी है। आज तक भी there is no clear clarification on this issue. सरकार ने हरियाणा राज्य का डोमिसाईल बनवाने के लिए 5 साल की कंडीशन लगा दी है। इसके अनुसार दूसरे राज्यों के बी.सीज./एस.सीज. कैटेगरीज के जो लोग यहां पर आएंगे, वे हमारे प्रदेश की इन कैटेगरीज के लोगों का रिजर्वेशन का कोटा खा जाएंगे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आलरेडी जो कर्मचारी सर्विस कर रहे हैं, वे तो सर्विस में ही रहेंगे। प्रदेश में नयी जॉब्स कहां से आएंगी ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नयी जॉब्स भी आएंगी, नये इन्वेस्टमैंट्स भी आएंगे और नयी फैक्ट्रीज भी लगेंगी। अभी सरकार ने जो पॉलिसी बनायी है, अगर उस पॉलिसी में साल के बाद लगेगा कि इससे प्रदेश को नुकसान हो रहा है तो हम उसको बदल देंगे। इसके लिए हमारे ऊपर कोई प्रैशर नहीं है। हरियाणा प्रदेश के इंट्रस्ट में जो पॉलिसी बनानी होगी, हम वही पॉलिसी बना देंगे।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरी छोटी सी बात है जो मैं कहना चाहता हूं। बार–बार सदन में यह बात कही जा रही है कि प्रदेश के बाहर के लोग आ जाएंगे। क्या ये लोग पाकिस्तान के हैं? उन लोगों को बाहरी–बाहरी कहकर क्या बात कही जा रही है ? ये बाहरी लोग नहीं हैं। इनको बाहरी कहने का क्या मतलब

है ? हम सभी का एक झंडा, एक निशान और एक संविधान है। इसके अतिरिक्त यह प्राईवेट सैक्टर की नौकरियों में 10 प्रतिशत का कैप भी गलत है।

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये बातें भी इनकी पार्टी के माननीय सदस्य ही करते हैं, इसलिए माननीय सदस्य को इनकी पार्टी के माननीय सदस्यों को ही समझाना चाहिए।

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जो 33,000 कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा के तहत लगे हुए हैं तो क्या सरकार इस ठेका प्रथा को खत्म करेगी ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, ये अलग–अलग विषय हैं। मेरा कहना यह है कि स्टेट के इंट्रस्ट में जो उचित होगा, उसको हम जरूर करेंगे। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके बारे में अलग–अलग मत होते हैं। किसी का कोई मत है और किसी का कोई मत है। जब कोई निर्णय लिया जाता है तो कुछ समय हम उसी के हिसाब से आगे चलते हैं। अगर हमें लगेगा कि वह निर्णय प्रदेश के हित में नहीं है तो उस निर्णय को बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष के माननीय सदस्य भी यहीं पर हैं और हम भी यही पर हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, इस फैसले से लोग सफर करेंगे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इससे कोई सफर नहीं होगा, हम इसको देख लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं 2–3 विषयों पर जानकारी देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। इसके अतिरिक्त रोजगार देने का विषय आया था। रोजगार देने के नाते से इंजीनियर्ज की भर्ती में 'गेट' क्वालीफाईड की वेटेज के बारे में बातें की गयी। लगभग 2 साल पहले हमारे प्रदेश में

इंजीनियरिंग स्टॉफ बहुत कम हो गया था और उस स्टॉफ के लिए भर्ती करने में कठिनाइयां आ रही थी। इसमें एक सुझाव आया कि गेट का एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का होता है। जैसे मैडिकल एजुकेशन के लिए एग्जाम होता है, उसी तरह से यह एग्जाम होता है। गेट का एग्जाम देकर जो पोस्ट्स ग्रेजूएट करने के लिए एडमिशन लेते हैं, सरकार ने उसी एग्जाम को मान्यता दी है। उसकी मैरिट के अनुसार अगर कोई बच्चा यहां पर नौकरी लेना चाहता है तो वह उसके लिए फार्म एप्लाई कर सकता है। हमारा भर्ती करने का पहला पैमाना मैरिट का है। अगर हम नया एग्जाम लेंगे, तब भी वही बच्चे मैरिट में आएंगे और उसके लिए सिर्फ उनको दोबारा टैस्ट ही देना होगा। यानी अगर वे फार्म एप्लाई करेंगे तो उनको सिर्फ दोबारा अपनी योग्यता ही सिद्ध करनी होगी। हम इसमें किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को एप्लाई करने से रोक नहीं सकते क्योंकि यह सरकारी नौकरी है। संविधान की ऑर्टिकल 14 में कहा गया है कि पूरे देश में कैंडिडेट्स कहीं पर भी सर्विस के लिए एप्लाई कर सकते हैं। हमारे एग्जाम और गेट के एग्जाम में अन्तर नहीं है। जब यह भर्ती की गयी तो एक बात को ध्यान में रखा गया था कि गेट की वेटेज 80 प्रतिशत होगी और उसमें हरियाणा प्रदेश के कैंडिडेट्स को 20 प्रतिशत अंक का सोसियो इकोनॉमिक का वेटेज मिलेगा। यह वेटेज सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा। अर्थात इस प्रकार हरियाणा प्रदेश के कैंडिडेट्स को 20 प्रतिशत का अपडेशन मिल जाता है। फिर इसमें लोगों द्वारा प्रचार किया गया कि हरियाण प्रदेश के कैंडिडेट्स बहुत कम भर्ती हुए हैं। कुल 155 एस.डी.ओज. में से हरियाणा प्रदेश के 85 एस.डी.ओज. भर्ती हुए हैं। यानी हरियाणा प्रदेश के आधे से ज्यादा एस.डी.ओज. भर्ती हुए हैं। जबकि लोगों द्वारा यह कहा गया कि 88 एस.डी.ओज. में से केवल 22 एस.डी.ओज. ही हरियाणा प्रदेश के हैं। यह बात क्यों कही गयी ? इसमें 3 प्रकार की लिस्ट लगायी गयी थी जिसमें एक लिस्ट जनरल, दूसरी लिस्ट बी.सीज. और तीसरी लिस्ट एस.सीज. कैटेगरी की थी। हमारे कुछ बंधु जनरल कैटेगरी का तो प्रचार करते हैं लेकिन एस.सीज. कैटेगरी में 100 प्रतिशत बच्चे हरियाणा प्रदेश के होते हैं, उसका प्रचार नहीं करते। इसका मतलब क्या आप उन एस.सीज. कैटेगरी के बच्चों को हरियाणा प्रदेश का नहीं मानते हैं ? अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अलग है कि कोई एप्लाई करे या न करे। इसमें हरियाणा प्रदेश के इतने प्रतिशत बच्चे भर्ती हुए हैं तो उसमें जनरल, बी.सीज. और एस.सीज. कैटेगरी के बच्चे भी होंगे। माननीय सदस्यों

को इस विषय को ढंग से रखना चाहिए। विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह कहना चाहिए कि इन 155 एस.डी.ओज. में से हरियाणा प्रदेश के 88 एस.डी.ओज. की संख्या कम ही है। इस परसैंटेज को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन हर समय यही प्रचार करना और दूसरी बात को गोल कर देना कि उस लिस्ट में 88 में से केवल 22 बच्चे ही हरियाणा प्रदेश के भर्ती हुए हैं और 66 बच्चे दूसरे राज्यों के भर्ती हुए हैं, यह गलत है। हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रतिशत है। इस प्रकार इस भर्ती में 25 प्रतिशत बच्चे हरियाणा प्रदेश के भर्ती हुए हैं। इस प्रकार जो दूसरे राज्यों के बच्चे भी भर्ती हुए हैं वे तो वैसे भी आ सकते हैं। आज के दिन इंजीनियरिंग स्टॉफ में देश के अन्य राज्यों के बच्चे भर्ती होते हैं। प्रदेश में क्लास–1 सर्विसिज में दूसरे प्रदेशों के बच्चे पहले भी आते रहे हैं और अब भी आ रहे हैं। आई.ए.एस., आई.पी.एस., एच.सी.एस. और एच.पी.एस. की सर्विसिज में भी देश के दूसरे राज्यों के बच्चे भर्ती होकर आते रहे हैं। इसी प्रकार से ये बच्चे भी भर्ती हुए हैं। जिस प्रकार प्राईवेट नौकरियों में 50,000 रुपये से नीचे की सैलेरी की क्लास–सी और डी की भर्ती होती है। यह भी उसी लेवल की नौकरी है। यह ग्रुप–ए और ग्रुप–बी की पोस्ट्स नहीं हैं लेकिन ये बातें कौन बतायेगा? इसलिए इनको मेरा कहना यह है कि इन बातों पर जरूर ध्यान रखें। जब ग्रुप–सी और ग्रुप–डी की भर्ती प्रक्रिया की बात की जाती है तब इसमें हर विभाग अपनी–अपनी नौकरी निकालता है। मान लो किसी विभाग में 200 पद खाली हैं, किसी विभाग में 500 पद खाली हैं, किसी विभाग में 1000 पद खाली हैं और किसी विभाग में 2000 पद खाली हैं। इस तरह से इन पदों पर भर्ती के लिए लाखों व्यक्ति एपीयर होते हैं। हमारी सरकार ने इस बात को देखते हुए इसमें भर्तियां करने के लिए एक प्रावधान किया है कि ''वन टाईम रजिस्ट्रेशन'' पोर्टल बनाया जाये। मैं इस बारे में इस महान सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि इस पोर्टल के आधार पर प्रार्थी एक बार एग्जाम देगा और एक बार ही उसको फीस देनी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी के व्यक्तियों को 500 रुपये और एस.सीज. कैटेगरी के व्यक्तियों को 200 रुपये फीस देनी पड़ेगी। इस पोर्टल पर इनकी 3 साल तक मैरिट मान्य रहेगी। तीन साल में जिस डिपार्टमैंट को ग्रुप–डी के कर्मचारियों की जरूरत है तो वे विदआउट इन्टरव्यू मैरिट के हिसाब से लेते रहेंगे। संबंधित डिपार्टमैंट को साल भर में जितनी भी रिक्विजीशन की आवश्यकता होगी वह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजते रहेंगे और मैरिट के आधार पर

कर्मचारियों की नियुक्ति करते रहेंगे। जिन बच्चों को भर्ती किया जायेगा उनसे ऑप्शन पूछा जायेगा कि आपकी नियुक्ति किस डिपार्टमैंट में की जाये, क्या वे संबंधित डिपार्टमैंट में जाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। अगर वे संबंधित डिपार्टमैंट में जाने के लिए तैयार है तो उनकी नियुक्ति मैरिट के हिसाब से संबंधित डिपार्टमैंट में कर दी जायेगी। हमारी सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए भर्ती का सिस्टम सरल बना दिया है। ग्रुप–सी की भर्ती के लिए मान लो डिपार्टमैंट में रिक्विजीशन 100 पदों के लिए है तो मैरिट में जो 300 कैंडीडेट्स सबसे ऊपर होंगे उनका एग्जाम ले लिया जायेगा और उन 300 कैंडीडेट्स में 100 कैंडीडेट्स को सिलैक्ट कर लिया जायेगा। पहले किसी भी एग्जाम के लिए लाखों प्रार्थियों द्वारा बार–बार फार्म भरा जाता था और बार–बार एग्जाम देने के लिए ट्रेनें, बसिज और अपने–अपने वाहनों से परीक्षा देने के लिए दूर–दूर तक जाना पड़ता था। अब हमारी सरकार ने इन सब समस्याओं का हल निकाल दिया है। अब ''वन टाइम रजिस्ट्रेशन'' पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को लाभ दिया जायेगा। अब मैं इस महान सदन में रोजगार के बारे में अंतिम विषय पर बात करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार–बार कहा जाता है कि प्रदेश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। कई वक्ताओं ने इस विषय पर अपनी अपनी बात रखी। अध्यक्ष महोदय, सी.एम.आई.ई. (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) नाम की एक प्राइवेट संस्था है। वह हर सप्ताह बेरोजगारी और रोजगार से जुड़े हुए आंकड़े जारी करती है। उस संस्था ने हमारे प्रदेश के 42 परसैंट से 43 परसैंट तक बेरोजगारी के आंकड़े दर्शाये हैं। मेरा यह कहना है कि इन आंकड़ों में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है, जिसे माना जा सके क्योंकि यह एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है वह अपने हिसाब से सर्वे करती रहती है और अपनी रिपोर्ट छापती रहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि National Statistical Organization द्वारा ऑथेंटिक सर्वे किया जाता है, उसका ही सर्वेक्षण माना जाता है। यह संस्था सैंट्रल गवर्नमैंट की है। यह संस्था सैंट्रल गवर्नमैंट का ही सर्वे करती है। इस सर्वे के अनुसार जनवरी से मार्च 2020 में एक रिपोर्ट आई थी। यह रिपोर्ट मार्च 2020 में छापी गई है इस रिपोर्ट के अनुसार हमारी एक साल की बेरोजगारी दर 7 परसैंट दिखाई गई है। इसके अलावा मैं हुड्डा साहब को एक और आंकड़े के बारे में बताना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में बेरोजगारी का आंकड़ा कितना परसैंट था? एक बार इस महान सदन को इस बारे में भी बताया जाये। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा जी को बताना चाहूंगा कि जो सी.एम. आई.ई. (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) संस्था का एम.डी. है, वह गुजरात का कोई मिस्टर शाह है और वह कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है। मैं यह बात इनको रिकॉर्ड के मुताबिक ही बता रहा हूं चाहे तो हुड्डा साहब इसको चैक करवा सकते हैं। वह कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है, उसने किस स्टेट की बेरोजगारी कितनी प्रतिशत दिखानी है, उसका अपना काम है वह करता रहे। हमारी सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेना चाहती है? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, वह प्राईवेट व्यक्ति है, सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : गीता जी, वह प्राईवेट व्यक्ति है, उसकी कौन सी authenticity है। सरकार उसकी बात को नहीं मान रही है तो फिर उस व्यक्ति पर किस बात एक्शन लिया जाये। उस व्यक्ति का हमारी सरकार पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है क्योंकि वह प्राईवेट संस्था है। हमारी सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। हमारी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को यह बात बता दी है। कांग्रेस पार्टी चाहे तो उस व्यक्ति का पुराना इतिहास उठाकर देख सकती है कि क्या वह व्यक्ति कभी कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी रहा है? मैं यह बात भी बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। (विघ्न) उस व्यक्ति ने जो मैथड तैयार किया है, उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वह शुरू में 2 परसैंट या 3 परसैंट बेरोजगारी का आंकड़ा दिखाता रहा और जैसे ही देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वह व्यक्ति कभी तो 28 परसैंट बेरोजगारी आंकड़ा दिखा देता है और कभी 34 परसैंट का आंकड़ा दिखा देता है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गुजरात प्रदेश में वह व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है तो उस व्यक्ति को

गुजरात प्रदेश में बेरोजगारी आंकड़ा हाईएस्ट दिखाना चाहिए। वह हरियाणा प्रदेश में क्यों बेरोजगारी आंकड़ा हाईएस्ट दिखा रहा है? (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं हुड्डा साहब को अगला आंकड़ा देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। आजकल हमने एक नया प्रोजैक्ट शुरू किया हुआ है और वो प्रोजैक्ट है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र में संयोग से इस समय 58 लाख परिवार रजिस्टर हो चुके हैं जिनमें कुल 2 करोड़ लोग हैं। अभी इसमें 15 परसैंट परिवार रजिस्टर होने बाकी हैं। हम उनको भी धीरे–धीरे रजिस्टर करने का काम करेंगे। इन दो करोड़ लोगों में से 18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोग हैं उन सभी का ब्यौरा कि कौन क्या करता है खेती करता है, दुकान करता है, नौकरी करता है, सरकारी सेवा में है या प्राईवेट सैक्टर में सर्विस करता है हमारे पास सभी का आंकड़ा है। हाउस वाईफ का अलग आंकड़ा है। उसके अंदर अपने आपको जिन्होंने स्वयं बेरोजगार डिक्लेयर किया है उनकी संख्या 6 लाख है। जिन्होंने स्वयं अपने आपको बेरोजगार डिक्लेयर किया है हमारे पास उसके बारे में लिखित जानकारी है। उसको हमने बेरोजगार डिक्लेयर नहीं किया है। अगर कोई खेती वाला है और वह अपने आपको स्वयं बेरोजगार कहता है तो उसके बाद ही सरकार उसको बेरोजगार मान सकती है अगर वह अपने आपको बेरोजगार नहीं कहता तो सरकार उसको कैसे बेरोजगार मान सकती है। अगर विपक्ष के साथ खेती करने वाले को, दुकानदार को और दूसरे छोटे–मोटे काम करने वालों को भी बेरोजगारों की श्रेणी में जोडेंगे उस स्थिति में तो बहुत संख्या बढ़ जायेगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिकवैस्ट है कि वे प्रदेश के सभी जिलों की एम्प्लॉयमैंट एक्सचेंजिज से अनइम्प्लॉयड का डाटा मंगवा लें। मेरी जानकारी के मुताबिक एक–एक डिस्ट्रिक्ट में 11–11 लाख बेरोजगार मिल जायेंगे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं मैं उनको उस आंकड़े के बारे में भी बता देता हूं। आज से बीस साल पहले अनइम्प्लॉयमैंट का जो आंकड़ा लिखा जाता था वह आज तक भी वैसे का वैसे है। वहां पर सिस्टम का यह दोष है कि वहां पर जो एक बार लिखा गया उसको कभी काटा नहीं जाता। वहां पर जो अपने आपको अनइम्प्लॉयड लिखवा गया वह सदा के लिए अनइम्प्लॉयड हो गया। वहां पर यह व्यवस्था पिछले लगभग 18–20 साल से चल रही है। हमने अब यह शुरू किया है कि हमने परिवार पहचान पत्र में यह

पूछना शुरू कर दिया, उसके बाद उसका वैरीफिकेशन करवायेंगे। उसके हमने जितने 10+2, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को कहा कि वे अपने आपको सक्षम युवा में रजिस्टर करवायें। उनको कैटेगरी के हिसाब से क्रमशः 1500/– रूपये और 3000/– रूपये बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। साथ में उनको 100 घंटे का काम दिया जायेगा। प्रति घंटे के हिसाब से उसका पैसा अलग से दिया जायेगा। एक पोस्ट ग्रेजुएट को 9000 रूपये 100 घंटे का आज हमारी सरकार दे रही है। इसमें भी कुल मिलाकर के सवा लाख लोग ही हैं। इससे ज्यादा इसमें भी नहीं आये। हम लोगों को ओपनली कहते हैं। वे आयें तो सही। हम तो पोस्ट ग्रेजुएट को काम देकर 9000 रूपये उसकी जेब में डाल रहे हैं ताकि वह अपना जरूरी खर्च कर ले और अपने आपको आगे बढ़ा ले। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) इसी प्रकार से डोमीसाईल का विषय श्री बलराज कुण्डु जी ने उठाया था। इस विषय के बारे में मैंने बता दिया है। अध्यक्ष जी, विषय तो मेरे पास और भी बहुत से बचे हैं लेकिन उन सभी पर अभी इस समय चर्चा किया जाना सम्भव नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी ही चर्चा करूंगा और कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगा कि विपक्ष के माननीय साथियों को तनाव में नहीं रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि खुद की फिक्र अक्सर तनाव देती है, दूसरों की फिक्र करके देखिए लगाव देती है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक छोटी सी अमैंडमैंट है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक गलती ध्यान में आई है और उस गलती को हमारे माननीय सदस्य श्री वरूण चौधरी जी द्वारा प्वायंट आउट किया गया है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। श्री वरूण चौधरी जी ने यह बताया है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा नम्बर 153 में यह लिखा गया है कि पुलिस के लिए हम जो गाड़िया खरीद रहे हैं वो 600 गाड़ियां खरीदने का आर्डर दे दिया गया है जबकि इसमें सच्चाई यह है कि वे गाड़िया खरीद ली गई हैं इसलिए इसमें इतना संशोधन करके हम इसको इस ढंग से पढ़ेगे कि पैरा नम्बर 153 – मेरी सरकार ने इस परियोजना हेतु पुलिस विभाग के लिए 630 वाहनों को खरीदने का कार्य पूर्ण कर लिया है। इस प्रकार से यह लाईन इसमें एड कर ली जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, प्रश्न है–

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाये –

> "कि इस सत्र में इक्ट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 05 मार्च, 2021 को दोपहर 02.00 बजे सदन में देने की कृपा की है।"।"

(प्रस्ताव पारित हुआ।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2021 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*19.30 बजे

(तत्पश्चात् सभा बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2021 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)